www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

ज़ख्म हैं कि भरने का नाम नहीं लेते

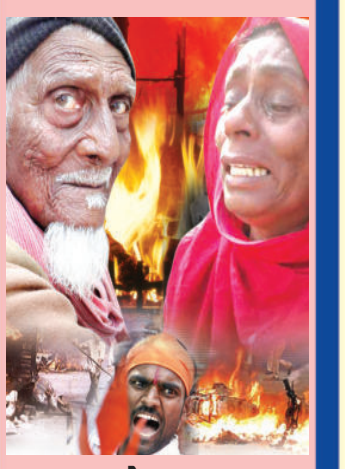

पेज-5

अन्ना और रामदेव वी पी सिंह से सीख लें

पेज-6

अफ़ीम से महकते खेत

पेज-7

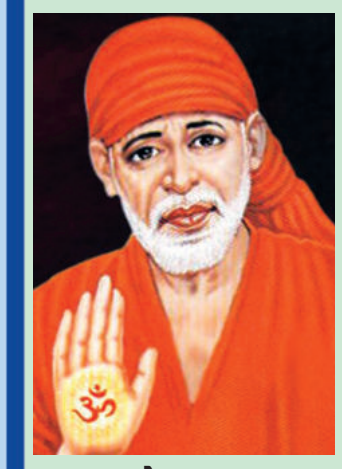

साई की महिमा

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 20 जून-26 जून 2011 | मूल्य 5 रुपये

भ्रष्टाचार और काले धन के ख़िलाफ़ आंदोलन में

बाबा रामदेव चूक गए

सभी फोटो-*सुनील मल्होत्रा*

मनीष कुमार

राजनीति भी अजीबोग़रीब खेल है, इसलिए इसे गेम ऑफ इंपोसिबल कहा गया है. यह ऐसा खेल है, जिसमें बड़े-बड़े खिलाड़ी को धराशायी होने में वक़्त नहीं लगता है, छोटे खिलाड़ी बाज़ी मार ले जाते हैं और कभी-कभी सबसे अनुभवी खिलाड़ी भी किसी नौसिखिए की तरह खेल जाता है. यह किसने सोचा था कि बाबा रामदेव के आंदोलन का ऐसा अंत होगा. यह किसने सोचा था कि मनमोहन सिंह जैसे शांत चित्त वाले लोग रात के एक बजे सो रही महिलाओं और बच्चों पर लाठियां बरसाने और अहिंसक आंदोलन पर अश्रु गैस के गोले दागने का फ़रमान जारी कर देंगे. बाबा के आंदोलन का ऐसा हश्र क्यों हुआ और सरकार ने इस आंदोलन को शक्ति से कुचलने का फ़ैसला क्यों लिया? ग़लतियां दोनों तरफ़ से हुईं. सरकार ने तो ग़लत किया ही, लेकिन बाबा रामदेव से भी चूक हो गई. बाबा रामदेव जिस स्थिति में हैं, उसके लिए वह स्वयं ज़िम्मेदार हैं.

रामदेव का घोषित अनशन बहुत सही मुद्दों पर था और लोग भी विश्वास लेकर आए थे, पर पुलिस की ओर से जो कार्रवाई हुई, वह निंदनीय है. लेकिन दोनों तरफ़ से कुछ ज़्यादा होशियारी बरतने की वजह से अविश्वास का वातावरण बना. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा रामदेव ने सरकार के साथ समझौता किया और उस समझौते को लोगों से छिपाया. दूसरी तरफ़ सरकार चाहती थी कि रामदेव आरएसएस की राजनीति न करके उसकी बनाई हुई गाइड लाइन पर आंदोलन करें, बाबा रामदेव के आंदोलन से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो. जब केंद्र के एक मंत्री ने बाबा रामदेव से यह कहा कि आप एक सद्भावना पूर्ण संदेश सरकार को दीजिए, ताकि आप में और सरकार में संवाद क़ायम हो. रामदेव इसके लिए मान गए. उन्होंने यह बयान दिया कि प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को लोकपाल बिल के दायरे में नहीं लाना चाहिए. इसी बयान से सरकार को यह भरोसा हुआ कि अब रामदेव कांग्रेस के फ़ायदे के लिए अपनी बात कहेंगे. इसी सद्भावना पूर्ण माहौल में कलैजियर्स होटल में दोनों के बीच पत्रों का आदान-प्रदान हुआ, लेकिन बाबा के जो सलाहकार थे, वही आरएसएस के भी सलाहकार हैं. उनकी रणनीति थी कि जैसे ही सरकार बाबा की सारी बातें माने, वैसे ही रामदेव यह घोषणा करेंगे कि उन मांगों से जुड़े हुए सवालों पर अब अध्यादेश लाया जाए. इस बात की जानकारी बाबा के ही किसी आदमी ने उस मंत्री को दे दी, जो मुख्य मध्यस्थ था. वह मंत्री तत्काल प्रधानमंत्री के पास गया और आनन-फानन में यह फ़ैसला ले लिया गया कि बाबा रामदेव के साथ अब वार्ता नहीं करनी है. न केवल वार्ता नहीं की जानी है, बल्कि रामदेव की विश्वसनीयता देश के लोगों के सामने भी लानी है. इसका ज़िम्मा कपिल सिब्बल को सौंपा गया. इस समय यह फ़ैसला नहीं लिया गया था कि रामलीला मैदान से लोगों को खदेड़ा जाएगा. सुबोध कांत सहाय ने यह घोषणा की कि सरकार ने बाबा की मांगें मान ली हैं और वह चिट्ठी भेज रहे हैं. पर आईबी ने सूचना दी कि चेन्नई में बैठे आरएसएस के एक नेता ने रामदेव को यह सलाह दी है कि वह चिट्ठी पाने के बाद यह घोषणा कर दें कि जब तक अध्यादेश नहीं आएगा, तब तक वह अनशन समाप्त नहीं करेंगे. आरएसएस के इस नेता का पिछले 8 महीनों से फोन टेप हो रहा है, जिससे यह बात पता चली. फिर प्रधानमंत्री के स्तर पर यह फ़ैसला लिया गया कि रामलीला मैदान रात में खाली करा लिया जाए.

अगर बाबा रामदेव ठग हैं तो कुछ सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए. अगर बाबा रामदेव ठग हैं तो कांग्रेस के नेता एवं मंत्री उनके शिविर में क्या करने जाते थे, कांग्रेस शासित राज्यों में उन्हें शिविर लगाने की अनुमति क्यों मिलती है, दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे मिलने मंत्रीगण क्यों गए थे, उनके साथ कपिल सिब्बल होटल के कमरे में क्यों डील कर रहे थे, सरकार ने उन्हें गिरफ़्तार क्यों नहीं किया और हवाई जहाज से हरिद्वार क्यों छोड़ा गया, पतंजलि फूड पार्क के लिए कांग्रेस की सरकार ने पैसे क्यों दिए और राहुल गांधी उनसे क्यों मिलते हैं?

बाबा रामदेव की कोशिशों से तैयार जन समर्थन का फ़ायदा उठाने के लिए एक ख़ास रणनीति के तहत अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में हुए पुलिसिया दमन के ख़िलाफ़ 8 जून को जंतर-मंतर पर अनशन करने का फ़ैसला लिया, लेकिन आख़िरी समय पर जगह बदल कर राजघाट कर दिया. अन्ना को लोग गांधीवादी बता रहे हैं, लेकिन गांधी के आंदोलनों की पहली ख़ासियत ही अन्ना भूल गए. गांधी का आंदोलन तो क़ानून तोड़ने के लिए होता था. अगर जंतर-मंतर पर सरकार ने अनशन करने से रोक दिया था तो अन्ना और उनके सहयोगियों को विनती पूर्वक गिरफ़्तारियां देनी थीं.

जब कोई ग़ैर राजनीतिक व्यक्ति राजनीति करने लग जाता है तो ग़लतियां होने का ख़तरा बढ़ जाता है. बाबा रामदेव वैसे तो योग गुरु हैं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं. उनकी सबसे बड़ी भूल यही है उन्होंने राजनीति शुरू कर दी. बाबा रामदेव से कई ग़लतियां हो गईं. बाबा रामदेव को राजनीतिक दलों के साथ डील करना नहीं आया. किस राजनीतिक दल से कितना सटना है, किससे कितना दूर जाना है, बाबा इसका सही आकलन नहीं कर सके. बाबा ने आंदोलन के कुछ दिनों पहले से ऐसे संकेत दिए, जिनसे यह लग रहा था कि वह आंदोलन भी करना चाहते हैं और कांग्रेस और भाजपा दोनों को ख़ुश भी रखना चाहते हैं. वह संघ के सलाहकारों की बात भी सुन रहे थे और कांग्रेस के नेताओं के साथ बात भी कर रहे थे. बाबा राजनीतिक दोस्त और दुश्मन में फ़र्क़ नहीं कर पाए. यही वजह है कि वह इस बात का आकलन नहीं कर पाए कि साध्वी ऋतंभरा को मंच पर बैठाना और उनसे भाषण दिलवाना उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है. बाबा रामदेव को भनक भी नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाकर उनके पूरे आंदोलन की हवा निकाल देगी. बाबा कांग्रेस पार्टी के मीडिया मैनेजमेंट की ताक़त को नहीं पहचान सके. यह बाबा की राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ नज़दीक दिखना बाबा रामदेव के लिए महंगा साबित हुआ. मीडिया बाबा के ख़िलाफ़ हो गया. वैसे संघ के पदाधिकारी बताते हैं कि संघ का बाबा रामदेव पर कोई नियंत्रण नहीं है. वह अपनी ही मर्जी से सारा कुछ करते हैं. बाबा रामदेव उनकी एक बात भी नहीं सुनते हैं.

लोगों को लगता है कि रामदेव दिल के साफ़ हैं, जो मन में आता है, वह बोल देते हैं, लेकिन असलियत यह है कि बाबा रामदेव अविश्वासी हैं. वह किसी पर विश्वास नहीं करते हैं. वह सिर्फ़ अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेते हैं. समझने वाली बात यह है कि जब फरवरी में रामलीला मैदान

(शेष पृष्ठ 2 पर)

पीएमओ द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक के किसी भी प्रोजेक्ट की देखरेख सिर्फ़ पीएमओ द्वारा की जाएगी.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

तीव्र सुधार

दीदी के कोलकाता जाने के बाद से रेल मंत्रालय का कार्यभार पीएमओ संभाल रहा है, कम से कम मंत्रिमंडल में नए बदलाव होने तक. इससे मनमोहन सिंह को उन सुधारों को लागू करने का अवसर मिल गया है, जिन्हें दीदी ने रोक रखा था. अभी हाल में मनमोहन सिंह ने रेलवे के उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक की. सूत्रों के मुताबिक, पीएमओ इस मंत्रालय पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है. पीएमओ द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक के किसी भी प्रोजेक्ट की देखरेख सिर्फ पीएमओ द्वारा की जाएगी. इससे साफ हो गया है कि 77 हजार करोड़ रुपये के फ्रेट कॉरिडोर सहित अन्य भारी– भरकम प्रोजेक्ट्स की निगरानी पीएमओ ही करेगा. यह भी संकेत दिए जा रहे हैं कि भले ही किसी अन्य को इस मंत्रालय का चार्ज दे दिया जाए, लेकिन पीएमओ अपनी पकड़ ढीली करने वाला नहीं है.

अफ़ग़ानी बाबू भारत आएंगे

इस कॉलम में पहले भी बताया गया है कि भारी–भरकम वेतन–भत्ते दिए जाने के प्रस्ताव के बाद भी देसी बाबू काबुल जाकर अफगानी बाबुओं को प्रशिक्षण देने में रुचि नहीं दिखा रहे थे, जबकि भारत और अफगानिस्तान के बीच इस संबंध में एक एमओयू भी है. बहरहाल, अधिकारियों को काबुल भेज पाने में असफल सरकार ने अब अफगानी लोकसेवकों को दिल्ली बुलाकर ही प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम बनाया है. उन्हें विभिन्न मंत्रालयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, अफगानी बाबू जल्द ही दिल्ली आएंगे.

संकटकालीन प्रशिक्षण

कम ही लोगों को मालूम होगा कि नए कैबिनेट सचिव अजीत सेठ, जो के एम चंद्रशेखर से प्रभार लेंगे, भी दिल्ली एयरपोर्ट पर बाबा रामदेव से मिलने गए थे, लेकिन बाबू लोग मीडिया के सामने खुद को लो प्रोफाइल बनाकर रखते हैं, इसलिए वह मीडिया की नज़र से बच गए. इसलिए भी, क्योंकि मीडिया की नज़र तो चार मंत्रियों पर टिकी हुई थी. सेठ के वहां जाने के पीछे यह विचार था कि योग गुरु द्वारा सरकार के लिए जो राजनीतिक संकट खड़ा किया गया था, उससे निबटने का गुर वह सीखना शुरू कर दें, ताकि अपने नए रोल को निभाने में उन्हें परेशानी न हो. बहरहाल सेठ की नियुक्ति को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्हें वरिष्ठता के आधार पर कैबिनेट सचिव बनाया गया है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है. कम से कम बिहार राजस्व बोर्ड के चेयरमैन एस पी केशवन उनसे भी वरिष्ठ हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

किंगरा होंगे सीएमडी

1980 बैच के आईएफएस अधिकारी हरदीप सिंह किंगरा का नाम नेशनल शिड्यूल कास्ट शिड्यूल ट्राइब फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीएमडी पद के लिए चर्चा में है. यह निगम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है. वह अमांता चरण पाढी की जगह जा सकते हैं.

अतुल पहुंचे पीईएसबी

अतुल चतुर्वेदी अभी कैबिनेट सचिवालय में प्रधान सलाहकार की भूमिका में हैं. उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत आने वाले पब्लिक इंटरप्राइजेज सेलेक्शन बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है.

लोहानी बने जेएस

1980 बैच के अधिकारी एस के लोहानी को राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव बनाकर भेजा जा सकता है. वह बी बालगोपाल की जगह लेंगे.

माथुर गृह मंत्रालय में

1992 बैच के आईटीएस अधिकारी दिनेश माथुर को गृह मंत्रालय में निदेशक पद पर नियुक्त किए जाने की संभावना है. वह 1990 बैच की आईएएस अधिकारी ज्योति कलश की जगह लेंगे.

दीपक पहुंचे संस्कृति मंत्रालय

1995 बैच के अधिकारी दीपक आशीष कौल को संस्कृति मंत्रालय में निदेशक पद पर नियुक्त किए जाने की संभावना है. इस मंत्रालय में यह पद नवसृजित है.

बाबा रामदेव चूक गए

पृष्ठ एक का शेष

में बाबा रामदेव ने रैली की, तब उस रैली में अन्ना हजारे, राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, गोविंदाचार्य, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल और विश्वबंधु गुप्ता आदि कई दिग्गज थे. रामलीला मैदान में इस बार इनमें से कोई नज़र नहीं आया. ये लोग कहां ग़ायब हो गए. बाबा और इनके बीच ऐसी क्या बात हुई, जिसकी वजह से इन लोगों ने बाबा के साथ आने से इंकार कर दिया. बाबा अपने आंदोलन और रैलियों में लोगों को बुलाते तो हैं, लेकिन उनसे कोई राय नहीं लेते. अगर कोई राय देता भी है तो उसे वह नहीं मानते हैं. आंदोलन की प्लानिंग बाबा ने अपनी बुद्धि और विवेक से की. एक उदाहरण देता हूं. रामलीला मैदान में साध्वी ऋतंभरा के बगल में बैठे थे शिया धर्मगुरु और इस्लामिक स्कॉलर कल्बे रुशैद रिज़वी. उन्हें पता ही नहीं था कि साध्वी ऋतंभरा भी आने वाली हैं. उन्हें यह भी पता नहीं था कि और कौन–कौन लोग आने वाले हैं. जबकि वह पिछले एक साल के दौरान बाबा रामदेव के भारत स्वाभिमान आंदोलन के प्रचार के लिए देश के कई शहरों में गए. उन्होंने बाबा रामदेव के आंदोलन को फैलाया, लेकिन जब रामलीला मैदान में अनशन की योजना बनी, तब उनसे भी कोई सलाह–मशविरा नहीं किया गया. उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि सरकार के साथ बैकडोर बातचीत हो रही है. इसका मतलब यह है कि बाबा रामदेव किसी से राय लेने में विश्वास नहीं रखते हैं और न किसी पर भरोसा करते हैं. इसी कमी की वजह से बाबा कांग्रेस पार्टी के जाल में फंस गए.

बाबा के आंदोलन को सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब कपिल सिब्बल ने उस चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया, जिसमें बाबा रामदेव ने यह आश्वासन दिया था कि वह दो–तीन दिनों में अनशन तोड़ देंगे. किसी भी आंदोलन से पहले और आंदोलन के दौरान सरकार और आंदोलनकारियों में बातचीत होना कोई नई बात नहीं है. ऐसा हर आंदोलन में होता है, होना भी चाहिए. अगर बातचीत ही बंद हो जाएगी तो फिर निगोशिएशन कैसे होगा, लेकिन इस बातचीत को सार्वजनिक करना उचित नहीं माना जा सकता है. कपिल सिब्बल ने बालकृष्ण के पत्र को दिखाकर ग़लती की. लेकिन बाबा रामदेव की ग़लती यह है कि उन्हें स्वयं सरकार से इस तरह बातचीत नहीं करनी चाहिए. बाबा ने अगर किसी दूसरे व्यक्ति या ग्रुप को सरकार से बातचीत करने की ज़िम्मेदारी दी होती तो आज स्थिति कुछ और ही होती. वैसे कांग्रेस पार्टी अब बालकृष्ण को नेपाली नागरिक बताकर बाबा से हिसाब चुका रही है. चौथी दुनिया कई महीने पहले ही इस ख़बर को छाप चुका है, यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल को यह तो बताना ही पड़ेगा कि क्या भारत सरकार एक नेपाली नागरिक से समझौता कर रही थी? मीडिया के सामने जो पत्र उन्होंने दिखाया, क्या वह किसी नेपाली नागरिक का था?

बाबा ने एक और ग़लती रामलीला मैदान में की. जिस तरह वह पुलिस के डर से भागे और महिलाओं का वस्त्र धारण कर पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, उससे बाबा रामदेव के बारे में लोगों में संदेह पैदा हो गया है. बाबा को पुलिस के सामने डटकर भाषण देना था और आराम से ख़ुद को गिरफ़्तार करा लेना था. गांधी जी के सत्याग्रह को याद करें तो उसमें यही होता था. गांधी जी क़ानून तोड़ते थे, पुलिस आती थी, उन्हें गिरफ़्तार करती थी. गांधी जी कहते थे, पूरा देश ही जब जेल है तो जेल के अंदर क्या और बाहर क्या! जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाता था, लेकिन बाबा रामदेव ने ऐसा कुछ नहीं किया. उल्टा जान बचाने के लिए वह एक घंटे से ज़्यादा छिपे रहे. यह इस बात को साबित करता है कि बाबा सचमुच अराजनीतिक व्यक्ति हैं. राजनीतिक व्यक्ति तो इस बात के लिए लालायित रहता है कि लोग उस पर हो रही पुलिसिया कार्रवाई को देखें और उसे गिरफ़्तार किया जाए.

बाबा रामदेव से चूक हुई, लेकिन कांग्रेस की भी ग़लतियों की लिस्ट लंबी है. अब कांग्रेस पार्टी बाबा रामदेव को ठग बता रही है. अगर बाबा रामदेव ठग हैं तो कुछ सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए. अगर बाबा रामदेव ठग हैं तो कांग्रेस के नेता एवं मंत्री उनके शिविर में क्या करने जाते थे, बाबा रामदेव अगर ठग हैं तो कांग्रेस शासित राज्यों में उन्हें शिविर लगाने की अनुमति क्यों मिलती है, अगर बाबा ठग हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे मिलने मंत्रीगण क्यों गए थे, अगर बाबा ठग हैं तो उनके साथ कपिल सिब्बल होटल के कमरे में क्यों डील कर रहे थे, अगर बाबा ठग हैं तो सरकार ने उन्हें गिरफ़्तार क्यों नहीं किया और हवाई जहाज से हरिद्वार क्यों छोड़ा गया, अगर बाबा ठग हैं तो पतंजलि फूड पार्क के लिए कांग्रेस की सरकार ने पैसे क्यों दिए और बाबा रामदेव अगर ठग हैं तो राहुल गांधी उनसे क्यों मिलते हैं? असलियत तो यह है कि इस आंदोलन से पहले तक बाबा रामदेव के कांग्रेस के कई नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं. जब बाबा रामदेव ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बाबा को प्रोत्साहन भी दिया. कांग्रेस पार्टी की योजना यह थी कि अगर बाबा चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी के वोट काटेंगे, लेकिन जबसे बाबा ने पार्टी बनाने से मना किया और वह संघ परिवार के साथ खड़े नज़र आने लगे, तबसे कांग्रेस और रामदेव में युद्ध शुरू हो गया.

सरकार ने तो हद ही कर दी. रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार और काले धन के ख़िलाफ़ आंदोलन चल रहा था. पुलिस डंडा चला रही थी. उसी दौरान मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री की करतूत उजागर हो रही थी. ए राजा से पहले यूपीए सरकार के टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन के कारनामे सामने आए. पिछले एक साल से लगातार एक के बाद एक घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है. भ्रष्टाचार को लेकर लोगों की नाराज़गी चरम पर है, लेकिन केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कोई कड़े क़दम उठाने के बजाय बाबा रामदेव को डराने में लग गई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी को बाबा रामदेव के पीछे लगा दिया गया है. बाबा के पास इतने पैसे कहां से आए, बाबा ने विदेश में कितना पैसा निवेश किया, बाबा ने कहां–कहां क़ानून तोड़ा, बाबा का पैसा और कहां–कहां लगा है जैसे कई सवाल हैं, जिन्हें सरकारी एजेंसियां खंगाल रही हैं. देश के क़ानून की स्थिति यह है कि बाबा रामदेव क्या, कोई भी व्यक्ति, जिसके पास इतना सारा धन है, वह क़ानून की नज़र में कहीं न कहीं गुनाहगार बन ही जाता है. सरकार क़ानून की दृष्टि से सही हो सकती है, लेकिन यह पहल भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की पहल नहीं हो सकती है. सरकार अगर बाबा रामदेव के खातों की जांच कर रही है तो इसके साथ ही देश के बड़े–बड़े उद्योगपतियों के ग़ैर क़ानूनी धन के बारे में भी जांच होनी चाहिए. ऐसा क्यों है कि 2–जी स्पेक्ट्रम मामले में छोटी–छोटी मछलियां जेल के अंदर हैं, जबकि जिन कंपनियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उसके मालिक टाटा और अंबानी को क्लीन चिट दे दी गई. इस सवाल का जवाब भी सरकार को देना चाहिए. रात के अंधेरे में हुई पुलिसिया कार्रवाई की जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है. सरकार के एक फ़ैसले ने उसे गुनाहगार बना दिया.

प्रजातंत्र में किसी भी आंदोलन या राजनीतिक गतिविधि के लिए जनता का समर्थन ज़रूरी होता है. बाबा रामदेव के साथ जनता का अपार समर्थन है. जिस तरह भीड़ इकट्ठा करने की क्षमता उनमें है, वह देश के किसी दूसरे नेता में नहीं है. बाबा रामदेव के आंदोलन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अन्ना हजारे को मिला है. अन्ना के पास एजेंडा तो है, लेकिन समर्थन का अभाव है. तीन महीने पहले जब बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान में रैली की थी तो अन्ना मंच पर बाबा रामदेव के पीछे बैठे थे. रैली में उमड़ी भीड़ देखकर उन्होंने पास में बैठे विश्वबंधु गुप्ता से कहा, मैं भी अब दिल्ली में आंदोलन करना चाहता हूं. विश्वबंधु गुप्ता ने पूछा कि लोगों को कहां से लाएंगे? तो अन्ना ने रामलीला मैदान में मौजूद भीड़ को दिखाकर कहा कि जब सब लोग साथ हैं तो लोग स्वयं आ जाएंगे. अन्ना पहले भी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन उनके आंदोलन ने कभी देशव्यापी जनांदोलन का रूप नहीं लिया. वह महाराष्ट्र तक ही सीमित थे. आंदोलन से पहले तक अन्ना का नाम दिल्ली के लोगों के लिए नया था. दिल्ली में कोई अब सफ़ेद टोपी पहने नज़र नहीं आता है, इसलिए दिल्ली के एलीट वर्ग के लिए अन्ना एक अनोखा व्यक्तित्व थे. अन्ना के आंदोलन में ग़रीब नहीं हैं, अल्पसंख्यक नहीं हैं, दलित नहीं हैं, मज़दूर और किसान नहीं हैं, लेकिन मीडिया, मोबाइल फोन, एसएमएस और इंटरनेट के सटीक इस्तेमाल ने अन्ना के लिए अलादीन के चिराग़ का काम किया. अन्ना के आंदोलन का दायरा शहरी है. टेक्नालॉजी के इस्तेमाल से दिल्ली का उच्च और उच्च–मध्यम वर्ग आंदोलित हो गया.

बाबा रामदेव का आंदोलन अचानक ख़त्म होने से अन्ना के सहयोगियों को लगा कि यह एक अच्छा मौक़ा है, जब भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बने जनमत को अन्ना की तरफ़ मोड़ा जाए. इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले दो सालों से भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लोगों को जागरूक करने का काम बाबा रामदेव ने किया. लोगों में नाराज़गी है. लोग भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ देश में आंदोलन चाहते हैं. बाबा रामदेव की कोशिशों से तैयार जन समर्थन का फ़ायदा उठाने के लिए एक ख़ास रणनीति के तहत अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में हुए पुलिसिया दमन के ख़िलाफ़ 8 जून को जंतर–मंतर पर अनशन करने का फ़ैसला लिया, लेकिन आख़िरी समय पर जगह बदल कर राजघाट कर दिया. अन्ना हजारे को लोग गांधीवादी बता रहे हैं, लेकिन एक बात यह समझ में नहीं आई कि उन्होंने जंतर–मंतर की जगह राजघाट को क्यों चुना. गांधी के आंदोलनों की पहली ख़ासियत ही अन्ना भूल गए. गांधी का आंदोलन तो क़ानून को तोड़ने के लिए होता था. अगर अन्ना गांधीवादी आंदोलन करना चाहते हैं तो गांधी के इस मूलमंत्र को उन्हें याद रखना होगा. अगर जंतर–मंतर पर सरकार ने अनशन करने से रोक दिया था तो अन्ना और उनके सहयोगियों को विनती पूर्वक गिरफ़्तारियां देनी थीं. जंतर–मंतर की जगह राजघाट में अनशन करना आंदोलन के भविष्य पर सवाल खड़ा करता है. साफ है कि अन्ना का आंदोलन भी सरकार के दबाव का शिकार हो रहा है. अन्ना ने 16 जून से जंतर–मंतर पर आमरण अनशन का ऐलान किया है. क्या यह आमरण अनशन जंतर–मंतर पर होगा, क्या लोकपाल बनाने वाली कमेटी की बैठकों का लाइव टेलीकास्ट होगा, क्या लोकपाल को प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जजों, वरिष्ठ अधिकारियों और सांसदों के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही का अधिकार होगा और क्या सरकार फिर से आंदोलनकारियों के साथ डील करेगी आदि जैसे कई सवाल हैं, जिनका उत्तर अन्ना के आमरण अनशन के दौरान मिलेगा.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 15
दिल्ली, 20 जून–26 जून 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रबंध संपादक (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)
डॉ. सुनील कौशिक

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9871194800
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4+4+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

अन्ना शुरू से अपने आंदोलन के ग़ैर राजनैतिक होने का दावा कहते रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन की तैयारी के दिनों का विश्लेषण किया जाए तो इस दावे की सच्चाई का पता चलता है.

अन्ना का आंदोलन

कुछ सवालों के जवाब ज़रूरी हैं

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

शशिशेखर

राजनीति से आप पीछा छुड़ाना भी चाहें तो राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी. भारतीय लोकतंत्र में भी राजनीति और आम आदमी के बीच कुछ ऐसा ही संबंध है, लेकिन लोकपाल बिल पर अन्ना हजारे का आंदोलन राजनीति और आम आदमी के बीच इस संबंध को मानने से इंकार कर रहा है. अन्ना अपने आंदोलन में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को घुसने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने के लिए उन्हीं राजनीतिक लोगों के साथ बैठते भी हैं. इस सच्चाई को, कि लोकपाल बिल आख़िरकार संसद ही बनाएगी, क्या अन्ना और उनकी टीम नहीं समझती?

अन्ना का आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? टीम अन्ना अपने बयानों में, अपनी बातों में और अपने विचारों में कितनी समानता रखती है? अन्ना रामदेव के साथ रामलीला मैदान में बैठने की बात करते हैं तो स्वामी अग्निवेश इसका विरोध करते हैं. फिर अगले ही दिन अन्ना रामलीला मैदान में रामदेव के सत्याग्रह पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में 8 जून को जंतर–मंतर पर एक दिन के अनशन की घोषणा करते हैं. यह जानते हुए भी कि जंतर–मंतर सहित सेंट्रल दिल्ली में धारा 144 लागू की जा चुकी है. फिर अनुमति न मिलने पर राजघाट पर अनशन करते हैं. यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कोई भी जनांदोलन सरकार और पुलिस की इजाज़त का मोहताज नहीं होता. जब अन्ना को पता था कि धारा 144 लागू है तो फिर उन्होंने क्यों जंतर–मंतर पर अनशन करने की बात कही और जब कर ही दी थी तो क्यों जगह बदल कर राजघाट कर दिया. ख़ैर, राजघाट पर अनशन हुआ.

लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हुईं, जिन पर सवाल उठाया जाना ज़रूरी है. मसलन, इस आंदोलन के स्वयंसेवक (वालंटियर) राजघाट पर अन्ना के मंच से भाकपा (माले) की कविता कृष्णन को ज़बरदस्ती उतार देते हैं, माइक बंद कर देते हैं. जबकि अन्ना टीम के ही एक सदस्य ने कविता को मंच पर आमंत्रित किया था, बाकायदा मंच से घोषणा करके. लेकिन एक मिनट के भीतर उसे मंच से उतार भी दिया जाता है, क्योंकि अन्ना के मंच पर नेता नहीं आ सकते. अहम सवाल यह है कि उसी मंच पर आइसा के लोगों को बुलवा कर उनसे गाना गवाया जाता है. आख़िर क्यों? क्या आइसा एक ग़ैर राजनीतिक संगठन है? इस आधार पर कल को अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के लोग अन्ना के मंच पर आना चाहें तो क्या अन्ना इसकी इजाज़त देंगे? अगर सीपीआई (माले) राजनीतिक है तो राजा बुंदेला को उस मंच से बोलने की इजाज़त कैसे दी गई? राजा बुंदेला बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और उनका अपना राजनीतिक एजेंडा भी है. आख़िर उस वक़्त अन्ना के स्वयंसेवकों ने बुंदेला को मंच से क्यों नहीं उतारा? क्या इसके पीछे कोई एजेंडा था या अन्ना और उनके स्वयंसेवकों को इस बात की जानकारी नहीं थी.

अन्ना शुरू से अपने आंदोलन के गैर राजनैतिक होने का दावा कहते रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन की तैयारी के दिनों का विश्लेषण किया जाए तो इस दावे की सच्चाई का पता चलता है. 30 जनवरी को जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की रैली हुई थी और जब उसके बाद जन लोकपाल बिल पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने की घोषणा की गई थी, तभी से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों (कांग्रेस सहित) से मिलना–जुलना और समर्थन मांगना शुरू कर दिया था. इंडिया अगेंस्ट करप्शन की ओर से इंडिया इस्लामिक सेंटर में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था. इसमें कांग्रेस को छोड़ कर लगभग सभी दलों के लोगों ने शिरकत की थी और मीडिया के बीच अपना समर्थन इस आंदोलन को देने की बात कही थी. ग़ौरतलब है कि उस मीटिंग में भाकपा (माले) की ओर से कविता कृष्णन भी मौजूद थीं. इसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोगों ने सभी पार्टी दफ्तरों में जाकर जन लोकपाल के मुद्दे पर नेताओं से मुलाक़ात की थी और उनका समर्थन भी मांगा था. लेकिन अन्ना के दिल्ली आते ही और उनका अनशन शुरू होते ही अचानक ऐसा क्या हो गया कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोगों को राजनीतिक दलों से रातोंरात नफरत हो गई.

बहरहाल, इस देश में कानून भले ही ज्वाइंट कमेटी ड्राफ्ट करे, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में क़ानून पास करने का अधिकार तो संसद को ही है. यह एक साधारण सी बात है, जिसे अन्ना टीम भी बख़ूबी जानती है. इस देश में एक भी ऐसा जनांदोलन याद नहीं आता, जो पूर्ण रूप से ग़ैर राजनीतिक रहा हो. चाहे वह आज़ादी की लड़ाई रही हो या आपातकाल का विरोध रहा हो. सवाल यह नहीं है कि आंदोलन किसने शुरू किया और जीत किसकी हुई, बल्कि सवाल यह है कि जिस मक़सद के लिए आंदोलन हो रहा है, उसे पूरा कैसे किया जाए, लेकिन शायद अन्ना टीम ऐसा नहीं सोचती. उसके लिए लक्ष्य हासिल करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन करते रहना भर है. उसके लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसके आंदोलन में कोई नेता न घुस पाए. शायद इन्हीं वजहों से ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी की कई बैठकों के बाद अन्ना टीम अपनी एक भी मांग मनवा पाने में असफल रही है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र

राजनीति का व्याकरण बदल रहा है

राजेश नामदेव

राज्य में इन दिनों शिव शक्ति–भीम शक्ति का शोर मचा हुआ है. इसके साथ ही एक और मुद्दा जुड़ गया है दादर स्टेशन के नामांतरण का. अब दादर स्टेशन का नाम चैत्य भूमि रखा जाए या डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर, इस पर कोई विवाद नहीं, लेकिन इसी बहाने राजनीतिक अस्त्र–शस्त्रों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है. सभी दादर स्टेशन के नाम परिवर्तन में अपनी भूमिका रेखांकित और दूसरे की ख़ारिज करने में लगे हैं. इस रेखांकित व ख़ारिज करने के संघर्ष में एक–दूसरे के कपड़े उतारने का प्रयास पूरे जोशो–खरोश से किया जा रहा है. इसके साथ ही यह भी दावा करने का प्रयास किया जा रहा है कि हम सबसे अधिक दलित हितैषी हैं. इस संघर्ष में शिव शक्ति–भीम शक्ति की ओर से शिवसेना के मुखिया बाला साहब ठाकरे, रिपब्लिकन पार्टी के रामदास आठवले ने कमान संभाल रखी है. वहीं राकांपा के अजीत पवार और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे हमलावर की भूमिका में नजर आ रहे हैं.

जब कांग्रेस–राकांपा में रामदास आठवले की पूछ कम हो गई तो उन्होंने पहले रिपब्लिकन पार्टी के अलग–अलग धड़ों को एक मंच पर लाने की भरसक कोशिश की, मगर उनका यह प्रयास रिपब्लिकन नेताओं के अहंकार के कारण नाकाम साबित हुआ. पांच साल तक मंत्री पद और दस साल तक सांसदी का सुख भोग चुके आठवले को पिछले लोकसभा चुनाव में शिरडी में मिली पराजय ने झकझोर कर रख दिया. उसके बाद से सत्ता से दूर रहने की कसक आठवले को बेचैन किए हुए थी. ऐसे में उन्होंने अपना राजनीतिक अस्तित्व बरकरार रखने के लिए नए साथी की तलाश शुरू की. पिछले जनवरी माह से आठवले ने भाजपा और शिवसेना से मेलजोल बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए. अप्रैल माह में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और आठवले के मिलन के साथ ही शिव शक्ति–भीम शक्ति की रूपरेखा बनकर उभरी और उसमें भाजपा को भी भागीदार बनाया गया. उसके बाद राज्य के हर जिले में शिव शक्ति–भीम शक्ति–भाजपा गठजोड़ का झंडा बुलंद किया जाने लगा. इन सभाओं की ख़ास बात यह थी कि इनमें मुख्य वक्ता रामदास आठवले ही रहे. इससे आठवले का उत्साह और बढ़ गया. नागपुर में बीते 2 जून को आयोजित शिवसेना–भाजपा–रिपाई सम्मेलन में आठवले ने घोषणा की कि शिव शक्ति–भीम शक्ति का यह गठजोड़ राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए है. इससे साफ हो जाता है कि सत्ता के बिना आठवले कितने बेचैन हैं. सम्मेलन में भाजपा के स्थानीय नेता तो शामिल हुए, पर प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, महासचिव देवेंद्र फडणवीस का न होना खटका. जबकि नागपुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का गृहनगर है. शिवसेना की ओर से पूर्व सांसद प्रकाश जाधव, शिवसेना प्रवक्ता एवं सांसद संजय राउत शामिल हुए. उन्होंने भी आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन का सफाया करने का दावा किया. राकांपा नेताओं को सपने में भी आशा नहीं थी कि आठवले इस तरह पलटी मारकर शिवसेना से गठजोड़ कर लेंगे. आठवले ने राकांपा का साथ ऐसे वक़्त में छोड़ा, जब वह कांग्रेस को पछाड़ने की रणनीति बना रही थी. पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यकों, दलितों और उत्तर भारतीय मतदाताओं को जोड़ने के सूत्र गढ़ने में लगी थी. ऐसे वक्त में आठवले द्वारा शिवसेना से हाथ मिलाने से राकांपा को करारा झटका लगा. लिहाज़ा जब शिवसेना के साथ मिलकर आठवले ने पूरे राज्य का दौरा करके शिव शक्ति–भीम शक्ति की अलख जगानी शुरू की तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इसकी काट के लिए दादर स्टेशन का नाम चैत्य भूमि रखने का राग छेड़ दिया. इससे इस राजनीतिक संघर्ष में नया मोड़ आ गया. हड़बड़ाए बाला साहब ठाकरे और आठवले ने पवार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया. सवाल किया कि एकाएक अजीत पवार को दलितों के हित की याद कैसे आ गई. जवाब में अजीत ने बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक योगदान को ही सवालों के घेरे में ला दिया. शिरडी की एक सभा में पवार ने पूछा कि बाला साहब ठाकरे ने कौन–कौन से सामाजिक काम किए हैं? उन्होंने स्कूल–कॉलेज और कारखाने खोलने के बजाय छत्रपति शिवाजी के नाम पर सिर्फ़ राजनीति की या अपने घर में बैठकर जय शिवाजी–जय भवानी के नारे लगाए. इस पर शिवसेना ने अजीत पवार की खिल्ली उड़ाई. पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने पवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राकांपा के शैक्षणिक संस्थान और शक्कर कारखाने भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं.

अजीत पवार ने दादर स्टेशन का नाम बदलने का जो राग छेड़ा है, उसके चलते अब सभी में यह होड़ शुरू हो गई है कि अंबेडकर की विचारधारा से कौन कितना सरोकार रखता है और दलितों के बारे में सोचता है. इसके साथ ही नाम परिवर्तन का श्रेय लेने की दौड़ भी शुरू हो गई है. शुरुआत की कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष माणिक राव ठाकरे ने. उन्होंने बीती 30 मई को राकांपा के स्थापना दिवस से पहले दलितों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर 60 सूत्रीय मांगपत्र जारी कर दिया. ठाकरे ने कहा कि बीते 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौक़े पर हमने डॉ. मुणगेकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दलितों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों की मांगों के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने को कहा था. उस समय राकांपा या अन्य किसी दल ने इस बारे में कोई क़दम नहीं उठाया था. मांगों में पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्तियों में 25 प्रतिशत की वृद्धि, आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों का शिक्षा शुल्क सरकार द्वारा भरा जाना, चैत्य भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना और अंबेडकर फाउंडेशन की स्थापना कर नागपुर में उसका मुख्यालय बनाना आदि शामिल हैं. उन्होंने दावा किया कि दादर स्टेशन का नाम चैत्य भूमि रखने की मांग कांग्रेस ने साल भर पहले उठाई थी. उनकी पार्टी इन मांगों को पूरा करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी. कांग्रेस को लगता है कि राकांपा का यह प्रयास उसके वोटरों में सेंध लगा सकता है. इसलिए चैत्य भूमि मामले का श्रेय लेने के लिए उसने राकांपा से पहले यह क़दम उठाया है. दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने दादर स्टेशन का नाम चैत्य भूमि रखे जाने का पुरजोर विरोध किया. राज ने कहा कि नाम बदलने से क्या होगा? कुछ नहीं बदलेगा. इसलिए महापुरुषों के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए. राज ने शिवसेना प्रमुख का बचाव करते हुए कहा कि अजीत पवार को बाला साहब के बारे में बोलते समय अपनी और उनकी उम्र का ध्यान रखना चाहिए. राज ने कहा कि आठवले के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि वह बाला साहब के घर के बगल में आलीशान मकान बनाकर रह रहे हैं. इस पर आठवले ने राज ठाकरे पर पलट वार करते हुए उन्हें विश्वासघाती बताया और कहा कि राज बताएं कि उन्होंने कोहिनूर की ज़मीन किन पैसों से ख़रीदी है. अब यह संघर्ष राज बनाम आठवले हो चुका है. इस राजनीतिक संघर्ष का एक रोचक तथ्य यह है कि भाजपा तमाशबीन की भूमिका में नज़र आ रही है. भाजपा ने दादर का नाम बदले जाने पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और न अजीत पवार एवं बाला साहब ठाकरे के बीच चल रही बयानबाज़ी पर कुछ कहा. वह सिर्फ़ शिव शक्ति–भीम शक्ति के साथ खड़ी है. इस गठबंधन की ओर से मोर्चे की कमान संभाल रखी है आठवले ने. वह लगातार राकांपा–कांग्रेस और राज ठाकरे के हमलों का जवाब दे रहे हैं.

बहरहाल, यह संघर्ष राज्य में दलित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए छेड़ा गया है. यह संघर्ष दलितों के हितों के नाम पर राज्य में अपना वर्चस्व क़ायम करने के लिए अधिक हो रहा है. दलितों की हालत सुधारने की चिंता किसने कितनी की, यह दो जून की रोटी के लिए संघर्षरत किसी मज़दूर से अच्छा कोई नहीं बता सकता. लिहाज़ा इस राजनीतिक संघर्ष से महाराष्ट्र का पूरा राजनीतिक व्याकरण ही बदलता नज़र आ रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

सबूत बताते हैं कि पास्को और सरकारी अधिकारियों के बीच आपराधिक साठगांठ है. इस प्रोजेक्ट को लेकर कई कमेटियों का गठन किया गया, जिन्होंने प्रोजेक्ट के तहत की जा रही धोखाधड़ी को देश के सामने उजागर किया.

पास्को परियोजना

राष्ट्रीय वन संपदा की खुली लूट

रोमा

उड़ीसा के जगतसिंहपुर में 50 हज़ार करोड़ रुपये निवेश करने वाली दक्षिण कोरिया की कंपनी पोहंग स्टील (पास्को) के आगे केंद्र और राज्य सरकार ने अपने घुटने टेक दिए हैं. पल्ली सभा (ग्राम परिषद) के विरोध के बावजूद बीती 18 मई को पोलंग गांव में भूमि अधिग्रहण के लिए पुलिस भेज दी गई है. इससे नंदीग्राम और सिंगुर की तरह पोलंग में भी ख़ूनी संघर्ष का माहौल तैयार हो चुका है. पास्को जहां भी ग्रामसभा और वनों की भूमि का अधिग्रहण कर रही है, वहां टकराव की स्थिति बनी हुई है. बीती 2 मई को वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश द्वारा पास्को प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने के बाद 18 मई को जगतसिंहपुर के बालीतूथा इलाक़े में बड़ी संख्या में पुलिस पहुंच चुकी है. यहीं से कंपनी द्वारा प्रस्तावित गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. पोलंग में ज़िला प्रशासन द्वारा पान एवं झींगा के खेतों, जंगल एवं आवासीय ज़मीनों पर क़ब्ज़े की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है. धिन्किया, नौगांव एवं गड़ा कुचंगा के हज़ारों लोगों ने इस ज़बरिया अधिग्रहण के ख़िलाफ़ मोर्चेबंदी भी शुरू कर दी है. उनके समर्थन में अनेक सामाजिक एवं स्वैच्छिक संगठन भी लामबंद हो गए हैं. लोगों ने बालीतूथा से धिन्किया, नौगांव एवं गड़ा कुचंगा को जोड़ने वाले सभी संपर्क मार्ग काट दिए हैं. प्रशांत भूषण, अरुणा राय, अरविंद केजरीवाल एवं वंदना शिवा आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में इस प्रोजेक्ट के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण को तत्काल रोकने की अपील की है.

सबूत बताते हैं कि पास्को और सरकारी अधिकारियों के बीच आपराधिक साठगांठ है. इस प्रोजेक्ट को लेकर कई कमेटियों का गठन किया गया, जिन्होंने प्रोजेक्ट के तहत की जा रही धोखाधड़ी को देश के सामने उजागर किया. इसके बावजूद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पास्को को देश की बेशक़ीमती प्राकृतिक संपदा लूटने की इजाज़त दे दी गई. हालांकि उड़ीसा हाईकोर्ट ने पास्को को वन अनापत्ति प्रमाणपत्र ज़ारी करने पर रोक लगा दी है. पास्को दुनिया के लगभग 70 देशों में इस्पात बनाने की परियोजनाएं चलाती है. पास्को परियोजना को 15 मई, 2007 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति मिली थी. कंपनी ने उड़ीसा सरकार के साथ 22 जून, 2005 को पांच साल के लिए करार किया था, जो अब समाप्त हो चुका है, लेकिन करार का नवीनीकरण किए बग़ैर कंपनी को पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र देने का अपराध किया गया. कंपनी को कुल 1621 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 1253 हेक्टेयर वनभूमि है. ऐसा करके जयराम रमेश और उड़ीसा सरकार ने पल्ली सभा के प्रस्तावों की भी अवहेलना की है, जिनमें वनाधिकार क़ानून की धारा 6 के तहत पास्को को धिन्किया एवं गोबिंदपुर की ज़मीनें देने का विरोध किया गया था. उड़ीसा सरकार ने न सिर्फ़ तथ्यों को दबाया, बल्कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को लिखा कि पल्ली सभा के प्रस्ताव फ़र्ज़ी थे और उन पर धिन्किया एवं गोबिंदपुर गांव के मात्र क्रमश: 69 और 64 लोगों के हस्ताक्षर थे. जबकि धिन्किया के 2,445 ग्रामसभा सदस्यों में से 1,632 और गोबिंदपुर के 1,907 सदस्यों में से 1,265 ने पल्ली सभा में पास्को के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था.

जिन गांवों की भूमि अधिग्रहीत की जानी है, वहां के लोगों ने ज़िलाधिकारी जगतसिंहपुर के ख़िलाफ़ भूमि रिकॉर्ड में हेराफेरी और झूठे तथ्य पेश करने के संबंध में एक आपराधिक मामला भी दर्ज कराया है. ज़िलाधिकारी ने बीते एक मार्च को बयान दिया कि प्रस्तावित भूमि पर 1930 से पहले कोई जंगल नहीं था. जबकि आंकड़े, जो आज़ादी से पहले के निस्तार पत्र रिकॉर्ड से लिए गए हैं, साबित करते हैं कि प्रस्तावित भूमि पर 1928 में घने जंगल थे (देखिए बॉक्स). पास्को परियोजना ज़ारी रखने पर केंद्र एवं राज्य सरकार की पूर्ण सहमति है. उड़ीसा में इसी तरह वेदांता कंपनी द्वारा किए जा रहे अवैध खनन और नियमागिरी पर्वत की प्राकृतिक संपदा की लूट के मामलों को लेकर भी केंद्र सरकार पर काफी दबाव बना था, जिसके तहत 2010 में दो सदस्यीय एन सी सक्सेना कमेटी गठित करके इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई और पाया गया कि कंपनी केवल वन संरक्षण अधिनियम 1980 का ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण एवं वनाधिकार क़ानून 2006 का भी खुला उल्लंघन कर रही थी. नियमागिरी के मामले में ही वनाधिकार क़ानून 2006 किसी कंपनी को क्लीयरेंस देने के लिए पहली बार राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना. इसी समय पास्को पर भी गाज गिरी, जब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और अनुसूचित जनजाति मंत्रालय द्वारा वनाधिकार क़ानून की समीक्षा के लिए अप्रैल 2010 में गठित की गई संयुक्त समीक्षा समिति का पास्को द्वारा अधिग्रहीत क्षेत्र में दौरा हुआ. समिति ने इन वन क्षेत्रों में प्रोजेक्टों को मिल रही अनुमति की वैधता पर सवाल उठाए और पाया कि वनाधिकार क़ानून 2006 का सरासर उल्लंघन किया गया है.

सक्सेना कमेटी ने ऐसे तथ्यों को उजागर किया, जिनकी उम्मीद पास्को और राज्य सरकार को नहीं थी. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 4 अगस्त, 2010 को पेश की, जिसमें कहा गया कि इस क्षेत्र में अन्य परंपरागत वनवासी रहते हैं, जिनके दावों को क़ानून की धारा 4 (5) के तहत पूरा किए बग़ैर उक्त भूमि अधिग्रहीत नहीं की जा सकती. अन्य परंपरागत वनवासियों (दलित, गरीब एवं आदिवासी, जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल नहीं है) के मामले पर अभी केंद्र और राज्य सरकार ख़ामोश हैं और उनके अधिकारों को मान्यता देने से आनाकानी कर रही हैं. इस वजह से आज हर वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत समुदायों के बीच तनाव और जातीय मतभेद बढ़ता जा रहा है. इन्हीं तमाम तथ्यों को सक्सेना कमेटी द्वारा उजागर किया गया. पास्को और सरकार के बीच क़रार पर हस्ताक्षर हुए पांच वर्ष से ऊपर हो गए हैं, लेकिन पास्को प्रतिरोध संघर्ष समिति के सशक्त विरोध के कारण पास्को कोई भी भूमि अधिग्रहीत नहीं कर पाई और न काम चालू कर पाई. संयुक्त समीक्षा समिति की इसी रिपोर्ट पर राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई. इस पर केंद्र सरकार ने 25 जुलाई, 2010 को मीना गुप्ता की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया. मीना गुप्ता कमेटी के समक्ष ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों ने कई साक्ष्य पेश किए, जो बताते हैं कि कंपनी ने न केवल वनाधिकार क़ानून का उल्लंघन किया, बल्कि अन्य परंपरागत वन समुदायों के अस्तित्व को ही नकार दिया. इस संदर्भ में ज़िलाधिकारी जगतसिंहपुर द्वारा झूठा बयान दिया गया कि इस क्षेत्र में अन्य परंपरागत समुदाय रहते ही नहीं हैं, जो कि 75 वर्ष पहले से इन ज़मीनों पर क़ाबिज़ हैं और न प्रस्तावित भूमि पर 1930 से पहले कोई जंगल था. मीना गुप्ता कमेटी में तीन सदस्य ऐसे थे, जिनमें एक पूर्व डायरेक्टर जनरल वन और अन्य दो सदस्य अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे. उन्होंने मीना गुप्ता के निष्कर्षों से अलग अपना मत बिना झिझक रखा. इस बहुमत रिपोर्ट में पाया गया कि जो तथ्य सक्सेना कमेटी के सामने आए थे, वे सही थे और उड़ीसा सरकार एवं प्रशासन ने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर पास्को के हित में काम करते हुए ग्राम परिषद के दावों के संदर्भ में झूठे तथ्य पेश किए. दोनों कमेटियों की रिपोर्ट आ जाने के बाद पास्को का मामला वन सलाहाकार समिति में भी गया, जहां सदस्यों में आम सहमति बनने में लगभग एक महीने का समय लगा. समिति में अधिकांश सदस्य, जो वन विभाग के थे, वे पास्को के पक्ष में मत देना चाहते थे.

अंतत: समिति ने 25 अक्तूबर, 2010 को पास्को का वन अनापत्ति प्रमाणपत्र रद्द करने की सिफ़ारिश कर दी. जबकि इससे पहले ही वन विभाग के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल एच सी चौधरी ने 5 अगस्त, 2010 को पत्र संख्या एफ 8-63/2007 एफ-सी में सक्सेना कमेटी की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए उड़ीसा के प्रमुख सचिव वन को पास्को को 1225.225 हेक्टेयर वन भूमि का स्थानांतरण रोकने और अनापत्ति प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश दे दिए थे. देश के पर्यावरण मंत्री ख़ुद इन कमेटियों द्वारा की गई जांच में पाए गए तथ्यों को स्वीकारते हुए राज्यसभा में पास्को और राज्य सरकार द्वारा ग्राम परिषद के साथ की गई हेराफेरी के बारे में उठे सवालों का जवाब दे चुके हैं. अनापत्ति प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश के बाद 9 अगस्त, 2010 को राज्यसभा में जयराम रमेश ने डी राजा के सवाल पर पास्को के संबंध में पूरे तथ्य रखे. उन्होंने कहा कि सक्सेना समिति ने पाया कि अधिग्रहीत किए जाने क्षेत्र में वनों में निवास करने वाले आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन समुदाय हैं, जिनके अधिकारों को वनाधिकार क़ानून के तहत मान्यता देने के लिए दावों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई. पास्को परियोजना को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से दिसंबर 2009 में जब मंजूरी मिली, उस समय वनाधिकार क़ानून 2006 पारित हो चुका था. इस क़ानून के तहत जो प्रक्रिया गांव में पूरी की जानी थी, उसे भी पूरा नहीं किया गया था. वन मंत्रालय अपने ही विभाग द्वारा पारित 3 अगस्त, 2009 के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें कहा गया है कि अब किसी भी वन भूमि को स्थानांतरित करने से पहले यह जांचा जाएगा कि वनाधिकार क़ानून के तहत कोई दावा लंबित तो नहीं है और यह मंजूरी ग्रामसभा के फ़ैसले के बग़ैर नहीं दी जाएगी, लेकिन अभी तक इस आदेश का स्वयं वन मंत्रालय द्वारा पालन नहीं किया गया.

उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का अगस्त 2010 में प्रधानमंत्री से ख़ास तौर पर पास्को को लेकर मिलना उस सौदेबाज़ी को साबित करता है कि केंद्र और राज्य सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने को कटिबद्ध है. ग़ौरतलब है कि उसी समय उड़ीसा में कंधमाल में ईसाइयों के साथ लूट और अन्याय के ख़िलाफ़ जंतर-मंतर दिल्ली पर बरसी मनाई जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री को दंगे के शिकार इस समुदाय की न ख़बर लेने की फ़ुरसत थी और न उससे मिलने की. उस समय राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों की गतिविधियों से लग रहा था कि नियमागिरी पर तो रोक लग जाएगी, लेकिन पास्को पर अभी फौरी तौर पर रोक लगाकर विवाद शांत किया जाएगा. केंद्र सरकार इसे किसी न किसी तरह बहाल करने का मन बनाए हुए थी, क्योंकि यह प्रोजेक्ट अब तक देश का सबसे बड़ा विदेशी पूंजी निवेश है. इस प्रोजेक्ट द्वारा हर वर्ष 1,95,000 करोड़ रुपये के टर्न ओवर और 65,000 करोड़ रुपये के मुनाफ़े का अनुमान है. यह मुनाफ़ा केवल कैपटिव आयरन और लोहे के खदान के आधार पर होगा. यहां वनाधिकार क़ानून की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है. ज़िला प्रशासन द्वारा कहना कि यहां अन्य परंपरागत वन समुदाय की मौजूदगी नहीं है, बिल्कुल ग़लत है. आख़िर क्या वजह है कि पास्को को लेकर इतनी कमेटियां बनीं, इसकी वैधता पर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात पहुंची और उड़ीसा के मुख्यमंत्री अगस्त, 2010 में एक हफ्ते तक दिल्ली में पड़े रहे और पीएमओ से आश्वासन लेकर ही गए कि इस कंपनी को अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने में किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी. सबसे महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक अन्याय की बात, जो वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों पर पिछले 250 साल से किए जा रहे हैं और वनाधिकार क़ानून 2006 की प्रस्तावना में जिन्हें समाप्त करने का ज़िक्र है. पास्को परियोजना को स्वीकृति उस समय मिली थी, जब ए राजा देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री थे. उस समय परियोजना के तहत जन सुनवाई में मानवाधिकार हनन के कई मामले सामने आने के बावजूद ए राजा द्वारा कंपनी के प्रस्ताव को आनन-फानन में स्वीकृति दे दी गई.

(लेखिका एन सी सक्सेना समिति में बतौर विशेषज्ञ सदस्य शामिल थीं)

feedback@chauthiduniya.com

अधिग्रहीत वन भूमि पर परंपरागत तौर पर ग्रामीणों की निर्भरता और संबंधित दस्तावेज़

दस्तावेज़ का नाम और नंबर	विवरण	वर्ष	ग्राम/ क्षेत्र/वन क्षेत्र	टिप्पणी
गोबिंदपुर निस्तार पत्रक (14472)	जंगल से जालौनी लकड़ी लाने के लिए बर्धमान राजा द्वारा निस्तार पत्र ज़ारी	1922	गोबिंदपुर	
निस्तार पत्र (12847)	जंगल से जालौनी लकड़ी लाने के लिए बर्धमान राजा द्वारा निस्तार पत्र ज़ारी 1925 गोबिंदपुर	1925	गोबिंदपुर	
निस्तार पत्र (13179)	जंगल से जालौनी लकड़ी लाने के लिए निस्तार पत्र गोबिंदपुर	1912		
उचब नायक दस्तावेज़ (4029 वगैरह)	वनोपज के लिए निस्तार पत्र	1932	गोबिंदपुर	
जमींदारी भूमि रिकॉर्ड (1 व 2)	अधिकार एवं सुविधाएं	1952	किला कुचांग (गढ़ कुचांग)	यह रिकॉर्ड ग्रामीणों के उन अधिकारों को दर्ज करता है, जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं
कुचांग वन बंदोबस्त (पीपी 14 व 15)	खेती / वन भूमि पर अतिक्रमण	1952	भुनयापाल	यह रिकॉर्ड ग्रामीणों के उन अधिकारों को दर्ज करता है, जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं

नया बाज़ार के रतन सिंह के घर, जो जमुना कोठी के नाम से मशहूर है, की सीढ़ियों पर चढ़ते वक़्त का अंधेरा अब भी क़ायम है. रतन बताते हैं, यहीं से बलवाई ऊपर चढ़े थे.

भागलपुर दंगा
ज़ख़्म है कि भरने का नाम नहीं लेते

आवेश तिवारी

21 साल, एक महीना और एक दिन! आप कह सकते हैं, इतना समय कोई भी ज़ख्म भरने के लिए काफी होता है, मगर कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं, जिनके भरने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं. बिहार के भागलपुर शहर को भी एक ऐसी ही चोट लगी, जिसके घाव आज भी यहां के बाशिंदों की आंखों से रिसते रहते हैं. दर्द ख़त्म होने का नाम नहीं लेता. कभी मस्ज़िद की अजान से, कभी मंदिरों की घंटियों से तो कभी अदालत के फ़ैसले से यह और भी बढ़ जाता है. बुन्नी बेगम को अपने हाथों से खाना खाए उतना ही समय हो गया है, जितना इस शहर को दर्द सहते हुए. उन्हें अब भी लगता है, किसी दिन पगलाई भीड़ एक बार फिर आएगी और उनके बचे–खुचे सपनों को रौंदते हुए चली जाएगी. भागलपुर के नया बाज़ार निवासिनी बुन्नी अभी पिछले दिनों बेटी–दामाद के साथ इस शहर को एक बार फिर सलाम कह गई थीं, क्योंकि अयोध्या मामले का निर्णय आने वाला था. नूरपुर के बूढ़े रहमत कुरेदने पर कराह उठते हैं, उन्हें लगता है कि उनका पोता एक बार फिर बाबा–बाबा कहते हुए आएगा. उन्होंने अपनी आंखों के उस यक़ीन को मानने से इंकार कर दिया है, जो एक कुएं में उसकी लाश देखने से पैदा हुआ था. दंगा सिर्फ़ हत्याओं का एक बेहद क्रूर समयकाल नहीं होता, वह मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक कभी ख़त्म न होने वाले युद्ध को भी जन्म देता है. सामाजिक–आर्थिक लड़ाइयों के भी नए पन्ने मुआवज़े के लिए की जा रही जद्दोज़हद से खुल जाते हैं. शहर कल भी सदमे में था, अब भी सदमे में है.

नया बाज़ार के रतन सिंह के घर, जो जमुना कोठी के नाम से मशहूर है, की सीढ़ियों पर चढ़ते वक़्त का अंधेरा अब भी क़ायम है. रतन बताते हैं, यहीं से बलवाई ऊपर चढ़े थे. छत पर हमारी मुलाक़ात बुन्नी बेगम से होती है. साथ में 25–26 साल की जवान बेटी है, जो डायबिटीज से पीड़ित है. हमें देखते ही बुन्नी बेगम अपने दोनों हाथ जोड़ती हैं. कटी हुई उंगलियों से अभिवादन असहनीय हो जाता है. बुन्नी की चुप्पी टूटती है, यह मेरी बेटी है, इसी के यहां रहती हूं. अपने पति की रोटी चुराकर मुझे देती है. उस दंगे ने मेरा सब कुछ छीन लिया. बिटिया बीच में टोकते हुए कहती है, नहीं मां, इसलिए चोरी करती हूं, क्योंकि तुम्हारी ग़ैरत का ख्याल रहता है. बुन्नी बेगम बिलख पड़ती हैं. रुंधे गले से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, यहीं से हमारे बाल पकड़ कर नीचे ले गए थे वे. जहां मैं बैठी हूं, यहीं पहले हमारी दोनों बहनों को काट डाला. जब हमने कहा कि इन्हें मत मारो भैया, तो पहले मेरी उंगलियां काटीं, फिर मुझे ताबड़तोड़ छुरे मारकर मरा समझ कर चले गए. इस छोटी सी छत पर 22 लोगों को मारा गया और लगभग 18 लोग घायल हुए थे. पूरे पांच घंटे तक इस घर में इंसानों को जानवरों की तरह काटा जाता रहा, उधर हमारे घर धू–धू कर जल रहे थे. बुन्नी को दिए गए ज़ख्मों की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती. जिस वक़्त दंगाई शहर को रौंद रहे थे, ठीक उसी वक़्त नया बाज़ार की गलियों में पिंकी और रुक्कू का प्यार परवान चढ़ रहा था. बुन्नी का छोटा बेटा रुक्कू मोहल्ले की एक हिंदू लड़की के प्यार में पागल था. वादे, वफ़ा और उम्मीदें, साथ जीने–मरने की कसमें. सब कुछ इतने ख़ूनख़राबे के बाद भी क़ायम रहा. दंगों के कुछ ही दिनों बाद रुक्कू को दिनदहाड़े गोली मार दी गई. बुन्नी बताती हैं कि पुलिस के सामने मैं चीखती रही कि इसी ने काटी हैं मेरी उंगलियां, मगर उसने अनसुना कर दिया. जमुना कोठी में एक अशरफ मास्टर भी थे. इलाक़े के कई बच्चों को उन्होंने अंग्रेजी सिखाई थी, पर उन्हें मारने वालों में उनके छात्र भी थे.

नया बाज़ार मुस्लिमों से लगभग खाली हो चुका है. ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीन औने–पौने दामों में बेच दी और शहर छोड़कर चले गए. जो लोग रह गए हैं, उनके लिए ज़िंदगी का सफ़र अब भी बेहद मुश्किलों भरा है. दंगा पीड़ितों को मिली मुआवज़ा राशि भी काफी कम है. दंगाई आज भी खुलेआम घूम रहे हैं. बुन्नी की बेटी दरकचा, जिसका हिंदी में अर्थ चमकना होता है, से जब हमने पूछा कि क्या अब भागलपुर चमक रहा है? वह कहती है, हां, शहर चमक रहा है, लेकिन हमारा घर नहीं. बुन्नी अचानक बोल पड़ती हैं, जानते हैं भाई, दंगाइयों ने किसी की इज़्ज़त नहीं लूटी. वे चाहते थे तो ऐसा कर सकते थे. क्या इस बात पर हमें गहरी सांस लेनी चाहिए? जवाब शाह जंगी में मिलता है. इस बस्ती के ज़्यादातर घरों में छत के नाम पर सिर्फ टीन है. गली के मुहाने पर 70–80 साल के दरमियां उम्र वाले 5–6 बुजुर्ग ताश खेल रहे हैं. सड़क पर बैठा लाठी लिए एक बूढ़ा हमें देखकर उठ खड़ा होता है. कौन हो बाबा? लड़खड़ाती हुई आवाज़ आती है, मैं हूं.....गुलज़ार ख़ान. दंगे में मेरी बेटी, बीवी और पोते को मार दिया गया. बीवी और बेटी को मारा, मगर उस बच्चे को क्यों मारा? गुलज़ार की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, कहते हैं, बहुत याद आती है उन सबकी. किसने मारा था आपके घरवालों को? जवाब आता है, अब भी वे खुलेआम घूमते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते. गुलजार के घर अब न कोई कमाने वाला है, न पका कर खिलाने वाला. गुलज़ार कहते हैं, एक दिन सड़क पर लावारिस मर जाऊंगा. सरकार दंगाइयों को सज़ा नहीं दे सकी, हमें जीने का हक़ तो दे देती.

थोड़ी ही दूर पर रेहाना का घर है. जवान बेटी, खाली रसोई. दंगाइयों ने बेटे को तो मारा ही, नया बना घर भी फूंक डाला. रेहाना की बेटी बताती है कि भैया यहां रहता भी नहीं था, दिल्ली में काम करता था. उसे मालूम भी नहीं था कि शहर में दंगा हो गया है, वह छुट्टियों में घर आ रहा था, रास्ते में ही बलवाइयों ने उसे मार दिया. हम हर घर में पनाह मांगते रहे, पर किसी ने आसरा नहीं दिया. रेहाना का छोटा बेटा बताता है कि दंगों के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में जो थोड़े से पैसे मिले थे, वे ख़र्च हो गए. न कोई रोज़गार मिला और न जीने की बुनियादी सुविधाएं. आगे नसीमा का घर है, मोहल्ले वाले आगे जाने से रोक देते हैं कि वहां नसीमा का विक्षिप्त बेटा है. दंगे वाले साल पैदा हुआ था, तभी से पागल है, किसी पर भी हमला बोल देता है. नसीमा ने अपने पति और एक आठ साल के बेटे को दंगे में खो दिया था. आपके पति और बच्चे को किसने मारा? वह फूट पड़ती हैं हिंदुओं ने मारा. तब तक उसका विक्षिप्त बेटा दौड़ता हुआ आता है, नहीं, काफिरों ने मारा! चार बेटियों की मां नसीमा को मुआवज़ा मिल गया है, लेकिन सबकी क़िस्मत ऐसी नहीं है. शाह जंगी, नया बाज़ार और जगदीशपुर में कई मुस्लिम परिवार ऐसे हैं, जिन्हें अब तक एक धेला नहीं मिला. शर्मनाक यह कि 22 साल बाद भी दंगा पीड़ितों को अपनी पहचान साबित करनी पड़ रही है. आगे शबनम का मकान है, वह अब मायके में रहती हैं, बीड़ी बनाती हैं. नीतीश के जनता दरबार में दो बार हाज़िरी लगाई, मगर कुछ नहीं हुआ. जिस वक़्त पति की हत्या हुई, बेटी पेट में थी. शबनम की मां बताती हैं, उस वक़्त हम नूरपुर मोहल्ले में रहते थे. हमारा दामाद जमाल कलकत्ता में पढ़ाता था. शहर में दंगा हुआ तो पुलिस हमें दूसरी जगह ले गई. जब वापस लौटे तो घर जला हुआ था और मेरे पति ग़ायब थे. खाने की बात तो दूर, हम पानी को तरस गए थे. हमें आज भी लगता है कि वह लौट आएंगे. उनकी लाश नहीं मिली तो क्या इसमें मेरा कसूर है? हम औरत जात, कोई पुरुष नहीं, साथ में गर्भवती बेटी. कहां खोजते उनको? अब नतिनी बड़ी हो गई है, कहां से इसकी शादी करें?

चंदेरी गांव की मलका बेगम की कहानी दिल दहलाने वाली है. दंगाइयों ने उनकी टांगें काटकर उन्हें तालाब में फेंक दिया था. दंगों के बाद जब सेना तैनात की गई तो उसे मोहम्मद ताज नामक एक जवान से प्यार हो गया. जब अस्पताल से बाहर आई तो जम्मू–कश्मीर बटालियन में तैनात उस जवान ने उन्होंने शादी कर ली. ताज से उन्हें बच्चे भी हुए, लेकिन जैसे ही मलका को मुआवज़ा मिला, ताज मलका और बच्चों को धोखा देकर फरार हो गया. 1993 में मलका ने उसके ख़िलाफ़ मुक़दमा भी किया, लेकिन आज तक कोई राहत नहीं मिली. अशरफ नगर के महमूद ख़ान पावरलूम चलाते हैं. ख़ूनी मंगलवार अब भी उनके जेहन में ताजा है. बताते हैं, हमने उस दौरान दोस्तों के चेहरे भी बदलते देखे. चंपा नगर में उस दिन सारी लड़कियों को पड़ोसी गांव में भेज दिया गया. सिर्फ़ बूढ़े–बुज़ुर्ग और हम कुछ लड़के रह गए. रात को बम का धमाका हुआ, इसके पहले कि हम भी निकलते, दंगाइयों ने हमला बोल दिया. मेरे घरवालों को तो मारा ही, मेरे वालिद और मेरी जीवन भर की कमाई भी आग के हवाले कर दी. दंगाइयों ने हमारी ज़मीन और खेत पर क़ब्ज़ा कर लिया. 2500 रुपये में मकान और 6 हज़ार रुपये में हमने अपना खेत बेच दिया. जिन लोगों ने हत्याएं कीं, वे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं. महमूद कहते हैं, हमारे मकान जले, सामान जला, सब कुछ तबाह हो गया, बेशर्मी यह कि 600 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक क्षतिपूर्ति दी गई.

मुश्किलों का सिलसिला थमा नहीं

वर्ष 1989 में हुए भागलपुर के दंगे में कुल 982 मारे गए, 259 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. 195 गांवों के 1500 से अधिक घर नेस्तनाबूद कर दिए गए थे. 24 अक्टूबर, 1989 से लेकर लगभग एक माह तक चले इस दंगे में 48 हज़ार लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें ज़्यादातर बुनकर, मज़दूर या फिर सीमांत किसान थे. दो–दो कमीशन बनाए जाने के बावजूद न दंगा पीड़ितों को न्याय मिला और न कोई राहत. सरकार आज 22 सालों बाद भी दंगा पीड़ितों की पहचान तक नहीं कर पाई है. जस्टिस के एन सिंह की अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिश पर नीतीश कुमार ने अपने पिछले कार्यकाल में दंगा पीड़ितों को ढाई हज़ार रुपये महीना पेंशन देने की घोषणा की थी. केंद्र ने इस मद में 30 करोड़ रुपये भी उपलब्ध कराए. अब तक 3.5 लाख रुपये की दर से मात्र 480 दंगा पीड़ितों को मुआवज़ा मिल सका है. लगभग 14 करोड़ रुपये ज़िला प्रशासन के खाते में आज भी मौजूद हैं. बमुश्किल 300 परिवारों को पेंशन मिल रही है. लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में गठित जस्टिस शमसुल हसन आयोग ने 1981 दंगा पीड़ित परिवारों को चिन्हित किया था, मगर स्थानीय प्रशासन ने यह संख्या घटाकर 861 कर दी. भागलपुर में कई ऐसे परिवार हैं, जो ख़ुद को दंगा पीड़ित साबित करने के लिए दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं. जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उन्हें क्षतिपूर्ति के नाम पर केवल पांच–पांच सौ रुपये दिए गए. दंगों का सर्वाधिक असर बुनकरों पर पड़ा. दंगाइयों ने हजारों हथकरघे जलाकर राख कर दिए. सरकार ने बदले में जो हथकरघे दिए, उनकी ऊंचाई 10–12 फीट थी, जबकि आम बुनकर का घर 8–9 फीट ऊंचा होता है. नतीजतन, हथकरघे खुले में रखे होने की वजह से ख़राब होते चले गए. दंगा प्रभावित परिवारों को जहां बसाया गया, वहां बुनियादी सुविधाओं का नितांत अभाव है. शाह जंगी के विस्थापित पेयजल के लिए आज भी लंबी दूरियां तय करते हैं.

इसीलिए शहर ज़िंदा है

इतिहास गवाह है कि दंगों ने हमेशा हिंदुओं एवं मुस्लिमों के बीच दूरी बढ़ाई है, लेकिन भागलपुर दंगा दिलों को बांटने में नाकाम रहा. जमुना बाज़ार की प्रतिभा सिन्हा एवं और उनकी बेटी जेनी आज भी पूरे मोहल्ले के लिए प्रेम, सद्भाव और इंसानियत की प्रतीक हैं. भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर एवं सुप्रसिद्ध गांधीवादी स्वर्गीय डॉ. के एम प्रसाद की बेटी और उनकी मां ने एक हफ्ते तक मोहल्ले की मुसलमान औरतों, लड़कियों और बच्चों को अपने घर में पनाह दी. प्रतिभा सिन्हा का चूल्हा लगातार जलता रहा. जेन्नी बताती हैं, हम अपनी मां और दादी के साथ सीढ़ी पर रास्ता रोककर बैठे थे कि कोई बलवाई ऊपर न चढ़े. बाहर लोग मेरी मां को गालियां दे रहे थे कि मुस्लिमों को बाहर निकालो, मगर हमने ठान लिया था कि दरवाजा नहीं खोलेंगे. इस बीच हमें पता नहीं चला कि कब बलवाई पीछे से छत पर चढ़ गए. उन्होंने सीढ़ी का दरवाजा तोड़कर हमें बाहर निकाल दिया, फिर अंदर जमकर मारकाट मचाई. जिन्हें भी हम बचा सके, बचाया. जब एक दंगाई बड़ा सा फरसा लिए कमरे में घुसा, उस समय तीन बच्चे सांस रोके पर्दे के पीछे छिपे थे. सामने रैक पर टेप रिकॉर्डर रखा था, वह उसे लेकर चला गया और बच्चे बच गए. जमुना कोठी छोड़कर जा चुकीं प्रतिभा कहती हैं, जब कभी यहां आती हूं, बीता हुआ कल आंखों के सामने आ खड़ा होता है. जमुना कोठी के मुन्ना सिंह कहते हैं कि जिन्होंने भागलपुर को ज़ख्म दिए, वे इंसान कहलाने के लायक़ नहीं हैं. हम नई उम्र के कई हिंदू लड़कों से भी मिले. दंगे में अपना सब कुछ गंवा चुके परिवारों में उन्हें आज भी चाचियां और दीदियां दिखाई देती हैं. अशरफ नगर का नूर दंगे में अपनी मां और बच्चों को गंवा चुका है, लेकिन अपने उन हिंदू दोस्तों के आगे आज भी सजदा करता है, जिन्होंने जान पर खेलकर उसकी पत्नी और बहनों को दंगाइयों के हाथों पड़ने से बचाया था. वह कहता है, हत्यारों का कोई धर्म नहीं होता. मैं कैसे भूल सकता हूं मुन्ना यादव की अम्मा को, जो दिन–रात मेरे बाल सहलाते हुए कहती थीं कि बेटा, अभी हम ज़िंदा हैं.

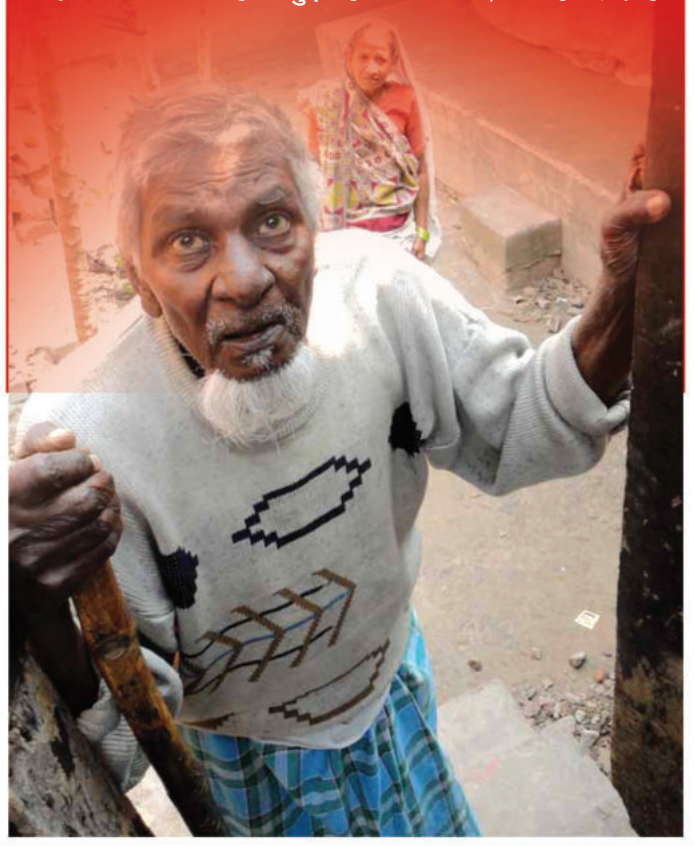

साथ में डॉ. जेन्नी शबनम

feedback@chauthiduniya.com

वी पी सिंह वित्त से रक्षा मंत्री बना दिए गए. रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बोफोर्स सौदे में दलाली का मुद्दा उठाया और पूरे देश के जनमानस को उद्धेलित कर सत्ता के चरित्र का पर्दाफाश कर दिया.

जन्मदिन पर विशेष

अन्ना और रामदेव वी पी सिंह से सीख लें

आंदोलन की घोषणा करना, आंदोलन करना और आंदोलन का सफल होना, ये तीनों बातें अलग–अलग हैं. रामदेव ने आंदोलन की घोषणा की, उसकी शुरुआत भी की, लेकिन 24 घंटों के भीतर रामलीला मैदान में उनके आंदोलन का क्या हश्र हुआ, सबने देखा. पुलिसिया कार्रवाई को जायज़ नहीं माना जा सकता, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसे समझने की ज़रूरत है. अन्ना ने पहले 5 दिनों का अनशन किया, लोकपाल बिल के लिए ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी बनी, लेकिन चंद बैठकों के बाद ही फिर से अन्ना को अनशन की चेतावनी देनी पड़ रही है, क्योंकि कमेटी की बैठक में सिविल सोसायटी के लोग सरकार से अपनी बातें मनवा पाने में असफल साबित हो रहे हैं. आख़िर ऐसा क्यों हो रहा है, इसे भी समझने की ज़रूरत है. बहरहाल, इन सवालों को समझने के लिए हमें एक शख्स को याद करना चाहिए, जिसका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वी पी सिंह.

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद तहसील की दो रियासतें थीं, डैया और मांडा. विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म इसी डैया के राजघराने में 25 जून, 1931 को हुआ था. डैया के बगल की रियासत मांडा के राजा थे राजा बहादुर राम गोपाल सिंह. वह नि:संतान थे. उन्होंने वी पी सिंह को गोद ले लिया. 1955 में वी पी सिंह ने बाकायदा कांग्रेस की सदस्यता ली और सक्रिय राजनीति में आए. 1957 में कठौली गांव के एक भूदान शिविर में अपनी 200 एकड़ उपजाऊ और नहर से जुड़ी भूमि (बिल्कुल सड़क के किनारे वाली) दान में दे दी. 1969 के विधानसभा चुनाव में वह सोरांवा विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंच गए. 1971 का लोकसभा चुनाव वह फूलपुर से लड़े और उन्होंने जनेश्वर मिश्र जैसे तपे–तपाए समाजवादी नेता को हराया. 10 अक्टूबर, 1976 को वह इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में व्यापारिक मामलों के उपमंत्री बना दिए गए, जहां दिसंबर 1976 तक रहे. 1980 में इंदिरा गांधी की केंद्र में वापसी हुई, तब वी पी सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया. इस दौरान उन्होंने राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए मंडल कमीशन की सिफ़ारिशों को लागू किया. वी पी सिंह जून 1980 से जून 1982 तक सिर्फ़ दो साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे. जुलाई 1983 में वह राज्यसभा में आए. इंदिरा गांधी के असामयिक निधन के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने. वी पी सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया. बतौर वित्त मंत्री वी पी सिंह ने महसूस किया कि इस व्यवस्था में केवल धनपतियों की चलती है, तब उन्होंने पूंजीवाद, धनपतियों और कर चोरों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंक दिया.

वी पी सिंह वित्त से रक्षा मंत्री बना दिए गए. रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बोफोर्स सौदे में दलाली का मुद्दा उठाया और पूरे देश के जनमानस को उद्वेलित कर सत्ता के चरित्र का पर्दाफाश कर दिया. तब तक प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उनका मतभेद काफी बढ़ चुका था. उन्होंने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया. मुज़फ़्फ़रनगर के किसान सम्मेलन में लाखों की भीड़ देखकर वी पी सिंह को पता चल गया कि देश की जनता परिवर्तन की बाट जोह रही है. कांग्रेस से अलग होकर वी पी सिंह ने जन समस्याओं के निदान के लिए जनमोर्चा का गठन किया. वी पी सिंह को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा. इसी बीच अमिताभ बच्चन के इस्तीफ़े से खाली हुई इलाहाबाद संसदीय सीट से वी पी सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस के सुनील शास्त्री को सवा लाख वोटों के अंतर से हरा दिया. वी पी सिंह के प्रयासों से व्यापक विपक्षी एकता बनी.

सात प्रमुख विपक्षी दलों को मिलाकर एक राष्ट्रीय मोर्चा तैयार हुआ. राजीव गांधी सरकार को वी पी सिंह ने भ्रष्टाचार एवं महंगाई समेत कई मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया. बोफोर्स मुद्दा अग्रणी बना. लोकसभा का चुनाव जनवरी, 1990 में होना चाहिए था, लेकिन राजीव गांधी ने नवंबर, 1989 में ही चुनाव कराने का निर्णय ले लिया. वी पी सिंह को पूरे देश में चुनावों का संचालन देखना पड़ा. कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, कहीं रक्तपात भी नहीं हुआ. केवल जनता की इच्छा थी कि सत्ता और विकास आम आदमी के दरवाज़े तक जाए. इसलिए जनता ने उस चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बेदख़ल कर दिया. राष्ट्रीय मोर्चा पूर्ण बहुमत के साथ सामने आया.

इस देश के उन करोड़ों किसानों, मज़दूरों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों का भी है, जिनकी अपनी-अपनी समस्याएं हैं. न तो अन्ना और न रामदेव अपने एजेंडे में इनकी समस्याएं शामिल कर पा रहे हैं और न इन लोगों को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं. जहां रामदेव के आंदोलन में आम जनता के नाम पर उनके भक्त ज़्यादा हैं, वहीं अन्ना के साथ शहरी मध्य वर्ग और शिक्षित युवा. ऐसे में इन दोनों को वी पी सिंह से सीखना चाहिए कि एक सफल आंदोलन के लिए कैसा, कितना व्यापक और समग्र दृष्टिकोण चाहिए. ख़ासकर भारत जैसे विविधता से भरे देश में.

वी पी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने दो दिसंबर, 1989 को अपना कार्यभार संभाल लिया. अगस्त 1990 में उन्होंने मंडल कमीशन की सिफ़ारिशें लागू करने की घोषणा की. वी पी सिंह का यह निर्णय भारतीय इतिहास में वंचितों के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. हालांकि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद भी वी पी सिंह के क़दम नहीं रुके. वह पूरे देश में घूम–घूमकर आम जनता के हितों के लिए संघर्ष करते रहे. इस दौरान जनता दल कई बार टूटा और टूटता ही रहा. धीरे–धीरे दलगत राजनीति से वी पी सिंह का मोहभंग होता गया और जुलाई 1993 में उन्होंने जनता दल संसदीय दल के नेता पद से त्यागपत्र दे दिया. इसके कुछ महीने बाद ही उन्होंने लोकसभा की सदस्यता भी छोड़ दी. दलगत राजनीति से बाहर आए तो जन चेतना मंच के ज़रिए जनसंघर्ष की शुरुआत की. दिल्ली की 30 हज़ार आबादी वाली वजीरपुर झुग्गी बस्ती को उजाड़ने के लिए सरकार ने बुलडोज़र चलाने की कोशिश की तो वह यह कहते हुए बुलडोज़र के सामने खड़े हो गए कि अगर सरकार सभी अनाधिकृत फॉर्म हाउसों को भी ढहा दे तो हम इस झुग्गी बस्ती को उजाड़ने से नहीं रोकेंगे. बाध्य होकर सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा. इस प्रकार झुग्गी झोपड़ी वालों की समस्या को वी पी सिंह ने एक राष्ट्रीय परिघटना बना दिया, लेकिन तब तक वी पी सिंह गुर्दे और कैंसर जैसी कई लाइलाज बीमारियों से घिर गए थे. धीरे–धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी. वह अपना इलाज भी कराते रहे और जनता के हितों की लड़ाई भी लड़ते रहे. दादरी के किसानों की भूमि के अधिग्रहण के विरोध में बीमार वी पी सिंह ने जो लड़ाई लड़ी, वह आज के आंदोलनकारियों के लिए किसी सीख से कम नहीं है.

27 नवंबर, 2008 को पूरा देश मुंबई पर आतंकी हमले से सहमा हुआ था. दोपहर में जब डॉक्टर रूटीन चेकअप के लिए आए तो उन्हें देखते ही वी पी सिंह बोल पड़े, डॉक्टर, मुझे आज़ाद कर दो. सचमुच पांच मिनट बाद यानी एक बजकर 55 मिनट पर उनकी धड़कन ठहर गई. वी पी सिंह को उनके जन्मदिन पर याद करना दरअसल वर्तमान दौर के आंदोलनों के स्वरूप को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है. वी पी सिंह ने यह दिखाया कि राजनीति करते हुए और राजनीति से बाहर रहते हुए भी आंदोलन किया जा सकता है और व्यवस्था में बदलाव लाया जा सकता है. जब हम देखते हैं कि अन्ना हजारे अपने मंच पर किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं आने देते या सिविल सोसायटी के लोग जनता से कांग्रेस या भाजपा को वोट न देने की अपील करते हैं, तब अन्ना और उनकी टीम की व्यापक एवं व्यवहारिक समझ पर संदेह होता है.

आख़िर इस देश में राजनीति और राजनेताओं को कैसे हाशिए पर डाल सकते हैं. मान लीजिए, अगर सरकार लोकपाल बिल (जैसा सिविल सोसायटी चाहती है) नहीं बनाती है तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जनता कांग्रेस को अगली बार सत्ता में नहीं आने देगी. लेकिन क्या इससे समाधान निकल आएगा? जनभावना को उद्वेलित करके सरकार बदली जा सकती है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए भविष्य की योजनाओं का होना ज़रूरी है. जो न अन्ना टीम के पास है और न रामदेव के पास. रामदेव जनता को यह नहीं बता सके कि काला धन वापस आने के बाद उसका क्या होगा और कैसे उसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि उस काले धन को ख़र्च करने की ज़िम्मेदारी तो आख़िरकार सरकार की ही होगी. रामदेव के पास इससे संबंधित कोई योजना नहीं है. रामदेव काले धन की बात करके जनता को सुनहरे भविष्य का सपना दिखा रहे थे. लेकिन सवाल सिर्फ़ काले धन या एक लोकपाल बिल का नहीं है. इस देश के उन करोड़ों किसानों, मज़दूरों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों का भी है, जिनकी अपनी–अपनी समस्याएं हैं. न तो अन्ना और न रामदेव अपने एजेंडे में इनकी समस्याएं शामिल कर पा रहे हैं और न इन लोगों को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं. जहां रामदेव के आंदोलन में आम जनता के नाम पर उनके भक्त ज़्यादा हैं, वहीं अन्ना के साथ शहरी मध्य वर्ग और शिक्षित युवा. ऐसे में इन दोनों को वी पी सिंह से सीखना चाहिए कि एक सफल आंदोलन के लिए कैसा, कितना व्यापक और समग्र दृष्टिकोण चाहिए. ख़ासकर भारत जैसे विविधता से भरे देश में.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भारत में नक्सली भी अफ़ीम की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं. वे अफ़ीम के बदले चीन, नेपाल एवं बांग्लादेश से हथियार और विस्फोटक लेते हैं.

अफ़ीम से महकते खेत

फ़िरदौस ख़ान

अफ़ग़ानिस्तान की वादियां ही अफ़ीम के फूलों से नहीं महकतीं, अब तो भारत में भी बड़े पैमाने पर अफ़ीम की खेती हो रही है. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के मुताबिक़, देश में क़रीब दस लाख लोग अफ़ीम की खेती से जुड़े हुए हैं. देश के विभिन्न राज्यों के 6900 गांवों के एक लाख 70 हज़ार परिवार अफ़ीम की खेती कर रहे हैं. इन सभी को सरकार ने लाइसेंस दे रखा है. ये तो सिर्फ़ वे आंकड़े हैं, जो सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज हैं. इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी अफ़ीम की खेती अवैध रूप से होती है. कुल अफ़ीम का 50 फ़ीसदी उत्पादन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होता है. देश में अफ़ीम उत्पादन का निर्धारित कोटा 12 सौ मीट्रिक टन है. इसमें 870 मीट्रिक टन निर्यात, 130 मीट्रिक टन घरेलू इस्तेमाल और 200 मीट्रिक टन स्टॉक के लिए है. भारतीय बाज़ार में एक किलो अफ़ीम की क़ीमत डेढ़ लाख रुपये है, जबकि एक किलो हेरोइन की क़ीमत डेढ़ करोड़ रुपये है. अफ़ीम से ब्राउन शुगर भी बनाई जाती है. अफ़ीम में 12 फ़ीसदी माफ़ीन पाई जाती है. अफ़ीम नशीली होती है और इसके सेवन से नींद आने लगती है. अफ़ीम एक औषधीय पौधा है और दर्द निवारक समेत कई दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा अफ़ीम नशे के भी काम आती है.

भारत अफ़ीम की वैध खेती कराने वाला दुनिया का पहला देश है. सरकार ने देश में अफ़ीम के उत्पादन की व्यवस्था में बदलाव करने का फ़ैसला किया है. इसके तहत ब्रिटेन की जॉनसन मैथी, स्पेन की अलकैलिबर, ऑस्ट्रेलिया की टीपीआई और हंगरी की एल्कलोइडा आदि कंपनियों के साथ मिलकर सन फार्मा ने अफ़ीम प्रसंस्करण का एक कारख़ाना लगाने का ठेका हासिल करने के लिए बोली लगाई है. यह ठेका हासिल करने वाली विदेशी कंपनी को भारत में पांच हज़ार हेक्टेयर में अफ़ीम की खेती करने की सुविधा भी मिलेगी. सरकार का मानना है कि भारतीय किसान आज भी पारंपरिक तरीक़े से खेती कर रहे हैं. इसके तहत पहले पोस्त के फल में चीरा लगाया जाता है और फिर उससे निकलने वाले द्रव्य को इकट्ठा कर लिया जाता है. इसके बाद उसे कारख़ानों को बेच दिया जाता है. इस प्रक्रिया में अफ़ीम का काफ़ी हिस्सा बर्बाद हो जाता है, जबकि आधुनिक तकनीक में फल से क़रीब आठ इंच नीचे चीरा लगाया जाता है और फिर खजूर के पेड़ से रस निकालने की विधि की तरह उसकी पेराई कर द्रव्य इकट्ठा किया जाता है. अफ़ीम की खेती का वक़्त दिसंबर से फ़रवरी तक है. फ़सल तैयार होने पर मार्च में इसकी कटाई शुरू कर दी जाती है. इसकी खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई जल की ज़रूरत होती है. ग़ौरतलब है कि वित्त मंत्रालय हर साल अफ़ीम की खेती से संबंधित लाइसेंस की नीति जारी करता है. सरकार अफ़ीम की खेती करने वाले किसानों को बीमे की सुविधा भी देती है. यह योजना केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) द्वारा जारी लाइसेंस के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में अफ़ीम की खेती करने वाले किसानों के लिए लागू होती है. नारकोटिक्स ब्यूरो पर्यवेक्षण के अधीन की जा रही अफ़ीम की खेती में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, तूफ़ान की वजह से फ़सलों के उखड़ने, पाला, कीट एवं अन्य रोगों से होने वाले नुक़सान के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है. बीमा बुवाई से फ़सल काटने की प्रथम प्रक्रिया शुरू करने के तुरंत पहले की तारीख़ तक होता है.

अफ़ग़ानिस्तान अफ़ीम का सबसे बड़ा उत्पादक है. यहां एक लाख 31 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में अफ़ीम की खेती होती है. अफ़ग़ानिस्तान के किसानों ने 2010 में क़रीब चार हज़ार टन अफ़ीम का उत्पादन कर 60 करोड़ डॉलर की कमाई की है, जो 2009 के मुक़ाबले 38 फ़ीसदी ज़्यादा है. हालांकि यह उत्पादन 2003 के मुक़ाबले सबसे कम है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अचानक अफ़ीम की क़ीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण किसानों को फ़ायदा हुआ. तालिबान की आमदनी का मुख्य ज़रिया भी अफ़ीम की खेती है. बताया जाता है कि इस वक़्त तालिबान ने क़रीब 12 हज़ार टन अफ़ीम की जमाख़ोरी कर रखी है. दुनिया की 90 फ़ीसदी हेरोइन अफ़ग़ानिस्तान से ही अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में पहुंचती है. यहां 2007 में 8200 टन और 2008 में 7700 टन अफ़ीम का उत्पादन हुआ. संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य नियंत्रण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, दुनिया भर में सालाना 400 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार होता है. नशीले पदार्थों का धंधा लोहे, इस्पात और कारों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से ज़्यादा और कपड़े के निर्यात के बराबर है. इन नशीले पदार्थों के धंधे में इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि तस्कर इसके लिए बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं. मादक पदार्थों के कारोबार के दो लोकप्रिय रूट हैं. एक है गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस शामिल हैं और दूसरे रूट गोल्डन क्रिसेंट में अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं. भारत भी मादक पदार्थों के कारोबार का गढ़ बन चुका है. भारत में नाइजीरियाई मादक पदार्थों का कारोबार चला रहे हैं. भारत में हर साल एक हज़ार किलो हेरोइन और 120 किलो कोकीन की खपत होती है. नशे का इंजेक्शन लेने वाले उत्तर-पूर्व के लोगों में से क़रीब 78 फ़ीसदी लोग संक्रामक बीमारियों के शिकार हैं. कोकीन का कारोबार दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया से संचालित होता है. कोलंबिया के अलावा ब्राज़ील और मैक्सिको से भी यह कारोबार चलता है. कोलंबिया में सबसे ज़्यादा कोकीन तैयार की जाती है. इस मामले में पेरू दूसरे और बोलीविया तीसरे स्थान पर है. दुनिया भर में कोकीन का सेवन करने वालों की तादाद क़रीब डेढ़ करोड़ है. कोकीन का कारोबार कोलंबिया से शुरू होकर अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, हांगकांग और पुर्तगाल के रास्ते पूरी दुनिया में फैलता है.

भारत में 1985 में नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांस एक्ट (एनडीपीएस) बनाया गया था. यह क़ानून अफ़ीम पैदा करने से लेकर विभिन्न क़िस्म के नशे के सेवन और उनके अवैध कारोबार से जुड़े हर अपराध की सज़ा निर्धारित करता है. इसकी दफ़ा आठ के मुताबिक़, अवैध रूप से अफ़ीम की खेती करते हुए पकड़े जाने पर 10 से 20 साल तक क़ैद और दो लाख रुपये तक के जुर्माने की सज़ा है. 1989 में इसमें एक नया अध्याय 5-ए जोड़ा गया, जिससे पुलिस को यह अधिकार दिया गया कि वह अफ़ीम के अवैध कारोबार के ज़रिए बनाई गई संपत्ति को ज़ब्त कर सकती है. क़ानून में कोई भी नशीली दवा बेचने, बांटने, अपने पास रखने और उनके आयात-निर्यात में शामिल होने आदि की सज़ा निर्धारित की गई है. इसकी सज़ा 10 से 20 साल तक हो सकती है. दूसरी बार इसी तरह के अपराध में पकड़े जाने पर सज़ा 30 साल तक हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन यह क़ानून अपने इस्तेमाल के लिए नशीली दवा रखने और बिक्री करने के अपराधों में ही फ़र्क़ करता है. अगर आरोपी यह साबित करने में कामयाब हो जाए कि उसके पास मिलीं नशीली दवाएं ख़ुद के इस्तेमाल के लिए हैं तो उसे केवल छह माह से एक साल तक की सज़ा होगी. इसके लिए ज़रूरी है कि बरामद दवाओं की मात्रा कम हो. यह मात्रा अलग-अलग नशीले पदार्थों के लिए अलग-अलग तय की गई है.

अफ़ीम की खेती को लेकर सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है. एक तरफ़ तो सरकार अफ़ीम उत्पादन को बढ़ावा देने के नाम पर विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ़ भारतीय किसानों को लाइसेंस देने की शर्तों को कड़ा कर दिया गया है. लाइसेंस की एक शर्त के मुताबिक़, किसान को प्रति हेक्टेयर 53 किलो अफ़ीम देनी होती है. अफ़ीम का लक्ष्य पूरा न होने पर बीते फ़रवरी माह में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के 300 किसानों ने 80 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फ़सल तबाह कर दी थी. उनका मानना था कि ऐसा करने से उनका लाइसेंस तो बच जाएगा.

भारत में नक्सली भी अफ़ीम की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं. वे अफ़ीम के बदले चीन, नेपाल एवं बांग्लादेश से हथियार और विस्फोटक लेते हैं. नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी समय-समय पर छापामारी करके अफ़ीम की अवैध खेती करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं. इस दौरान अफ़ीम के लहलहाते खेतों को तबाह कर दिया जाता है. अफ़ीम की खेती करने वाले किसानों का आरोप है कि ब्यूरो उन्हें लाइसेंस नहीं देता. झारखंड के अमूमन सभी ज़िलों में अफ़ीम की खेती हो रही है. नारकोटिक्स ब्यूरो ने माना है कि राजधानी रांची समेत, हज़ारीबाग़, चतरा, दुमका, खूंटी, कोडरमा, गिरिडीह, लातेहर, साहेबगंज, बोकारा और धनबाद में अफ़ीम की खेती से किसान मोटी कमाई कर रहे हैं. इसके अलावा जामताड़ा, पाकुड़, गुमला और पलामू में भी अफ़ीम की खेती होती है. ख़ास बात यह है कि आम किसान ही नहीं, बल्कि गांव के मुखिया भी अफ़ीम की खेती करते हुए पकड़े गए हैं. बीते फ़रवरी माह में पश्चिम बंगाल के वीरभूम और वर्द्धमान ज़िले में पुलिस ने 150 एकड़ भूमि पर लगी अफ़ीम की फ़सल को तबाह किया. इसी तरह बीते अप्रैल माह में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मुहिम चलाकर अफ़ीम के क़रीब 10 लाख पौधे नष्ट किए. नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने उत्तराखंड के 44 ऐसे गांवों की पहचान की है, जहां अवैध रूप से अफ़ीम की खेती होती है. टीम ने मोताड़, बैनोल, देई, राजूगांव, बदाऊ , बन्नूगाड़ और बागी आदि गांवों में छापा मारकर अफ़ीम की फ़सल नष्ट की. हरियाणा के कैथल ज़िले में भी बीते मार्च माह में अफ़ीम की खेती पकड़ी गई. इसी दौरान पुलिस ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी अफ़ीम की अवैध खेती पकड़ी.

अफ़ीम की खेती को लेकर सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है. एक तरफ़ तो सरकार अफ़ीम उत्पादन को बढ़ावा देने के नाम पर विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ़ भारतीय किसानों को लाइसेंस देने की शर्तों को कड़ा कर दिया गया है. लाइसेंस की एक शर्त के मुताबिक़, किसान को प्रति हेक्टेयर 53 किलो अफ़ीम देनी होती है. अफ़ीम का लक्ष्य पूरा न होने पर बीते फ़रवरी माह में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के 300 किसानों ने 80 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फ़सल तबाह कर दी थी. उनका मानना था कि ऐसा करने से उनका लाइसेंस तो बच जाएगा. नारकोटिक्स ब्यूरो ने तस्करी के मद्देनज़र किसानों पर सख्ती करते हुए उनसे उपज का ब्योरा लेना शुरू कर दिया है. किसानों का कहना है कि मौसम अनुकूल न होने एवं अन्य कारणों से उत्पादन घटने, कृषि लागत बढ़ने और नारकोटिक्स ब्यूरो के सख्त रवैये के कारण अफ़ीम उत्पादकों का इससे मोहभंग होने लगा है. हालत यह हो गई थी कि 2006-07 में सिर्फ़ सात किसानों ने ही अफ़ीम की खेती का लाइसेंस लिया था. बाद में इन किसानों ने भी अफ़ीम की खेती से तौबा कर लाइसेंस वापस कर दिए. इसके चार साल बाद किसानों ने अफ़ीम की खेती को अपनाया, लेकिन पर्याप्त उत्पादन न होने की वजह से उन्हें मायूसी ही हाथ आई. सनद रहे कि नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों ने ज़िले के जैतपुर, हैदरगढ़ और सुबेहा में हेरोइन की तस्करी करने वाले गिरोह के कई सदस्यों को पकड़ा था, तबसे यहां के किसानों के साथ सख्ती शुरू कर दी गई.

मध्य प्रदेश के भवानी मंडी के किसानों को भी ख़ासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि लगातार गिरते भूजल स्तर का असर अफ़ीम के उत्पादन पर पड़ा है. उत्पादन घटने से उनकी आमदनी इतनी कम हो गई है कि घर-परिवार का गुज़ारा करना मुश्किल हो गया है. उन्हें इस बात का भी मलाल है कि जहां बाज़ार में अफ़ीम की क़ीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं इस हिसाब से सरकार ने उनकी फ़सल के दाम नहीं बढ़ाए हैं. क़रीब ढाई दशक पहले यहां के किसानों के पास 25 हज़ार पट्टे थे, मगर अब यह घटकर सिर्फ़ छह सौ रह गए हैं. क़ाबिले ग़ौर है कि अफ़ीम के मुद्दे पर उन्नीसवीं सदी के मध्य में चीन और ब्रिटेन के बीच दो लड़ाइयां भी हो चुकी हैं, जिन्हें अफ़ीम युद्ध के नाम से जाना जाता है. दरअसल, ब्रिटेन के चीन के साथ कारोबार में आई कमी और ब्रिटेन द्वारा भारत से चीन में कराई जा रही अफ़ीम की तस्करी को लेकर दोनों देशों में जंग के हालात बन गए. पहली जंग 1839 से 1842 और दूसरी जंग 1856 से 1860 तक चली. दोनों ही जंगों में चीन की हार हुई और उसे अफ़ीम तस्करी के मुद्दे पर ख़ामोश रहने के लिए मजबूर होना पड़ा. उस वक़्त चीन में अफ़ीम के आयात पर पाबंदी थी. इस जंग में फ्रांस ने ब्रिटेन का साथ दिया था.

firdus@chauthiduniya.com

रुपये बहुत उपयोगी हैं, इनसे आप अपनी आवश्यक वस्तु प्राप्त कर सकते हैं. वे वस्तुएं नहीं, जो दूसरों की दृष्टि में आपके लिए आवश्यक हैं.

जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ रहा है, जिससे पैदावार में कमी के कारण खाद्यान्न संकट की समस्या भी उत्पन्न हो रही है.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

वितरण का माध्यम मुद्रा

साम्यवाद के संबंध में अख़बारों से पढ़कर आपने शायद सोचा होगा कि यह रूस द्वारा चलाई गई भयानक आर्थिक नीति है, जिसके द्वारा मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एकांत रूप से उपेक्षित होती है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है. साम्यवाद तो वित्त वितरण का बड़ा ही आदरणीय और सुगम मार्ग है, जो हज़ारों वर्षों से, किसी न किसी रूप में, कुछ अंशों में भारत में विद्यमान रहा है. सड़कें, पानी, रोशनी, पाठशाला, नदी के पुल इत्यादि आज के युग में साम्यवाद के प्रतीक हैं. [illegible]

[illegible]

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नद्रष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

आरोप लगाने से ज़्यादा कठिन है शासन करना

वर्ष 1970 की बात है. एडवर्ड हीथ प्रधानमंत्री पद की दौड़ में हैरल्ड विल्सन के ख़िलाफ़ खड़े थे और लोगों से यह वादा कर रहे थे कि मैं महंगाई कम कर दूंगा. जब वह जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, तब उन्हें पता चला कि विपक्ष में रहकर आरोप लगाने से ज़्यादा कठिन सत्ता में आने के बाद काम करना होता है, अपने वादों को पूरा करना होता है. कुछ इसी तरह की हालत लोकपाल बिल को लेकर अभी भारत में देखने को मिल रही है. फिर से आमरण अनशन की चेतावनी ने सरकार को बेचैन कर दिया है. जब अन्ना हजारे अपना आमरण अनशन कर रहे थे, तब रायसीना हिल्स में यह चर्चा चल रही थी कि यह अलोकतांत्रिक कदम है. हजारे ने जो मुद्दे उठाए हैं, वे दरअसल पिछले 40 सालों के दौरान सरकार की लापरवाही के विरोध में हैं. संसदीय लोकतंत्र में आई शून्यता की स्थिति को जनता के सामने लाने की कोशिश की गई.

इसके बाद सरकार शालीनता के साथ समझौता करने के लिए सामने आई और अन्ना हजारे के साथ बातचीत शुरू हुई. जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, अन्ना की टीम विजयी मुद्रा में आ गई और सरकार के सामने अपना कार्ड खोलने लगी और एक समय सीमा तय कर दी गई. याद रखने वाली बात है कि इस तरह की चीजें इतनी आसान नहीं होतीं. अगर आप उन्हें उचित तरीक़े से करना चाहें तो इतनी जल्दी भी नहीं हो सकतीं. विधेयक को काफी सावधानी से तैयार करना होता है, फिर उस पर बहस होती है और तब जाकर संसद उसे पारित करती है. इसका अर्थ यह नहीं है कि इस वजह से अनिश्चितकालीन देरी हो जाए, लेकिन सावधानी पूर्वक जांच तो करनी ही होगी.

जैसे ही यह पूरी प्रक्रिया शुरू की जा रही थी और शुरू हो भी चुकी थी, अचानक बाबा रामदेव का आमरण अनशन शुरू हो गया. इस वजह से भी कुछ गड़बड़ हुआ. इस अनशन ने कुछ और मनमानी मांगें सामने रख दीं. मसलन, काला धन वापस लाने का मामला, जबकि अभी लोकपाल पर बातचीत चल रही थी. काला धन वापस लाने का मामला ठीक हो सकता है, लेकिन यह न तो उतना आसान है और न भारत सरकार

के नियंत्रण में है. अमेरिका और जर्मनी को स्विस अधिकारियों से टैक्स चुराने वालों के आंकड़े जुटाने में काफी वक़्त लगा था और ब्रिटेन तो अभी भी इस प्रक्रिया में लगा हुआ है. ये अंतरराष्ट्रीय समझौते काफी जटिल और बहुत वक़्त लेने वाले होते हैं. असल में काला धन कितना है, इस पर भी असमंजस की स्थिति है.

इसके अलावा यह भी एक मुद्दा है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में होना चाहिए या नहीं. यह एक ऐसा विषय नहीं है, जिसमें ट्वीटर पर दिए गए संदेशों की गणना करके फ़ैसला लिया जा सके. ये सब जटिल मुद्दे हैं, जिन पर परामर्श किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ़ कुछ व्यक्तियों द्वारा अनशन करके. इस मुद्दे पर राज्य सरकारों और विपक्ष से भी बातचीत की जानी चाहिए, जिन्हें अभी तक इस पूरी प्रक्रिया से दूर रखा गया है. यदि सरकार अन्ना के मामले में अनिश्चित दिख रही थी तो रामदेव के मामले में वह अपनी ताक़त खोती दिखी. हवाई अड्डे पर जाकर चार मंत्रियों द्वारा बिना शर्त बाबा से बातचीत से ऐसा लग रहा था कि मानो सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया हो. आख़िर सरकार किस बात से डर रही थी. अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे किसी साधु या संन्यासी द्वारा आमरण अनशन की घोषणा के बाद सरकार क्या करेगी. सरकार का अर्थ है शासन करना, न कि मोबाइल द्वारा बुलाई गई भीड़ के सामने अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़ देना. सरकार रामदेव से भयभीत क्यों हुई, जबकि अन्ना से उसे डर नहीं लगा? मैं इस पर अभी केवल यही अंदाज़ लगा सकता हूं कि शायद कांग्रेस को रामदेव की राजनीतिक ताक़त का एहसास हुआ हो. कांग्रेस को इस देश में सिर्फ़ भाजपा और हिंदुत्व ही अपने दुश्मन नज़र आते हैं. इसलिए कांग्रेस अपने राजनीतिक लाभ की स्थिति को भाजपा के लिए राजनीतिक हानि में बदलने की हरसंभव कोशिश करती है. यही वजह है कि उसने लोकपाल के मुद्दे से भाजपा को दूर रखा (हजारे टीम की यह एक बड़ी ग़लती थी कि उसने ड्राफ्टिंग कमेटी में नेता विपक्ष को शामिल करने के लिए नही कहा). बाबा रामदेव अकेले हैं, लेकिन यदि उन्हें किसी को चुनना हो तो उनके सामने केवल भाजपा और आरएसएस ही हैं.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

बाबा का साम्राज्य

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे बाबा रामदेव ने विशाल कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर रखा है. उनके विश्वासपात्र बालकृष्ण कई कंपनियों के निदेशक हैं, जो केवल पांच साल के भीतर अस्तित्व में आई हैं. सीबीआई और आयकर विभाग ने अब कंपनियों पर नज़र डाली है. बाबा के पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट और दिव्य योग मंदिर को निशाने पर लिया गया है. ये दोनों ट्रस्ट हरिद्वार में एक हज़ार एकड़ भूमि पर बने हैं. 2009–2010 में दोनों ट्रस्टों का टर्न ओवर करीब 1100 करोड़ रुपये आंका गया. केंद्र सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये कंपनियां मेडिकल एवं कॉस्मेटिक्स आदि क्षेत्रों की हैं. बालकृष्ण की कंपनियों में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, दिव्य फार्मेसी योग, आरोग्य हर्बल, झारखंड मेगा फूड पार्क, दिव्य फार्मा और डायनामिक बिल्डकॉम आदि शामिल हैं. बाबा ने इतने कम समय में इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, यह बाबा से सीखना चाहिए.

–सरफ़राज़ ख़ान, *हिसार, हरियाणा.*

■ बाबा रामदेव भी अन्य बाबाओं की तरह हैं. उन्हें भी पैसे की अत्यधिक लालसा है. इसी कारण उन्हें आज तक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार नहीं मिला. एक विदेशी महिला ने अपना जीवन 51 रुपये से कोलकाता में शुरू किया और मदर टेरेसा के नाम से विख्यात हुई. कोढ़ियों एवं उपेक्षित लोगों की जिस तरह उन्होंने सेवा की, वह एक मिसाल है. नोबेल पुरस्कार से लेकर दुनिया भर के सम्मान उन्हें मिले.

–के के सिंह, *कोंडागांव, छत्तीसगढ़.*

हमारी प्रगति

जिन लोगों ने राजा–महाराजाओं और अंग्रेजी शासन का युग देखा है, केवल वे ही जानते हैं कि स्वराज में विकास की चाहे कितनी ही डींगें हांकी जाएं, परंतु सबसे अधिक प्रगति हमारे चारित्रिक पतन में हुई है. सादा जीवन एवं उच्च विचारों को तिलांजलि के साथ ही पांच सितारा जीवन पद्धति की होड़ के लिए पैसा ही सब कुछ हो गया है, चाहे वह किसी भी तरीक़े से इकट्ठा किया जाए. संयुक्त परिवार एवं पारिवारिक संबंधों की पवित्रता समाप्त होने से जीवन पद्धति प्रभावित हुई है. अरबों–खरबों के बजट एवं ख़र्च के बाद भी प्रशासन में कहीं भी ईमानदारी नज़र नहीं आ रही है. हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है. एक तरफ़ लाखों लोग भुखमरी के शिकार हैं तो दूसरी तरफ़ कुछ लोगों के पास अनाप–शनाप संपत्तियां हैं, करोड़ों रुपये हैं, टनों सोना है. न्याय प्रक्रिया की स्थिति यह है कि दशकों तक निर्णय सामने न आने पर लोग क़ानून हाथ में लेने को मजबूर हैं.

–एम सी बरला, *कोटा, राजस्थान.*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

देश हित ज़रूरी

आज भारत विश्व पर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है. अभी हाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दक्षिण अफ़्रीकी देशों के लिए करोड़ों रुपये का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत ख़ुद पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद पर आश्रित है और विश्व बैंक का भी क़र्ज़ हम पर है. देश में अशिक्षा है, ग़रीबी है और बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. यह तो वही बात हो गई कि अपने घर में आग लगी है और हम दूसरों को आग से बचने के उपाय बता रहे हैं.

–सुनील राणा, *कुतुब बाग़, दिल्ली.*

अख़बार पसंद आया

एक मित्र द्वारा चौथी दुनिया पढ़ने को मिला. एक साथ पूरा अख़बार पढ़ गया. अख़बार की जितनी भी तारीफ़ की जाए, कम है. सभी लेख उम्दा थे. अन्ना को अन्ना ही रहने दो शीर्षक से प्रकाशित आलेख ने बहुत प्रभावित किया. वैसे भी जितनी बड़ी सफलता जितनी जल्दी मिलती है, उतनी ही जल्दी उसका प्रभाव घटने लगता है. अन्ना के आंदोलन से आम आदमी का कोई मतलब नहीं है. आशा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार की सामग्री पढ़ने को मिलती रहेगी.

–सुनील कुमार चौहान, *बदायूं, उत्तर प्रदेश.*

लोकतंत्र का पाखंड

हमारे देश में लोकतंत्र एक दिखावे की वस्तु बनकर रह गया है. अंदरखाने सरकार तानाशाह है और नेता लोकतंत्र के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं. कहने को देश में जनता का शासन है, लेकिन वास्तव में कुछ मुट्ठी भर ताक़तवर लोगों के हाथ में ही पूरी शासन व्यवस्था है. लोकतंत्र की आड़ में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है. सब अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हैं.

–एन जे, *छपरा, बिहार.*

राजकमल प्रकाशन समूह
1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002
फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
शाखा : अशोक राजपथ, पटना-800006 फोन 0612-2672280
पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211001 फोन 0532-3293838, 2427274
लेखन विधा सम्मान 2011
'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जाने वाली 700 रुपए की किताबें

लेखक कमलनाथ ने भारतीय जन-गण की जुगाड़ की क्षमता को रेखांकित करते हुए बताया है कि भारत ने ग्लोबल मार्केट में महत्त्वपूर्ण स्थान कैसे बनाया?
शिवमूर्ति के इसी संग्रह की कहानी 'तिरिया चरित्तर' पर बासु चटर्जी ने फिल्म बनाई और 'कसाईबाड़ा' कहानी के पाँच हजार से अधिक मंचन।
राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029
पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

अन्ना और रामदेव उम्मीद की एक किरण हैं

यह देश विश्वास का मारा हुआ है. इस देश ने हर उस आदमी पर भरोसा किया, जिसने कहा कि हम समस्याओं से निजात दिलाएंगे. एक ओर नेहरू, इंदिरा, राजीव एवं वी पी सिंह तो दूसरी ओर जनता ने डॉ. राम मनोहर लोहिया और जेपी पर भरोसा किया. लोहिया ने सबसे पहले मिली–जुली सरकार की शुरुआत की थी. लोगों ने भरोसा किया, लेकिन उनकी समस्याएं हल कम हुईं, उल्टे और बढ़ गईं. धीरे–धीरे देश के लोग उस जगह पर पहुंच रहे हैं, जहां पर यह सवाल खड़ा हो गया है कि वे किसी पर भरोसा करें या न करें. ऐसे समय में अन्ना हजारे और बाबा रामदेव हमारे सामने आए हैं. अन्ना हजारे एवं रामदेव और जेपी, लोहिया एवं नेहरू आदि में बुनियादी फ़र्क़ है. पहले के लोगों ने विचारों के आधार पर समर्थन मांगा, जबकि रामदेव और अन्ना हजारे ने समस्याओं के आधार पर समर्थन मांगा है. यह बुनियादी फ़र्क़ देश को एक नए विश्वास और अविश्वास के चौराहे पर खड़ा कर देने वाला है. देश के लोग एक और धोखा न खाएं, इसलिए उन्हें अन्ना हजारे और रामदेव के वैचारिक और मानसिक स्तर को समझने की ज़रूरत है.

बाबा रामदेव या अन्ना हजारे के साथ जन समर्थन क्यों है? देश में कोई भी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, उसे जनता का समर्थन मिलेगा. इन लोगों को जनता का समर्थन इसलिए मिलता है, क्योंकि ये आशा जगाते हैं. लोग राजनीतिक दलों से निराश हो चुके हैं, सरकार और सत्ता से निराश हो चुके हैं. निराश होने की वजह यह है कि पिछले एक साल में एक के बाद एक इतने घोटालों का पर्दाफाश हुआ है कि लोगों को एक साथ सारे घोटालों का नाम भी याद रखना मुश्किल हो गया है. आम आदमी का सामना हर रोज इस भ्रष्ट तंत्र होता है. जब वह नेताओं के बारे में सोचता है, उसे भ्रष्ट व्यक्ति का चेहरा नज़र आता है. संसद की ओर देखता है तो निराशा और भी बढ़ जाती है. अधिकारियों की ओर देखता है तो उनमें एक घूसखोर नज़र आता है. सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर ऐसी कोई भी संस्था नहीं बची है, जिससे देश की जनता को कोई उम्मीद बची हो. देश में बेरोज़गारी, अशिक्षा और महंगाई है. आतंकवाद की वजह से पूरे देश में डर और ख़ौफ़ का माहौल है. ढाई सौ से भी ज़्यादा ज़िले नक्सलवाद की गिरफ़्त में आ चुके हैं. ऐसे में बाबा रामदेव और अन्ना हजारे आशा की किरण की तरह दिखते हैं. जब ये आवाज़ देते हैं तो लोग घर से बाहर निकल पड़ते हैं. बाबा रामदेव को इस बात के लिए श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार और काले धन के ख़िलाफ़ लोगों को जागरूक किया.

बाबा रामदेव की कुछ कमज़ोरियां भी हैं. सबसे बड़ी कमज़ोरी विचारधारा को लेकर है. किसी आंदोलन का नेतृत्व करना आसान काम नहीं है. इसके लिए भविष्य की साफ तस्वीर का होना ज़रूरी है. बाबा रामदेव भ्रष्टाचार से लेकर व्यवस्था परिवर्तन तक की बात तो करते हैं, लेकिन उनके पास भविष्य का कोई नक्शा नहीं है. बाबा रामदेव ने काले धन को लेकर पूरे देश को आंदोलित करके अनोखा काम किया है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि प्रजातंत्र में हर जाति, धर्म, वर्ग के लोगों का सहयोग लेना ज़रूरी होता है. एक सफल आंदोलन की पहचान यही है कि वह किसी वर्ग, जाति और धर्म के लोगों को नाराज़ नहीं करता. जेपी और लोहिया के आंदोलन की यह ख़ासियत होती थी कि कोई उनके आंदोलन का समर्थन करे या न करे, लेकिन वे किसी को विरोध करने का मौक़ा नहीं देते थे. बाबा रामदेव ने साध्वी ऋतंभरा से भाषण दिलवा कर देश के कई लोगों को नाराज़ कर दिया. बाबा रामदेव की इसी कमज़ोरी ने सरकार को यह हिम्मत दी कि वह रात के अंधेरे में पुलिसिया कार्रवाई कर सकी. बाबा रामदेव की यह भूल भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ देशव्यापी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुई.

कांग्रेस पार्टी ने बाबा रामदेव को सरकारी ताक़त का एहसास करा दिया. पहली बार बाबा रामदेव बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं. कांग्रेस पार्टी अब बाबा के साम्राज्य की क़ानूनी कमज़ोरियां तलाश रही है. बाबा के पास इतने पैसे कहां से आए, टैक्स दिया या नहीं दिया, विदेश में कहां–कहां

आम आदमी का सामना हर रोज इस भ्रष्ट तंत्र होता है. जब वह नेताओं के बारे में सोचता है, उसे भ्रष्ट व्यक्ति का चेहरा नज़र आता है. संसद की ओर देखता है तो निराशा और भी बढ़ जाती है. अधिकारियों की ओर देखता है तो उनमें एक घूसखोर नज़र आता है. सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर ऐसी कोई भी संस्था नहीं बची है, जिससे देश की जनता को कोई उम्मीद बची हो. देश में बेरोज़गारी, अशिक्षा और महंगाई है. आतंकवाद की वजह से पूरे देश में डर और ख़ौफ़ का माहौल है. ढाई सौ से भी ज़्यादा ज़िले नक्सलवाद की गिरफ़्त में आ चुके हैं. ऐसे में बाबा रामदेव और अन्ना हजारे आशा की किरण की तरह दिखते हैं.

पैसे निवेश किए, कहां–कहां क़ानून तोड़ा गया. गुरु शंकरदेव के गुम होने की वजह और रामदेव के साथी राजीव दीक्षित की मौत के रहस्य के बारे में भी पता लगाया जा रहा है. लेकिन सवाल है कि सरकार यह सब अब क्यों कर रही है. वह भी तब, जब चार–चार मंत्री एयरपोर्ट पर मिलने जाते हैं. कांग्रेस के कई नेताओं के रामदेव से पुराने संबंध रहे हैं. तब बाबा रामदेव की पड़ताल क्यों नहीं हुई. सरकार ने बाबा रामदेव की संस्था को आर्थिक मदद क्यों दी. राजनीति भी अजब–ग़ज़ब खेल कराती है. इसलिए जब सरकार और बाबा के बीच का क़रार टूटा, तब सरकार ने अपनी ताक़त दिखा दी. रात के वक़्त जब क़रीब 20 हज़ार लोग टेंट के अंदर सो रहे थे, तब पुलिस ने जो किया, उससे पूरे देश में सनसनी फैल गई. पुलिस की यह हरकत किसी भी नज़रिए से सही नहीं कही जा सकती. वैसे इस भगदड़ के दौरान बाबा रामदेव ने जो किया, उसका भी आकलन लोग कर रहे हैं. पुलिस की कार्रवाई सख़्त थी. उन्हें दिल्ली से हरिद्वार भेज दिया गया. उन्होंने मायावती से नोएडा में आंदोलन करने की इजाज़त मांगी, लेकिन मायावती ने इसे ठुकरा दिया. बाबा का आंदोलन अब हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में सीमित हो गया है. सरकार जो सवाल बाबा रामदेव से पूछ रही है, उसमें कई सवाल ऐसे हैं, जिनका जवाब रामदेव के पास है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी हैं, जिनका जवाब बाबा रामदेव के पास नहीं है.

रामदेव के आंदोलन का पहला लक्ष्य काला धन वापस लाना है और विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वालों को बेनक़ाब करके उन्हें दंडित करना है. इस मुहिम में बाबा के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए. लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या देश का काला धन सिर्फ़ विदेशी बैंकों में है. देश में जो काला धन है, जमाखोरी है, कालाबाज़ारी है, उसका क्या होगा. बाबा रामदेव को विदेशों में जमा काले धन के साथ देश के अंदर मौजूद काले धन को बाहर निकालने के लिए भी अपनी मुहिम में जगह देनी चाहिए.

बाबा रामदेव ने अब तक अपने आंदोलन या पार्टी की कोई समग्र और संगठित विचारधारा पेश नहीं की है. वह अपने शिविरों और रैलियों में राजनीति के बारे में बातें करते हैं. उनकी बातों से लगता है कि वह भारत में स्वदेशी व्यवस्था, अंग्रेजी भाषा के बहिष्कार, गौ हत्या के विरोध और अखंड भारत के पैरोकार हैं. रामदेव के भाषणों से जो बात निकल कर आती है, उससे यही लगता है कि उनकी विचारधारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा एक जैसी है. रामलीला मैदान में बाबा रामदेव ने कहा कि स्विस बैंकों से चार सौ करोड़ रुपया भारत लाना है और गौ हत्या के पाप से भी देश को बचाना है. गौ हत्या को अपराध संघ भी मानता है. काले धन पर भी रामदेव ने भाजपा वाली लाइन ले ली. विदेशों में जमा काले धन को निशाना बनाया. आश्चर्य की बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आडवाणी ने काले धन का मामला उठाया, तबसे बाबा रामदेव ने भी उस काले धन को मुख्य मुद्दा बनाया, जो विदेशों में है. विचारधारा न होने का यही दुष्परिणाम होता है कि आप मंच से कूदते हैं, महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं. आपको जान जाने का डर लगने लगता है, आप जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं. लेकिन यहीं पर नेता का चरित्र पता चलता है. जो जनता का नेता होता है, उसकी यह ख्वाहिश होती है कि उस पर पुलिसिया अत्याचार होते हुए लोग देखें. विचारधारा के अभाव में यह आंदोलन कहां पहुंचेगा, पता नहीं. उनके सारे बयान किसी सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा सामने नहीं रखते. इसका उदाहरण है, उनका एक बयान कि अब वह अपनी सेना बनाएंगे. आलोचना हुई तो कह दिया कि नहीं बनाएंगे. यहीं पर लोगों के विश्वास को, हो सकता है कि एक बड़ा धक्का मिले.

दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में आज न कोई नेता है और न कोई दल, जो विचारों और सिद्धांतों के आधार पर देश को एक नया सपना दिखा सके. इसीलिए जब समस्या आधारित आंदोलनों की बात कोई करता है तो लोग उसे शक की नज़र से देखते हुए भी उसका साथ देते हैं, क्योंकि सिद्धांत और विचारधारा कहीं नज़र नहीं आते. समस्या पर आधारित आंदोलन कभी बदले हुए समाज या बदली हुई व्यवस्था का स्वरूप रख ही नहीं सकता. इसीलिए बाबा रामदेव से यह आशा करना कि वह किसी नए समाज या व्यवस्था परिवर्तन का कोई नक्शा देश के सामने रख पाएंगे, बेवकूफी है. इसके बावजूद जब देश में सरकार के घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हों और भारतीय जनता पार्टी सहित वामपंथी दल विपक्ष की राजनीति के सिद्धांतों का मखौल उड़ा रहे हों, ऐसे समय में अन्ना हजारे और बाबा रामदेव द्वारा उठाई गई समस्याओं का स्वागत करना चाहिए.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

सौमित्र मोहन

जलवायु परिवर्तन

सबसे ज़्यादा असर ग़रीबों पर

इस बात से सभी सहमत हैं कि हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि ही जलवायु परिवर्तन की वजह है. इस नीले ग्रह (पृथ्वी) पर जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही है. यदि कोई संदेह रह गया है तो भारत में मानसून की आंख मिचौली और पूरी दुनिया में जलवायु का अनिश्चित व्यवहार इसके प्रमाण हैं. ऐसा माना गया है कि तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी से भी पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा. वहीं 19वीं सदी के आरंभ से अभी तक वैश्विक तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पहले ही हो चुकी है. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) का मानना है कि 2050 तक वैश्विक तापमान में 0.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस के बीच वृद्धि होगी, जबकि 2100 तक यह अनुमानित वृद्धि 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाएगी. ऐसा कहा गया है कि हर साल लगभग 10 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन हमारे वायुमंडल में छोड़ा जा रहा है. इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में लगभग 1.1 और 2.9 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ोत्तरी होगी. आईपीसीसी का आकलन है कि 2100 तक समुद्र के जलस्तर में 23 इंच तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है. माना जा रहा है कि समुद्र के जलस्तर में एक इंच की वृद्धि लगभग एक मिलियन लोगों के विस्थापन की वजह बन रही है. मानव जाति के सामने आने वाली तबाही को देखते हुए राहत और पुनर्वास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने की ज़रूरत है. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) का भी मानना है कि आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए शरणार्थी संबंधी मुद्दों को जल्द हल करने की ज़रूरत है.

जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ रहा है, जिससे पैदावार में कमी के कारण खाद्यान्न संकट की समस्या भी उत्पन्न हो रही है. नतीजतन, दुनिया के 6.75 बिलियन लोगों को खाद्य सुरक्षा की गंभीर समस्या से दो–चार होना पड़ सकता है. अनियमित वर्षा की वजह से हम पानी की कमी की समस्या से भी जूझ रहे हैं. बारिश का अधिकांश पानी यूं ही अधिक बहाव की वजह से बर्बाद हो जाता है और जंगलों की कमी की वजह से ज़मीन में पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे सूखे की समस्या झेलनी पड़ती है. समुद्र के जलस्तर में वृद्धि से न सिर्फ़ कृषि प्रभावित होगी, बल्कि मीठे पानी में समुद्र का खारा पानी मिलने से पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी. इसलिए

जल प्रबंधन नीति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वाटरशेड विकास पर भी ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है. जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव ग़रीबों और समाज के सबसे निचले तबके पर पड़ेगा, क्योंकि इनके पास बहुत सीमित क्षमता, योग्यता और स्रोत हैं. इसलिए समाज के इन वर्गों के जीविकोपार्जन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की ज़रूरत है. जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या में नगण्य योगदान के बावजूद सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वालों में यही लोग होंगे. बेहतर स्वच्छता और साफ़–सफ़ाई, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित पेयजल जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के साथ–साथ दूसरे अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों में शामिल हैं, जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है. स्वस्थ और बेहतर शिक्षित मानव संसाधन ही आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकता है. चतुर्दिक विकास ही इन सभी समस्याओं को जड़ से दूर करने का सबसे बेहतर उपाय है. मशहूर समाज विज्ञानी जॉन रॉल्स बिल्कुल सही कहते हैं कि न्याय का मतलब ही होता है, कल्याण के दायरे में सभी व्यक्तियों का शामिल होना. दुनिया की सभी सरकारों को यह तय करना चाहिए कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाए. इसमें ही सभी समस्याओं का सार निहित है. फिर भी हक़ीक़त यह है कि इनसे निपटने के लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंवेंशन में विकसित और विकासशील देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद सभी देश किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं.

भारत सहित कई विकासशील देशों का मानना है कि इन समस्याओं के लिए विकसित देश ज़िम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें सबसे अधिक ज़िम्मेदारी साझा करनी चाहिए. आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन चीन से चार गुना और भारत से 20 गुना ज़्यादा है. हालांकि 2006 में चीन ख़ुद कार्बनडाई ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है. भारत ने विकसित देशों के सामने प्रस्ताव रखा है कि उन्हें अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.5 फीसदी (1960 में साउथ कमीशन द्वारा प्रस्तावित 0.7 फीसदी से भी कम) हिस्सा अनुकूलन कोष (जैसे ग्रीन मार्शल प्लान) में देना चाहिए, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटा जा सके. ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए न सिर्फ़ उपभोक्तावाद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बल्कि पूरी दुनिया में उत्पादन और खपत की बढ़ रही ज़रूरतों को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है. निजी वाहनों की तादाद कम करने के लिए ईंधन और गाड़ियों पर अधिक टैक्स लगाने की भी सिफ़ारिश की गई है. इसके अलावा हमें अपनी प्रकृति को नुक़सान से बचाने और उसे पुनः हरा–भरा बनाने के लिए भी कई अन्य क़दम उठाने की जरूरत है. इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर वनीकरण की आवश्यकता है.

यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंवेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत क्लीन डेवलपमेंट मेकनिज़्म (सीडीएम) और एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम भी लागू करने की आवश्यकता है. सीडीएम का मतलब है कि धनी देशों की फर्मों एवं संस्थाओं को यह प्रस्तावित किया गया है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए विकासशील देशों की परियोजनाओं को आर्थिक मदद दी जाए. एमिशन ट्रेडिंग से तात्पर्य है कि जो देश तयशुदा सीमा से अधिक उत्सर्जन करेंगे, वे कम कार्बन उत्सर्जन वाले देशों को वित्तीय सहायता देकर ऐसा कर सकते हैं. हमें अनियमित मानसून की समस्याओं से निपटने के लिए अपनी सिंचाई क्षमता को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है. हालांकि खाद्य सुरक्षा के लिहाज़ से नदियों को जोड़ने की प्रस्तावित परियोजना को अभी काफी लंबा सफ़र तय करना है, पर यह कम ख़र्चीली और वैज्ञानिक रूप से व्यवहारिक भी है. इसमें संबंधित अनुसंधान और विकास तथा कृषि सुविधाओं के विस्तार के लिए विचार पर ज़ोर देने की ज़रूरत है. पश्चिमी देशों से पूर्व के देशों को तकनीक का हस्तांतरण कई समस्याओं को हल कर सकता है. कोयले से गैस बनाने, कार्बन पर नियंत्रण रखने, कम कार्बन वाले ईंधन की खोज और ऊर्जा के स्रोतों के विकास से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटा जा सकता है. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश और उनका इस्तेमाल भी जरूरी है. इस दिशा में अनुसंधान और विकास के लिए व्यापक स्तर पर निवेश की ज़रूरत है.

(लेखक आईएएस अधिकारी हैं. आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं और इनका सरकार के विचारों से कोई संबंध नहीं है)

feedback@chauthiduniya.com

आईडीएफ ने अनुमान लगाया है कि 2010 में इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरे विश्व में 37,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ख़र्च आएगा.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

समस्याएं अनेक समाधान एक

आज देश में एक धारणा बन गई है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं कराया जा सकता है. बहुत हद तक यह विचार सही भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार उस सीमा तक पहुंच गया है, जहां एक ईमानदार आदमी का ईमानदार बने रह पाना मुश्किल हो गया है. लेकिन इस भ्रष्ट व्यवस्था में भी आप यदि चाहें तो अपना काम बिना रिश्वत दिए करा सकते हैं. इसके लिए बस थोड़ी हिम्मत बनाकर रखनी होगी और सूचना कानून का इस्तेमाल करना होगा. हर आम या ख़ास आदमी का पाला कभी न कभी किसी सरकारी विभाग से पड़ता है. चाहे राशनकार्ड बनवाना हो या पासपोर्ट, आप चाहे शहर में रहते हों या गांव में, फाइल दबाने या आगे बढ़ाने के लिए सरकारी बाबुओं की रिश्वत की मांग से आप सभी का सामना ज़रूर हुआ होगा. गांवों में वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुजुर्गों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. शहरों में भी लोगों को आयु/जन्म–मृत्यु/आवास प्रमाणपत्र बनवाने या इन्कम टैक्स रिफंड लेने के लिए नाकों चने चबाने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है अलग से. अब सवाल यह है कि जो आदमी रिश्वत देने की स्थिति में नहीं है तो क्या उसका काम नहीं होगा. ऐसा नहीं है. काम ज़रूर होगा, वह भी बिना रिश्वत दिए. ज़रूरत है सिर्फ़ अपने अधिकार के इस्तेमाल करने की और वह अधिकार है सूचना का अधिकार. यह अधिकार एक क़ानून है. महज़ एक आवेदन देकर आप घूसखोर अधिकारियों की नींद हराम कर सकते हैं. यह आजमाया हुआ और सफल नुस्खा है. जैसे ही आप अपने लंबित काम से संबंधित एक आरटीआई आवेदन डालते हैं, भ्रष्ट और रिश्वतखोर अधिकारियों एवं बाबुओं की समझ में आ जाता है कि जिसे वे परेशान कर रहे हैं, वह आम आदमी तो है, लेकिन अपने अधिकारों और नियमों के प्रति जागरूक है. तय मानिए, सरकारी विभागों में आमतौर पर उन्हीं लोगों को ज़्यादा परेशान किया जाता है, जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं हैं. सूचना क़ानून में इतनी ताक़त है कि छोटे–मोटे काम तो आवेदन देने के साथ हो जाते हैं. इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, बजाय घूस देकर काम कराने के. चौथी दुनिया आपके हर क़दम पर आपका साथ देने को तैयार है. कोई भी समस्या हो, कोई सुझाव चाहिए या आप अपना अनुभव हमसे बांटना चाहते हों तो हमें पत्र लिखें या ईमेल करें. हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301,
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(किसी भी सरकारी विभाग में लंबित काम यथा राशनकार्ड, पासपोर्ट, वृद्धावस्था पेंशन, आयु–जन्म–मृत्यु–आवास प्रमाणपत्र बनवाने या इन्कम टैक्स रिफंड मिलने में देरी होने, रिश्वत मांगने या बिना वजह परेशान करने की स्थिति में निम्न प्रश्नों के आधार पर आ सूचना के अधिकार का आवेदन तैयार कर सकते हैं)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
मैंने आपके विभाग में.....तारीख़ को.....के लिए आवेदन किया था (आवेदन की प्रति संलग्न है), लेकिन अब तक मेरे आवेदन पर संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया है. कृपया इस संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. मेरे आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्यवाही अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. मेरा आवेदन किन–किन अधिकारियों के पास गया और किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा, इस दौरान उन अधिकारियों ने उस पर क्या कार्रवाई की? पूरा विवरण उपलब्ध कराएं.

2. विभाग के नियमों के अनुसार मेरे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनों में कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए थी? क्या मेरे मामले में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया?

3. कृपया उन अधिकारियों के नाम एवं पद बताएं, जिन्हें मेरे आवेदन पर कार्यवाही करनी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की.

4. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? यह कार्यवाही कब तक की जाएगी?

5. अब मेरा काम कब तक पूरा होगा?

(अतिरिक्त प्रश्न, यदि आवश्यक हों)

6. कृपया मुझे सभी आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत की सूची उपलब्ध कराएं, जिन्हें मेरे आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत के बाद जमा किया गया. सूची में निम्न सूचनाएं होनी चाहिए:
1. आवेदक/करदाता/याचिकाकर्ता/पीड़ित का नाम
2. रसीद संख्या
3. आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत की तारीख़
4. कार्यवाही की तारीख़

7. कृपया रिकॉर्ड के उस हिस्से की छाया प्रति दें, जो उपरोक्त आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत की रसीद का ब्योरा रखते हों.

8. मेरे आवेदन के बाद यदि किसी आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत को नंबर आने से पहले निस्तारित किया गया हो तो उसका कारण बताएं?

9. इस आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत के नंबर आने से पहले कार्यान्वयन के मामले में, यदि कोई हो तो, सतर्क पूछताछ कब तक की जाएगी?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में...रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय
नाम.....
पता.....

राशिफल

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल

इस सप्ताह आपको सभी प्रकार के छिटपुट कार्य निपटाने में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए. यदि आप किसी नौकरी या आजीविका से जुड़े हैं तो अधिकारी वर्ग आपके कामकाज से संतुष्ट रहेगा. किसी नई तरक्की का प्रस्ताव या स्थानांतरण की समीक्षा आपके हक़ में संभव है.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई

आपको अपने रोज़गार और कारोबार से जुड़े कार्यों के लिए घर से बाहर निकलना होगा. कुछ लोगों को सरकारी मामले निपटाने में जद्दोजहद करनी पड़ सकती है. यदि आप इन सब अटके हुए मामले निपटाने में तल्लीन रहेंगे तो सप्ताह मध्य में आपकी स्थिति बहुत उत्साहपूर्ण और स्फूर्तिदायक रहेगी.

मिथुन 21 मई से 20 जून

अपने और प्रियजनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे. किसी नए चिकित्सा स्थल या रोगोपचार करने वाले चिकित्सक की खोजबीन आप कर सकते हैं. यदि आपकी समस्या ज़्यादा गंभीर है तो इस मामले में दौड़धूप करने में भी पीछे नहीं रहेंगे.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई

यह सप्ताह आपको दूसरों के लिए कुछ कर दिखाने का मौक़ा दे रहा है. यदि आप अपने वादे को पूरा करना चाहें तो उसके लिए भी अनुकूल समय है. आपकी पहुंच और प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति के लिए रामबाण औषधि साबित हो सकती है. यही विचार आपको स्थायी साख और प्रसिद्धि देने में सहायक हो रहा है.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त

अपनी मान–मर्यादा और सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए कोई गुप्त चिंता आपको परेशान करेगी. शत्रुओं के षड्यंत्र विफल करने के लिए आप साम–दाम–दंड–भेद का सहारा ले सकते हैं. यदि आप समय रहते इन मामलों को अपने तरीक़े से हल नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपको खिन्नता झेलनी पड़ेगी.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर

कभी–कभी आय की तुलना में व्यय बढ़ जाने से आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है. ऐसा ही समय इस सप्ताह भी आपको बेचैन रखेगा. कार्यक्षेत्र में धीमी प्रगति के कारण आपका हौसला टूट सकता है.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

आप सिर्फ़ बातों से ही दूसरों को ख़ुश करने की तरकीब अपनाते हैं. इस सप्ताह यदि आप बातूनी और बड़बोले होकर काम करेंगे तो सहयोगी या वरिष्ठ अधिकारी की प्रताड़ना आपको झेलनी पड़ेगी.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

किसी विश्वसनीय दोस्त या प्रेमी के व्यवहार से आपको कुछ खिन्नता हो सकती है. आपको ऐसा लगेगा कि अब आपकी उपेक्षा होने लगी है. हो सकता है कि आपने उसके मिजाज़ पर पूरी तरह ग़ौर न किया हो या फिर उसकी किसी उल्टी–सीधी बात का ग़लत मतलब लगा लिया हो.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर

लोगों की नज़र में आप अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आंख बंद करके ख़र्च करते हैं. कुछ ऐसे ही सवालों और देनदारी का सामना इस सप्ताह करना पड़ सकता है, लेकिन छोटी–मोटी और झूठी वाहवाही के लिए अपनी जेब खाली करना बुद्धिमानी नहीं है.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी

यह सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. किसी गोष्ठी, मीटिंग या विचार–विमर्श के दौरान आपकी सलाह कार्यक्षेत्र में बहुमूल्य हो सकती है. किसी नई ज़िम्मेदारी या उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए भी आपसे कहा जा सकता है.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी

इस सप्ताह किसी कारण आपके मन में बहुत अशांति रहेगी. इसका कारण आर्थिक न होकर किसी प्रियजन या प्रेमी का व्यवहार भी हो सकता है. आपके अंदर यदि किसी मानसिक या शारीरिक कमज़ोरी का मामला बढ़ रहा है तो उसे दूर करने के लिए वैद्य या चिकित्सक की सलाह ज़रूरी है.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च

निजी या व्यवसायिक संबंधों के विस्तार के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल है. यदि आपको अपने पार्टनर या सहयोगियों पर पूरा भरोसा हो तो आप अपना काम उनके हवाले करके निश्चिंत हो सकते हैं. हो सकता है, आपकी दौड़भाग का कोई अच्छा नतीजा निकल आए.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

दुनिया का सबसे बड़ा खब्बू

डॉन गोसकि के नाम बिग मैक बर्गर खाने का विश्व रिकार्ड है. अमेरिका की एक जेल के इस रिटायर संतरी ने 25,000 बर्गर (बिग मैक) खाए. बिग मैक बहुत बड़े साइज़ का बर्गर होता है. डॉन गोसकि ने सबसे पहले नौ बर्गर ठीक 39 साल पहले खाए थे. उन्हें सम्मानित करने के लिए विसकोनसीन शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वह मरते दम तक बिग मैक बर्गर खाते रहेंगे. सत्तावन वर्षीय गोसकि 2004 में सुपर साइज़ बी नामक एक डाक्यूमेंट्री में भी शामिल हो चुके हैं. यह डाक्यूमेंट्री उन लोगों पर बनाई गई थी, जो रोज़ मैक्डोनल्ड का खाना खाते हैं और इस तरह के भोजन का उनके जीवन पर किस तरह का असर होता है.

हालांकि गोसकि दुबले–पतले हैं और उनका कोलस्ट्रॉल लेवल भी ठीक है. अपना 25,000वां बिग मैक बर्गर खाने से पहले गोसकि ने कहा कि जब वह 19 साल के थे, तब उन्होंने 1000वां बर्गर खाया था और पहली बार रिकॉर्ड बनाने का विचार उन्हें उसी वक़्त आया था. गोसकि कहते हैं, तब लगा था कि जब तक मैं 25,000 के रिकॉर्ड पर पहुंचूंगा, तब तक तो बूढ़ा हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन आप जानते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा नहीं हूं, मेरी उम्र 50 के आसपास है, हां रिटायर ज़रूर हूं. आप रिकॉर्ड बनाने के लिए इतने लंबे समय तक नहीं जीना चाहते हैं. गोसकि का कहना है कि वह जितने मैक बर्गर खाते हैं, उसका हिसाब रखते हैं. वह हर सोमवार को छह और गुरुवार को आठ बर्गर ख़रीद कर रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं. चिकित्सकों का कहना है कि वह किसी को गोसकि की तरह भोजन करने की सलाह नहीं देंगे.

बच के रहना रे बाबा

मधुमेह जैसी घातक बीमारी भारत को जकड़ती जा रही है. इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक़, विश्व में मधुमेह के सबसे ज़्यादा मरीज भारत में हैं. भारत में मधुमेह के मरीजों की संख्या 5.08 करोड़ है. वहीं चीन 4.32 करोड़ मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका 2.68 मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर है. आईडीएफ के अध्यक्ष प्रो. जीन क्लॉड बान्या के मुताबिक़, इन आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि अब यह बीमारी नियंत्रण के बाहर हो चुकी है. उन्होंने कहा, हम इस बीमारी से लड़ने की शक्ति खोते जा रहे हैं. कोई ऐसा देश नहीं है, जहां यह बीमारी न हो और न किसी देश में इससे लड़ने की पूरी क्षमता है.

आईडीएफ ने अनुमान लगाया है कि 2010 में इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरे विश्व में 37,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ख़र्च आएगा. वर्ष 2030 तक यह ख़र्च 49,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा. भारत में सबसे ज़्यादा मधुमेह के रोगी हैं, जहां हर साल 280 करोड़ डॉलर इससे लड़ने में ख़र्च होते हैं. आईडीएफ के प्रो. निगेल अनविन ने कहा कि पूरे विश्व को एकजुट होकर इस बीमारी के ख़िलाफ़ एक हेल्थ सिस्टम तैयार करना होगा, जिससे समय पर जांच हो सके और बचाव किया जा सके. आईडीएफ ने कहा कि विश्व के तमाम देश ऐसे हैं, जिनके पास मधुमेह से लड़ने की पर्याप्त क्षमता नहीं है और यह पूरे विश्व के लिए घातक है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ऐसा माना जाता है कि भारतीय विदेश नीति लचर है और चीन की पिछलग्गू है. जहां चीन जाता है, वहां भारत भी पहुंच जाता है.

भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2011

शुरुआत कमज़ोर पर राह सही

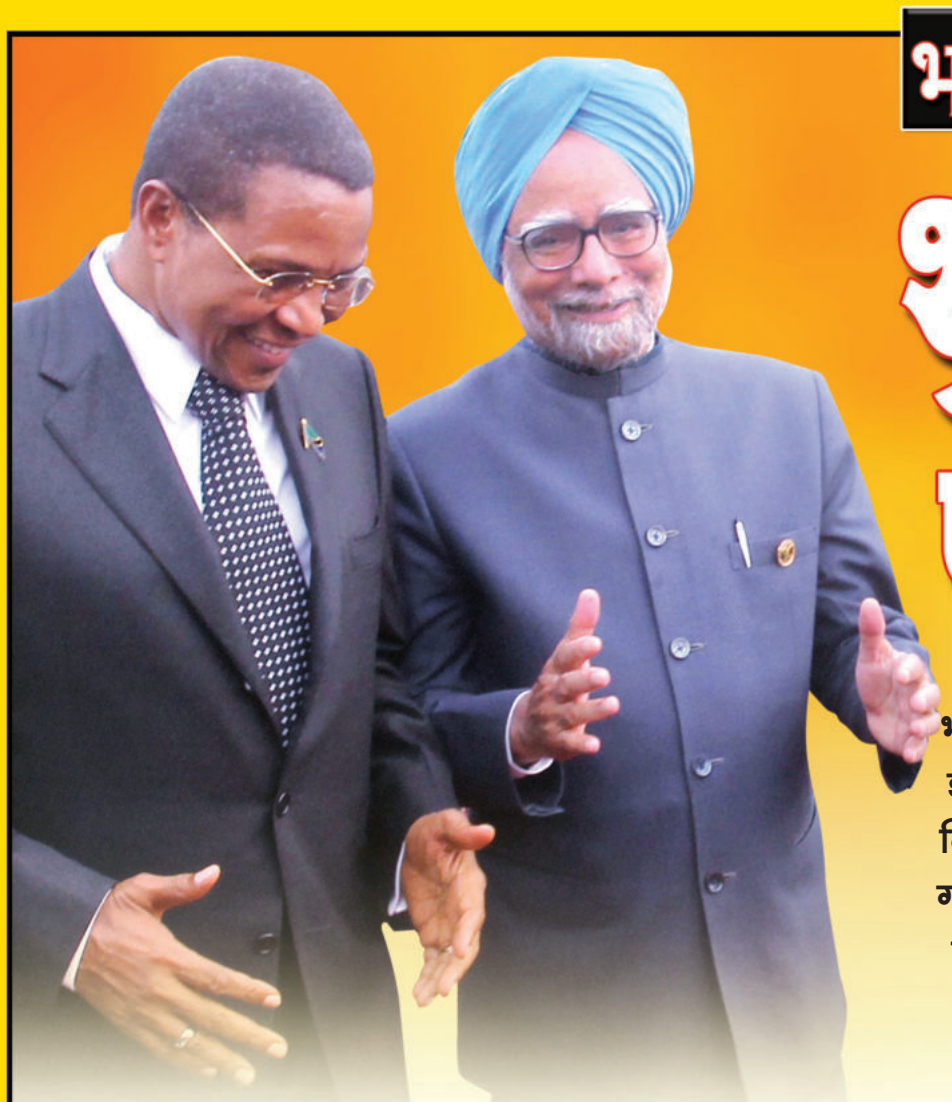

भारत ने अफ्रीका के लिए इस सम्मेलन के दौरान 5 बिलियन डॉलर अनुदान निश्चित किया है, जिसे अगले तीन सालों में दिया जाएगा. यह पैसा खासकर विकास कार्यों के लिए दिया गया है. साथ ही 700 मिलियन डॉलर का क़र्ज़ शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दिया गया है. भारत ने एक बिजनेस काउंसिल भी बनाई है, जो अफ्रीका में पैसा लगाने वाले पूंजीपतियों का कामकाज देखेगी.

आदिस अबाबा घोषणा पत्र

- अफ्रीका और भारत की दोस्ती आपसी विचारधारा के मेल पर आधारित.
- दोनों ही देशों में युवा शक्ति उभरने को आतुर.
- ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगे.
- विकसित देश विकासशील देशों को तकनीक दें.
- जी-20 में अफ्रीका को उचित स्थान दिया जाए.
- अफ्रीका को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की पूर्ति में मदद दी जाए.
- लीबिया में लड़ाई तुरंत ख़त्म हो, दोनों पक्ष असैनिक-राजनीतिक हल खोजें.
- अफ्रीका सुरक्षा परिषद में भारत के चयन का पक्षधर.
- संयुक्त राष्ट्र की कार्य पद्धति पारदर्शी बनाई जाए और उसमें सुधार हों.
- समुद्री लुटेरों पर रोक लगाई जाए.
- सामूहिक रूप से आतंकवाद की भर्त्सना.

सिद्धार्थ राय

भारत और अफ्रीका के बीच संबंध बहुत ही पुराने और ऐतिहासिक हैं. इतिहासकारों का कहना है कि भारतीय उप महाद्वीप पर मानव सभ्यता अफ्रीका केप ऑफ़ गुड होप से प्रारंभ हुई थी. मतलब यह कि भारत में सबसे पहले आने वाले मानव अफ्रीकी थे. महात्मा गांधी की पहली कर्मभूमि भी अफ्रीका की ही धरती रही. दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और सत्य के साथ अपने शोध को अंजाम दिया था. इसी कारण भारत और अफ्रीका की दोस्ती बहुत पुरानी और बाकी दोस्तों से अलग है, लेकिन आज तक भारत अपनी इस दोस्ती को आर्थिक और राजनीतिक तरीके से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं कर पाया है. पिछले कुछ सालों में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के चलते भारत ने अफ्रीका पर ध्यान देना शुरू किया है. इसी दिशा में भारत–अफ्रीका शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम है.

अफ्रीका और भारत की दोस्ती अन्य देशों से अलग है. इस विषय पर ध्यान से सोचा जाए तो हम यह पाएंगे कि जहां दूसरे देश अफ्रीका को मात्र खनिज और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की नज़र से देखते हैं, खासकर चीन, वहीं भारत द्वारा उठाए गए क़दमों से यह साफ़ हो जाता है कि उसके अफ्रीकी निवेश और सरकारी मदद केवल दोहन के लिए नहीं, बल्कि अफ्रीका के विकास और समृद्धि के लिए भी हैं. इसीलिए भारत ने अफ्रीकी देशों में मूल ढांचे और मानव संसाधन के विकास के लिए निवेश किए हैं, जबकि चीन के अफ्रीकी निवेश केवल व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र तक ही सीमित रहे हैं. भले ही चीन के 127 बिलियन डॉलर के मुकाबले भारत का 25 बिलियन डॉलर का निवेश नगण्य है, लेकिन दोनों के बीच का फर्क अफ्रीकी देशों को साफ़–साफ़ दिख रहा है, इस वजह से भारत व अफ्रीका और करीब आए हैं. भारत भले ही चीन से पिछड़ गया हो, लेकिन अब एक नई अफ्रीका नीति बनती नज़र आ रही है. अफ्रीका विश्व का सबसे अधिक खनिज संपदा वाला महाद्वीप है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वहां पर कभी न तो सरकारें ही ऐसी बन पाईं और न लोगों के पास इतना धन इकठ्ठा हो पाया कि इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन संभव हो पाता. इसका प्रमुख कारण यह रहा कि बहुत सारे अफ्रीकी देश पश्चिमी देशों के गुलाम रहे या फिर उनकी अपनी राजनीति में फंसकर रह गए. कुल मिलाकर पश्चिमी देशों ने अपने हितों के लिए अफ्रीकी देशों का दोहन किया. यही इन देशों में राजनीतिक सत्ता के टूटने का भी कारण बना. मिस्र हो या आइवरी कोस्ट, वे सभी देश, जो इस महाद्वीप में अग्रणी थे, को पश्चिमी देशों ने अपना शिकार बनाया. यही गुलामी का इतिहास ही अफ्रीका और भारत को एक–दूसरे का दोस्त बनाता है.

भारत ने अफ्रीका के लिए इस सम्मेलन के दौरान 5 बिलियन डॉलर अनुदान निश्चित किया है, जिसे अगले तीन सालों में दिया जाएगा. यह पैसा खासकर विकास कार्यों के लिए दिया गया है. साथ ही 700 मिलियन डॉलर का कर्ज शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दिया गया है. भारत ने एक बिजनेस काउंसिल भी बनाई है, जो अफ्रीका में पैसा लगाने वाले पूंजीपतियों का कामकाज देखेगी. भले ही देर से, मगर भारत भी यह समझ गया है कि जिस तरह अमेरिका और पश्चिमी देशों के बाद वह और चीन जैसे देश विश्व पटल पर विकास के नए इंजन बनकर उभरे, उसी तरह आगामी दशकों में अफ्रीका विश्व का नया आर्थिक केंद्र बनकर उभरेगा, क्योंकि आज उसके सामने सारी संभावनाएं खुली हुई हैं. इसी कारण भारत विकास की इस नई धारा का पूरा लाभ उठाना चाहता है, जो उसके अपने विकास के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा. याद रखने की बात है कि विश्व की छह सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं अफ्रीका में हैं. वैसे भारत अपनी प्रतिक्रियावादी विदेश नीति के लिए ही जाना जाता है. ऐसा माना जाता है कि भारतीय विदेश नीति लचर है और चीन की पिछलग्गू है. जहां चीन जाता है, वहां भारत भी पहुंच जाता है. चीन के कुछ करने के बाद ही भारत के नीति निर्माताओं को समझ में आता है कि वे दौड़ में पीछे रह गए हैं. इसी वजह से आज भारत ने अफ्रीका में अपने क़दम जमाने में देर कर दी है. लेकिन देर आए, दुरुस्त आए.

feedback@chauthiduniya.com

दोस्ती की नींव

भारत और अफ्रीका की दोस्ती की नींव रखी थी महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू ने. वैसे मनमोहन सिंह की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता. दो दशक पहले मनमोहन सिंह साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल थे और तंजानिया के उप राष्ट्रपति जुलिअस नेरेरे के साथ काम करते थे. नेरेरे अफ्रीका में बहुत सम्मानित नेता थे. शायद उन संबंधों की वजह से मनमोहन सिंह भी अफ्रीका से संबंध सुधारने के लिए आतुर हैं और इसीलिए इस बार के भारत–अफ्रीका शिखर सम्मेलन के बाद वह इथिओपिया और तंजानिया की यात्रा पर गए.

मनमोहन सिंह और अफ्रीका

पहला भारत–अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2008 में नई दिल्ली में हुआ था. इसमें अफ्रीकन यूनियन के चुने हुए 14 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया था. लीबिया और मिस्र ने इसमें भाग नहीं लिया था. असल में भारत और अफ्रीका के बीच दोस्ती का आगाज़ हुआ था 2006 में, जब मनमोहन सिंह दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए थे महात्मा गांधी के सत्याग्रह की सौवीं सालगिरह मनाने. 2007 में मनमोहन सिंह नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए, जहां उन्हें इबसा सम्मेलन में हिस्सा लेना था. उसी साल नवंबर में मनमोहन सिंह एक बार फिर अफ्रीका यात्रा पर गए कंपाला में आयोजित राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग लेने.

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक–संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम–उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301 www.chauthiduniya.tv

बाबा की इस बात पर पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हैजे का प्रकोप इस तरह रुक सकता है. हैजे का प्रकोप आसपास के गांवों में बड़ी तेजी केसाथ बढ़ता जा रहा था.

बाबा का आशीर्वाद और रहस्य

एक समय साई बाबा ने लगभग दो सप्ताह से खाना-पीना छोड़ दिया था. लोग उनसे कारण पूछते तो वह केवल अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली उठाकर अपनी बड़ी-बड़ी आंखें फैलाकर आकाश की ओर देखने लगते. लोग उनके इस संकेत का अर्थ समझने की कोशिश करते, लेकिन नाकाम रहते. बस कभी-कभी उनके कांपते होंठों से इतना ही निकलता, महाकाल का मुख खुल चुका है, सब कुछ उसमें समा जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा, एक-एक करके सब चले जाएंगे. बाबा के मुंह से ऐसा सुनकर लोग भय के मारे कांप उठते. वे बाबा से पूछते, लेकिन बाबा मौन हो जाते. उनकी कांपती हुई उंगली आकाश की ओर उठती और वह लंबी सांस लेकर फटी-फटी आंखों से आकाश की ओर देखते रह जाते. गांव का वातावरण सहमा-सहमा सा रहने लगा था. प्रत्येक वृहस्पतिवार को साई बाबा की शोभायात्रा बड़ी धूमधाम से निकलती थी, लेकिन न जाने क्यों, लोगों के मन किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठते थे. बाबा की बातें सुनकर यदि किसी को सबसे ज़्यादा ख़ुशी हुई तो वह पंडित जी थे. वह इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि बाबा जो कहते हैं, वह सच होता है. उनकी भविष्यवाणी झूठी नहीं हो सकती. भविष्य में होने वाली घटनाओं को वह पहले ही जान लेते थे. अकाल, बाढ़ और महामारी ऐसी दैवी आपदाएं हैं, जो गांव के गांव बर्बाद करके रख देती हैं. उनका कोई इलाज नहीं है. लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं. शायद ऐसा ही कोई संकट शिरडी में आने वाला है. पंडित जी यह सोच-सोचकर मन में बहुत ख़ुश थे कि यदि महामारी फैली तो लोग उनके पास ही अपना इलाज कराने के लिए आएंगे, जिससे उन्हें अच्छी-खासी कमाई होगी, जबकि सारा गांव अनिष्ट की आशंका से चिंताग्रस्त था. वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी, बाढ़ के आसार नहीं थे. अच्छी बारिश होने के कारण फ़सलें अच्छी हुई थीं, इसलिए अकाल की गुंजाइश नहीं थी. यदि कोई आपदा आ सकती थी तो वह थी महामारी. यदि महामारी फैली तो पंडित जी का भाग्य खुल जाएगा. जबसे साई बाबा शिरडी में आए थे, पंडित जी की आमदनी ख़त्म सी हो गई थी. बाबा की धूनी की भभूत असाध्य से असाध्य रोगों का समूल नाश कर देती थी. इस वजह से रोगियों ने पंडित जी के पास जाना बंद कर दिया था. मंदिर में भी पूजा करने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही थी. केवल पांच-सात लोग ही ऐसे बचे थे, जो पूजा करने के लिए सुबह-शाम मंदिर आते थे. इसके अलावा शाम के समय प्रसाद के लालच में कुछ बच्चे भी मंदिर में इकट्ठे हो जाते थे. इस तरह मंदिर से होने वाली आमदनी भी नाममात्र की रह गई थी. पुरोहिताई का धंधा भी बस ले-देकर चल रहा था.

साई बाबा के प्रवचनों को सुनकर लोगों में कथा सुनने की रुचि भी जाती रही. वर्षा भी समय पर होती थी, इसलिए समय पर वर्षा कराने के बहाने प्रत्येक वर्ष होने वाला यज्ञ भी अब बंद हो गया था. भूत-प्रेत, ब्रह्मराक्षस तो बाबा के गांव में क़दम रखते ही पलायन कर गए थे. गांव में अब किसी भी तरह का उत्पात नहीं होता था. प्रत्येक घर में सुख-शांति का बसेरा था. आपस के लड़ाई-झगड़े भी अब बंद हो चुके थे. पंडित जी के पास कोई काम नहीं रह गया था. वह सारा दिन अपने घर में बेकार पड़े रहते थे. घर में पड़े-पड़े पंडित जी बहुत दु:खी हो गए थे. उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी होने लगी थी. बाबा बराबर चिंता में डूबे रहते थे, वह केवल आकाश की ओर देखते रहते और किसी से कुछ भी न बोलते. तभी आसपास के बीस कोस के इलाक़े में हैजा फैलने की ख़बर से शिरडी गांव में कोहराम मच गया. हैजा से लोग मरने लगे. पहले कुछ उल्टियां होतीं, दस्त होते और लोग मौत के मुंह में समा जाते. जब तक लोग रोग को समझ पाते, रोगी बिना दवा-दारू के ही भगवान के पास पहुंच जाता था. पंडित जी की सारी भाग-दौड़ व्यर्थ चली जाती. आसपास के गांवों में हैजा फैलने की ख़बर सुनकर शिरडी के लोग भी चिंतित हो उठे. वे सब इकट्ठा होकर साई बाबा के पास पहुंचे. बाबा...बाबा, आसपास के गांवों में हैजा तेजी से पैर पसारता जा रहा है. अब तो वह हमारे गांव की ओर भी बढ़ता आ रहा है. कहीं ऐसा न हो कि हमारा गांव भी इस महामारी की चपेट में आ जाए, शिष्यों ने डरते-डरते बाबा से कहा. बाबा कई सप्ताह से मौन थे. उन्होंने खाना-पीना छोड़ रखा था. सारे शिष्य और वाईजा मां उनसे मिन्नतें करके हार गए थे, लेकिन न तो बाबा ने खाना खाया और न किसी से कोई बातचीत ही की. लोगों की पुकार सुनकर बाबा ने एक गहरी ठंडी सांस छोड़ी और फिर आकाश की ओर पूर्ववत देखने लगे. मस्जिद में उपस्थित लोग भी उन लोगों के साथ साई बाबा के चेहरे को देखने लगे कि शायद बाबा इस महामारी से बचने का कोई उपाय बताएंगे. बाबा का चेहरा एकदम गंभीर पड़ गया. चिंता की लकीर उनके सलोने मुख पर स्पष्ट रूप से नज़र आ रही थी. ऐसा लगता था कि बाबा किसी गहरी चिंता में हैं और कुछ कर पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं. अचानक साई बाबा ने अपनी आंखें मूंद लीं और बोले, तुम लोग कल सुबह आना. मैं सब बताऊंगा. यह कहकर बाबा शांत हो गए. सब लोग चुपचाप उठकर अपने-अपने घर चले गए.

अगले दिन पौ फटते ही सब लोग द्वारिकामाई मस्जिद पहुंचे. उन्होंने देखा कि मस्जिद के दालान में बैठे साई बाबा चक्की में जौ पीस रहे थे और जौ का आटा चक्की के चारों तरफ़ फैला हुआ था. सब लोग चुपचाप खड़े साई बाबा को जौ पीसते हुए देखते रहे, लेकिन साई बाबा पूरी लगन के साथ जौ पीसे जा रहे थे. किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उनसे कुछ पूछ सके. कुछ देर बाद एक भक्त ने साहस जुटाया और आगे बढ़कर पूछा, बाबा, आप यह क्या कर रहे हैं?

महामारी भगाने की दवा बना रहा हूं, बाबा ने कहा.

यह दवा है? भक्त ने फिर पूछा.

बाबा ने कहा, हां, यह दवा है. इस आटे को एक कपड़े में भरकर ले जाओ और गांव की सीमा पर चारों ओर जहां-जहां तक महामारी फैली हो, इसे छिड़क आओ. परमात्मा ने चाहा तो इस गांव की सीमा में हैजा प्रवेश भी न कर पाएगा. शिष्यों ने एक झोली में सारा आटा भर लिया और साई बाबा की जय-जयकार करते हुए गांव की सीमा की ओर चल पड़े. दोपहर तक गांव के चारों ओर सीमा पर आटे से लकीर सी बना दी गई. इस प्रकार साई बाबा द्वारा पीसे गए आटे से सारा गांव बांध दिया गया. बाबा की इस बात पर पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हैजे का प्रकोप इस तरह रुक सकता है. हैजे का प्रकोप आसपास के गांवों में बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था. दस-पांच आदमी रोजाना मौत के मुंह में समाते जा रहे थे. चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था. बाबा की इस अनोखी दवा का समाचार आसपास के गांवों तक पहुंच गया. लोग दवा मांगने के लिए द्वारिकामाई मस्जिद आने लगे. बाबा, हमारे गांव में भी हैजा फैला है, हमारे ऊपर दया करके हमें भी दवा दीजिए. और भी लोग साई बाबा के पास पहुंच कर दयनीय स्वरों में कहने लगे, हमें भी दवा दे दो बाबा, हम पर भी अपनी दया करो, हमारा सारा गांव श्मशान बन गया है.

अरे, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जितनी दवा है, आपस में बांटकर ले जाओ और गांव के प्रत्येक घर में छिड़क दो. जो बीमार होगा, ठीक हो जाएगा और यह महामारी तुम्हारे गांव से भी भाग जाएगी, बाबा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा. आसपास के गांवों के लोग बाक़ी बची हुई दवा को बांटकर ले गए. बाबा की चक्की की घर्र-घर्र की आवाज़ फिर मस्जिद के गुंबदों और मीनारों को गुंजायमान करने लगी. आवाज़ जहां-जहां पहुंचती, वहां हैजे का नामोनिशान ही मिट जाता. रोगी इस तरह उठकर खड़े हो जाते, मानो बीमार ही न पड़े हों. दवा एकदम रामबाण के समान अपना काम कर रही थी. महामारी गधे के सींग की तरह ग़ायब होती जा रही थी. बाबा की दवा की कृपा से सैकड़ों घर उजड़ने से बच गए. हर तरफ़ बस साई बाबा की जय-जयकार के स्वर ही सुनाई पड़ रहे थे. बाबा की कृपा से सबसे अधिक नुक़सान यदि किसी का हुआ तो वह थे पंडित जी. उन्हें कोई भी नहीं पूछ रहा था. महामारी फैली, पर उनके दवाखाने में एक भी आदमी दवा लेने नही आया. पंडित जी साई बाबा से जले-भुने बैठे थे. बाबा उन्हें गांव में ऐसे खटक रहे थे, जैसे आंख में तिनका. पंडित जी दिन-रात इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि किस तरह बाबा को नीचा दिखाकर शिरडी से निकाल भगाया जाए. वह अपने मन में बराबर उनके लिए नई-नई योजनाएं बना रहे थे, पर उनकी सारी योजनाएं अमल में लाने पर असफल होकर रह जाती थीं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

बाबा की बातें सुनकर यदि किसी को सबसे ज़्यादा ख़ुशी हुई तो वह पंडित जी थे. वह इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि बाबा जो कहते हैं, वह सच होता है. उनकी भविष्यवाणी झूठी नहीं हो सकती. भविष्य में होने वाली घटनाओं को वह पहले ही जान लेते थे. अकाल, बाढ़ और महामारी ऐसी दैवी आपदाएं हैं, जो गांव के गांव बर्बाद करके रख देती हैं. उनका कोई इलाज नहीं है. लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं. शायद ऐसा ही कोई संकट शिरडी में आने वाला है. पंडित जी यह सोच-सोचकर मन में बहुत ख़ुश थे कि यदि महामारी फैली तो लोग उनके पास ही अपना इलाज कराने के लिए आएंगे, जिससे उन्हें अच्छी-खासी कमाई होगी, जबकि सारा गांव अनिष्ट की आशंका से चिंताग्रस्त था.

धनाढ्य और असरदार महिलाओं से संबंध रखना भी हुसैन की शख्सियत का एक पहलू रहा, लेकिन जीवन भर वह अपनी पत्नी के वफ़ादार रहे.

अनंत विजय

बिहार में सांस्कृतिक क्रांति

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी मशहूर किताब संस्कृति के चार अध्याय में कहा है कि विद्रोह, क्रांति या बग़ावत कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसका विस्फोट अचानक होता है. घाव भी फूटने के पहले बहुत दिनों तक पकता रहता है. दिनकर जी की ये पंक्तियां उनके अपने गृहराज्य पर भी पूरी तरह से लागू होती हैं. बिहार में लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के तक़रीबन डेढ़ दशक के शासनकाल में सूबे की सारी संस्थाएं एक–एक कर नष्ट होती चली गईं या फिर प्रयास पूर्वक उनको बर्बाद कर दिया गया. जो बिहार एक जमाने में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में विश्व में मशहूर था, जहां नालंदा विश्वविद्यालय जैसे उच्च कोटि के शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, उन पंद्रह सालों के दौरान सब कुछ ख़त्म सा हो गया. जिस बिहार में कला–संस्कृति की एक समृद्ध परंपरा थी वहां कला संस्कृति मज़ाक बनकर रह गई. जो सूबा शिक्षा का अप्रतिम केंद्र हुआ करता था, वहां से हर साल उच्च शिक्षा के लिए हज़ारों छात्र पलायन कर दिल्ली और अन्य शहरों का रुख़ करने लगे. जिस सूबे में ज्ञान की गंगा बहा करती थी, वहां अपराध और रंगदारी का बोलबाला हो गया. राज्य के संवैधानिक मुखिया होने के नाते यह सारी ज़िम्मेदारी लालू–राबड़ी की बनती है कि उन्होंने बिहारी गौरव को बिहारी गाली में तब्दील कर दिया. लालू यादव का फूहड़पन और उनके रिश्तेदारों के रंगदारी के किस्सों पर फिल्में बननी लगीं और उन फिल्मों के अहम किरदारों में आपको उन लोगों की झलक साफ तौर पर दिखाई देने लगी. बिहारी शब्द हास्य और व्यंग्य का प्रतीक बन गया. लेकिन जैसा कि दिनकर जी ने लिखा है कि विद्रोह, क्रांति या बग़ावत कोई ऐसी चीज नहीं कि उसका विस्फोट अचानक होता है. उसी तरह जनता के गुस्से का विस्फोट होने में सालों लग गए. बिहार की जनता ने समझदारी दिखाते हुए सूबे में सरकार बदल दी. पहले तो कुछ अंदेशे के साथ, लेकिन दूसरी बार जब भरोसा हो गया तो प्रचंड बहुमत के साथ. इस प्रचंड बहुमत के साथ ही जनता की आशाएं और आकांक्षाएं भी सातवें आसमान पर जा पहुंची हैं.

यह वर्ष बिहार राज्य की स्थापना के सौवें वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. राज्य की नीतीश सरकार ने साल भर के कई कार्यक्रम बनाए हैं, जिनमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गोष्ठी–सेमिनार तो हैं ही, उसके अलावा कई पुस्तकों का प्रकाशन और सांस्कृतिक रूप से लुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण का काम भी शुरू किया गया है. इस काम में बिहार का कला–संस्कृति मंत्रालय बेहद शिद्दत से जुटा है. इसी कड़ी में मंत्रालय ने बिहार विहार नाम से एक कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन किया है. इस किताब में बिहार की कला–संस्कृति एवं युवा विभाग की मंत्री सुखदा पांडे ने मर्म पर चोट की है मैकाले के हवाले से उन्होंने लिखा है, हिंदुस्तानी यदि अपने सांस्कृतिक और वैचारिक इतिहास को जान जाएं तो हम उनको गुलाम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें उनके इतिहास को नहीं जानने दो. बिहार में तक़रीबन डेढ़ दशकों में यही हुआ. बिहार की नई पीढ़ी को उसकी संस्कृति और वैचारिक इतिहास की जानकारी से वंचित रखने का षड्यंत्र रचा जाता रहा और प्रयासपूर्वक ऐसा किया भी गया, लेकिन अब सुखदा पांडे के नेतृत्व में बिहार का यह मंत्रालय मैकाले के इन सिद्धांतों को झुठलाने में लगा है. सुखदा पांडे शिक्षण कार्य से जुड़ी रही हैं और उनसे यह उम्मीद भी की जा सकती है कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में बिहार के गौरव को वापस लाने में वह महती भूमिका निभाएंगी.

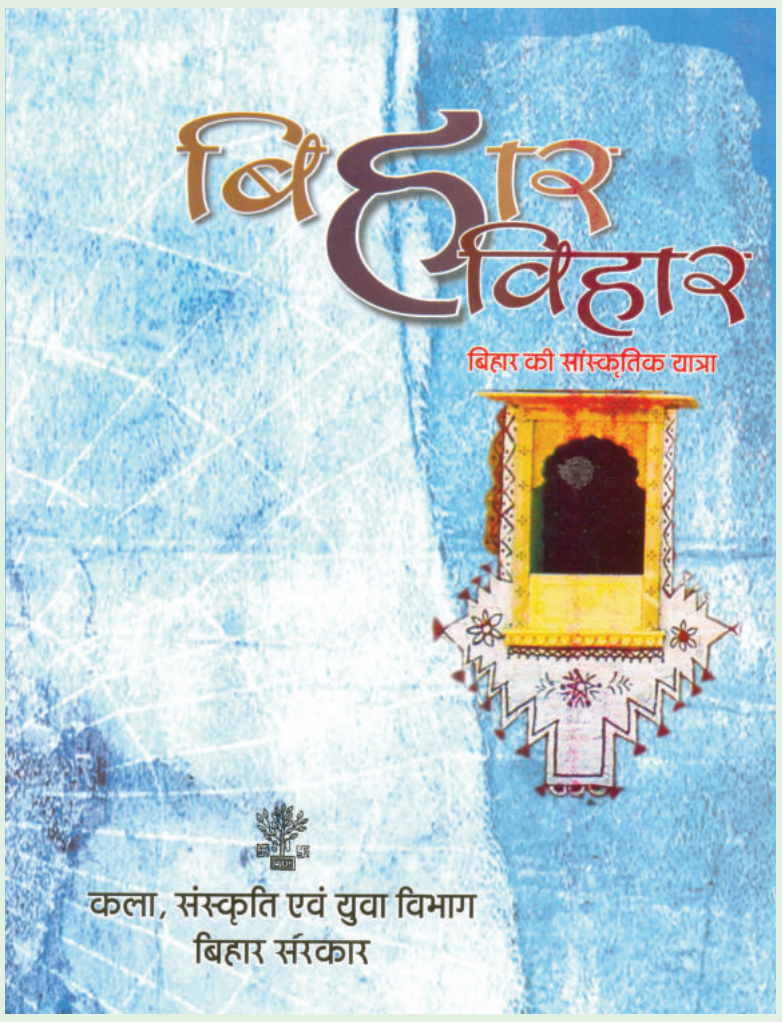

बिहार के गौरवशाली इतिहास को सामने लाने के लिए कला–संस्कृति मंत्रालय ने एक किताब बिहार विहार छापी है. इस किताब का संपादन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त लेखक विनोद अनुपम ने किया है. विनोद अनुपम ने अपने संपादकीय में बिहार के होने की पीड़ा से ही शुरुआत की है कि किस तरह से जब वह 1992 में फिल्म एप्रिशिएशन का कोर्स करने के लिए पुणे गए थे तो उनके साथ के लोगों को इस बात का आश्चर्य होता था और वे व्यंग्यात्मक लहज़े में पूछते थे कि कैसा है आपका बिहार? विनोद अनुपम के मुताबिक़, अब बदलते वक़्त में भी लोग बिहार के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन अब वे लोग बिहार के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, बिहार में हो रहे नवीनतम बदलाव के बारे में जानना चाहते हैं. जनता वह सब कुछ जानना चाहती है, जो शायद हम भी नहीं जानते. शायद इसलिए कि उसे पता है कि बदलाव की इबारत बिहार से ही लिखी जानी है, देश में भविष्य की रोशनी बिहार से ही आनी है. बिहार को क़रीब से जानने की इसी क्षुधा की पूर्ति की छोटी सी कोशिश है बिहार विहार. दरअसल, इस कॉफी टेबल बुक से बिहार की संस्कृति और समृद्ध लोक कलाओं की एक छोटी सी झलक भर ही मिलती है. संकेत मिलते हैं कि हमारे बिहार की कला परंपराएं कितनी समृद्ध रही हैं. बिहार का होने के बावजूद इस किताब को पढ़ने के बाद मेरी जानकारी में भी ज़बरदस्त इज़ाफ़ा हुआ. इस किताब से भी एक दिलचस्प प्रसंग जुड़ा है. विनोद अनुपम ने जब फोन पर मुझे कहा कि बिहार की कला संस्कृति पर वह बिहार सरकार की तरफ़ से प्रकाशित होने वाली कॉफी टेबल बुक का संपादन कर रहे हैं तो मुझे लगा था कि वह मज़ाक कर रहे हैं. पहले तो मुझे लगा था कि सरकार की कला–संस्कृति में क्यों दिलचस्पी होगी और उस पर कॉफी टेबल बुक. जब भी हमारी बातचीत होती थी तो विनोद अनुपम उसके बारे में बताते थे, लेकिन हर बार मैं सोचता था कि वह दिवास्वप्न देख रहे हैं और मैं सपने तोड़ने में यक़ीन नहीं रखता हूं. इस वजह से उनको कुछ कहता नहीं था, लेकिन कालांतर में पता चला कि बिहार विहार का जो सपना था और जिसे मैं दिवास्वप्न सोच–समझ रहा था, दरअसल वह हक़ीक़त था और सपना पूरा भी हुआ.

कॉफी टेबल बुक की योजना के बारे में विवेक कुमार सिंह ने अपनी पूर्व पीठिका में लिखा है, देश–विदेश में घूमते हुए मुझे कॉफी टेबल बुक की उपयोगिता का एहसास हुआ. विषय विशेष में रुचि जगाने के लिए कॉफी टेबल बुक हमेशा से एक बेहतर माध्यम रही है. यह विषय की विस्तार से जानकारी भले ही न दे, उसके प्रति दिलचस्पी अवश्य जगाती है. बिहार विहार की परिकल्पना बिहार के प्रति दुनिया की दिलचस्पी जगाने के लिए ही की गई है. विवेक कुमार सिंह को नज़दीक से जानने वाले यह बताते हैं कि इस प्रशासनिक अधिकारी ने बिहार में कला–संस्कृति के विकास के लिए बहुत कार्य किए और कई मृतप्राय संस्थाओं में नई जान फूंक दी थी. लेकिन कॉफी टेबल बुक की उपयोगिता उसकी उपलब्धता पर भी निर्भर करती है. अगर बिहार सरकार सिर्फ़ किताब छाप कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेगी तो इसका उद्देश्य पराजित हो जाएगा. ज़रूरत इस बात की है कि इस किताब को उन ख़ास लोगों तक पहुंचाया जाए, जहां से किसी भी सूबे की छवि निर्मित होती है. अन्यथा यह किताब भी अन्य सरकारी प्रकाशनों की तरह गोदाम में धूल फांक रही होगी और इसके प्रकाशन से जुड़े लोग अपनी पीठ थपथपा रहे होंगे.

इस किताब में बेहद श्रमपूर्वक सामग्री का चयन किया गया है, लेकिन इसमें जो चित्र लगे हैं, वे इस किताब की कमज़ोरी हैं. हो सकता है, वक़्त की कमी के चलते ऐसा हुआ हो या फिर कोई और कारण रहे हों, लेकिन सामग्री के हिसाब से चित्रण कमज़ोर है, चाहे वे रामलीला के पहले के चित्र हों या राजाओं के. लेकिन हमें इस प्रयास की सराहना करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की और सामग्री सामने आए. कमज़ोरियां तो दूर हो ही जाती हैं. बस जैसा कि मैंने ऊपर भी कहा कि इसे टारगेट पाठक वर्ग तक पहुंचाने का काम होना चाहिए.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

मक़बूल फ़िदा हुसैन
ख़त्म क़िस्सा हो गया

इक़बाल रिज़वी

लंदन में मशहूर चित्रकार मक़बूल फ़िदा हुसैन के निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया. आज तो भारतीय चित्रकारों का काम करोड़ों में बिक रहा है, लेकिन आठवें दशक में दुनिया की सबसे बड़ी नीलामी संस्थाओं सॉदबी और क्रिस्टीज़ से भारतीय आधुनिक कला का परिचय हुसैन ने ही कराया था. और वहीं से शुरू हुआ भारतीय कलाकारों का लखपति और फिर करोड़पति बनने का सिलसिला. फिल्मी होर्डिंग पेंट कर शुरुआत करने वाले हुसैन की कला की ख़ासियत यह रही कि वह किसी भी बड़ी घटना पर पेंटिंग के ज़रिए फ़ौरन प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते थे. चांद पर पहली बार इंसान पहुंचा हो या फिर 1971 के भारत–पाक युद्ध में इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए फ़ैसले हों या फिर मदर टेरेसा को नोबल पुरस्कार मिलने की घटना, हुसैन ने इन पर तत्काल पेंटिंग बनाकर प्रशंसा और आलोचना दोनों हासिल कीं. महाराष्ट्र के पंढरपुर इलाक़े में 17 सितंबर, 1915 को जन्मे और इंदौर में पले–बढ़े हुसैन ने जीवन में कड़ा

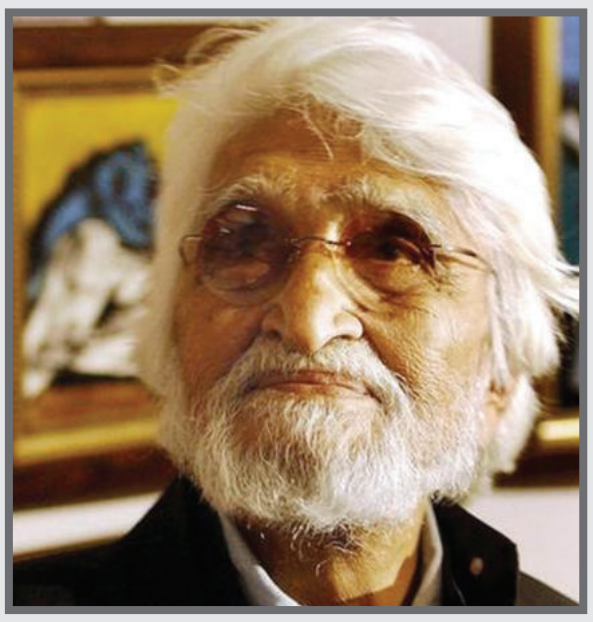

संघर्ष किया. उन्होंने मुंबई में रोज़ी–रोटी कमाने के लिए फ़िल्मी होर्डिंग्स बनाए, लेकिन उन्हें जो अच्छा लगता था, उसे वह खाली समय में काग़ज़ पर उतारा करते थे. हमेशा अपनी जेब में पेंसिल और रंगों का डिब्बा रखकर घूमने वाले हुसैन की पेंटिंग्स ने उनके समकालीन पेंटर सूज़ा को बहुत प्रभावित किया और फिर सूज़ा ने हुसैन, रज़ा एवं आरा जैसे युवा चित्रकारों का दल बनाया. प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप नामक इस दल ने भारतीय आधुनिक कला की बुनियाद मज़बूत की. अपने जीवन में ही किवदंती बन चुके, नंगे पैर रहने वाले हुसैन का कला के प्रति नज़रिया सबसे जुदा था. वह कला को स्टूडियो और आर्ट गैलरियों से बाहर ले गए. समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के सुझाव पर हुसैन ने रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित विशाल पेंटिंग्स की सीरीज बनाकर उन्हें बैलगाड़ियों में रख गांव–गांव प्रदर्शित किया. वहीं से हुसैन और आलोचना का चोली–दामन का रिश्ता बन गया.

गायन की विशेषता, उल्लास या अवसाद को चित्र में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हुसैन ने यह भी कर दिखाया. एक कार्यक्रम में पंडित भीमसेन जोशी जब अपने गायन का हुनर दिखा रहे थे तो सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हुसैन ने उनके गायन के साथ कैनवस पर रंगों और रेखाओं से जुगलबंदी करके सबको हैरत में डाल दिया. मुंबई में अपनी कार पर चित्र बनाकर उसका प्रदर्शन करना, शादी के कार्ड, विज़िटिंग कार्ड और बुक कवर डिज़ाइन कर देना, फ़र्नीचर और खिलौने डिज़ाइन करना, अपनी पेंटिंग को साड़ियों पर चित्रित कर देना, सिगरेट की डिब्बी पर तत्काल चित्र बनाकर किसी परिचित को भेंट कर देना, होटल, रेस्टोरेंट या पान के खोखे पर पेंटिंग बना देना, भव्य बिल्डिंगों पर म्यूरल बना देना और युवा कलाकारों की पेंटिंग ख़रीद लेना, ये वे सारे काम थे, जो हुसैन करते रहते थे और उनकी ओर प्रशंसा के फूलों के साथ–साथ आलोचना के पत्थर भी उछलते रहते थे. हुसैन कला सिर्फ़ कला के लिए वाली अवधारणा को नहीं मानते थे. उनका कहना था, ज़रूरी नहीं कि कलाकार किसी मुद्दे पर आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन समाज के प्रति उसकी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही तो होती ही है. साथ ही वह कला के लिए ख़ास माहौल जैसी चीज़ अवधारणा को भी नहीं स्वीकार करते थे. उनके मुताबिक़, अगर किसी भी तरह की सुविधा नहीं है तो कोयले से दीवार या ज़मीन पर भी चित्र बनाया जा सकता है. बीसवीं शताब्दी में दुनिया में पिकासो के बाद सबसे चर्चित कलाकार हुसैन ही रहे.

धनाढ्य और असरदार महिलाओं से संबंध रखना भी हुसैन की शख्सियत का एक पहलू रहा, लेकिन जीवन भर वह अपनी पत्नी के वफ़ादार रहे. अपने छह बच्चों में से उन्होंने किसी को भी कलाकार बनने के लिए प्रेरित नहीं किया. उनके बड़े बेटे शमशाद ने जब कला में रुचि दिखाई तो उन्होंने कहा कि पूरे देश में घूमो और हर माध्यम से चित्र बनाने का अभ्यास करो. अगर काम में दम हुआ तो लोगों में तुम्हारी पहचान ज़रूर बनेगी. इसी तरह छोटे बेटे उवैस के पेंटर बनने पर न तो उन्होंने आपत्ति की और न अपनी ओर से उवैस को कला जगत में स्थापित करने की कोशिश की. पेंटिंग ने हुसैन की पहचान बनाई, लेकिन हुसैन को पेंटिंग से भी ज़्यादा दिलचस्पी रही फ़िल्मों में. 1967 में उनकी बनाई एक प्रयोगात्मक फ़िल्म थ्रू द आइज़ ऑफ़ अ पेंटर ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय शोहरत दिलवाई. इसके बाद हुसैन ने कुछ डाक्यूमेंट्री फ़िल्में भी बनाईं. फिर हुसैन ने माधुरी दीक्षित को लेकर गजगामिनी बनाई. तब्बू और कुणाल कपूर स्टारर मीनाक्षी उनकी अंतिम फ़िल्म थी. हालांकि कुछ दिनों से चर्चा थी कि वह विद्या बालन को लेकर फ़िल्म बनाना चाह रहे हैं. पेंटिंग और सिनेमा के अलावा हुसैन की दिलचस्पी कविता में भी थी. उन्होंने अंग्रेज़ी और उर्दू में कविताएं तो लिखी हीं, उर्दू शायरों के हज़ारों शेर हुसैन को याद थे. ग़ालिब, जोश और इक़बाल के कई शेर हुसैन की पेंटिंग का हिस्सा भी बने.

1996 में हुसैन की पेंटिंग्स पर हिंदू देवी–देवताओं को अपमानित करने का आरोप लगा और एक सुनियोजित मुहिम के ज़रिए पूरे देश में हुसैन के ख़िलाफ़ ऐसा माहौल बनाया गया कि कई स्थानों पर हुसैन की पेंटिंग जलाई गई. उनके पक्ष में बोलने वालों के साथ दुर्व्यवहार किया गया. हुसैन के ख़िलाफ़ क़रीब 1000 मुक़दमे दर्ज कराए गए. 2006 से हुसैन निर्वासित जीवन बिताने पर मजबूर हो गए. साल भर पहले उन्होंने दुबई की नागरिकता ले ली और अपना ज़्यादातर समय वह दुबई और लंदन में बिता रहे थे.

feedback@chauthiduniya.com

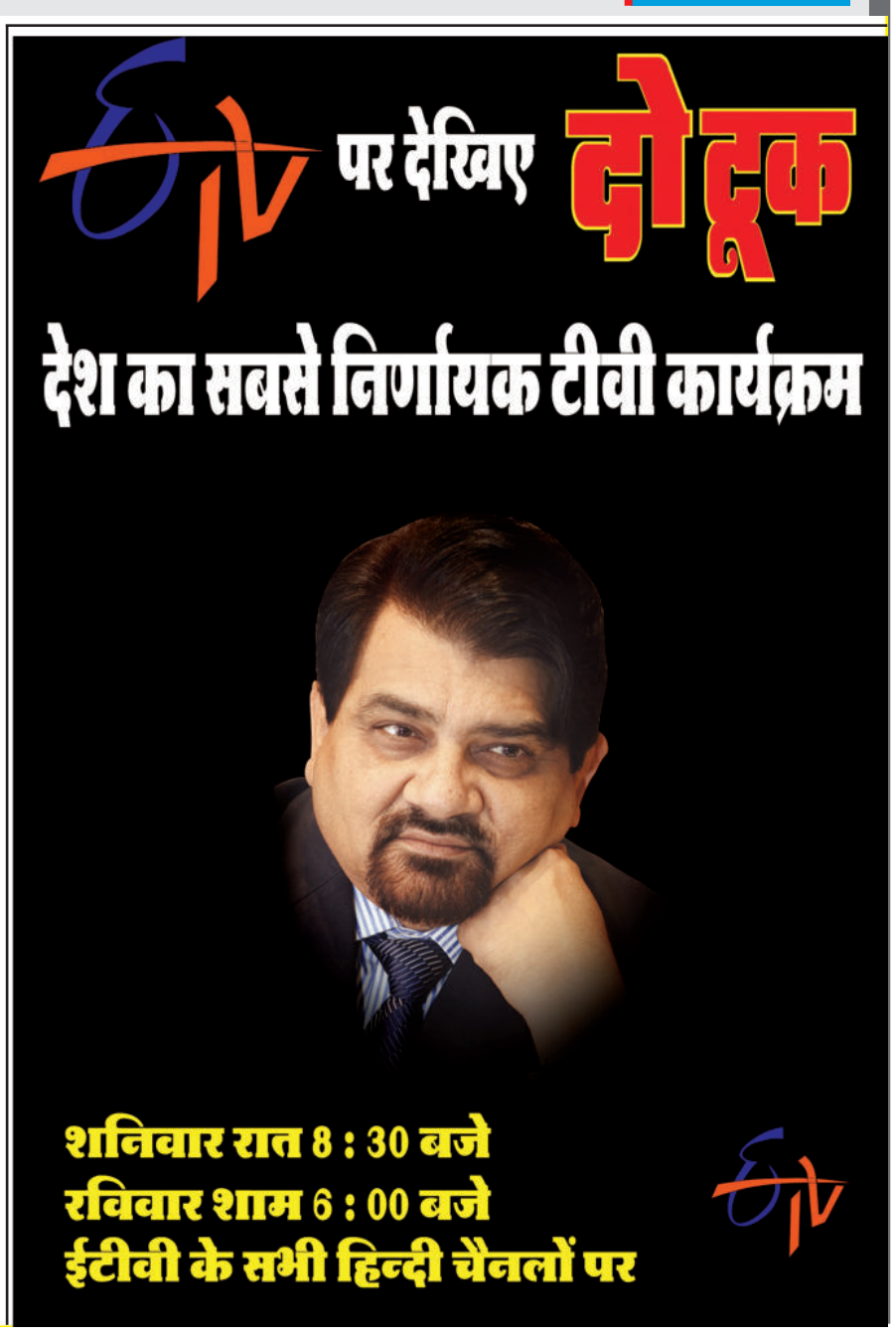

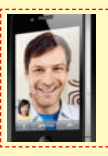

आईफोन-4 के 16 जीबी वाले मॉडल की कीमत 34,500 रुपये रखी गई है. वहीं इसका 32 जीबी मेमोरी वाला मॉडल 40,900 रुपये में उपलब्ध है.

ब्लैकबेरी का नया प्लेबुक टेबलेट

टेबलेट के क्षेत्र में बाजार पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा जमाने की होड़ में कंपनियां रोज नए-नए उत्पाद लांच कर रही हैं. इसी श्रेणी में अब ब्लैकबेरी ने भी नया प्लेबुक वाईफाई टेबलेट लांच करने की घोषणा की है. इसमें एक गीगाहर्ट्ज डुअल कोर प्रोसेसर लगाया गया है. साथ ही 3 मेगा फिक्सल और 5 मेगा पिक्सल का कैमरा भी है. एचडी मल्टीमीडिया के साथ ही सिक्योरिटी फीचर्स इसमें मौजूद हैं. इसमें एक जीबी की रैम मेमोरी, जीपीएस, ओरिएंटेशन सेंसर और 6 एक्सिस मोशन सेंसर भी लगाए गए हैं. इसमें ब्लूटूथ एड्रेस बुक, एचडीएमआई आउटपुट और स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं. यह टेबलेट जल्द ही लांच किया जाएगा.

क्वालकॉम का नया विंडो

क्वालकॉम ने माइक्रोसाफ्ट के साथ मिलकर विंडो का नया वर्जन बाजार में उतारने की घोषणा की है. यह नया वर्जन 2012 में बाजार में आ जाने की संभावना है.

आपके पर्सनल कंप्यूटर में बहुत जल्द होगा बिल्कुल नया विंडो. यह विंडो माइक्रोसॉफ्ट के उन दूसरे विंडोज की तरह नहीं होगा, जिन्हें थोड़ा-बहुत अंतर करके बाजार में पेश कर दिया जाता है, बल्कि यह होगा बेहद खास. दरअसल क्वालकॉम ने माइक्रोसाफ्ट के साथ मिलकर विंडो का नया वर्जन बाजार में उतारने की घोषणा की है. यह नया वर्जन 2012 में बाजार में आ जाने की संभावना है. इसमें जीएलटीई मोडम का प्रयोग किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि यह पहली बार हो रहा है, जब किसी विंडो वर्जन में पावर डिवाइस का प्रयोग किया गया है. कंपनी का यह भी कहना है कि इससे कंप्यूटर और मोबाइल केक्षेत्र में नई प्रगति होगी. इसमें प्रयोग किया गया स्नेपड्रेगन प्रोसेसर मोबाइल और कंप्यूटर को ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने में मदद करेगा.

आ गया आईफोन-4

अगर आप एप्पल आईफोन का लेटेस्ट मॉडल आईफोन-4 खरीदना चाहते हैं तो अब आपका यह इंतजार खत्म हो चुका है. देश में मोबाइल सर्विस देने वाली सबसे बड़ी कंपनी एयरटेल ने भारत में इसे लांच कर दिया है. आईफोन-4 के 16 जीबी वाले मॉडल की कीमत 34,500 रुपये रखी गई है. वहीं इसका 32 जीबी मेमोरी वाला मॉडल 40,900 रुपये में उपलब्ध है. कंपनी का कहना है कि भारत के 34 शहरों में एयरटेल के आउटलेट्स पर आईफोन-4 ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. मोबाइल सेवा देने वाली दूसरी बड़ी कंपनी एयरसेल ने भी ऐलान किया है कि आईफोन-4 उसके स्टोरों पर भी उपलब्ध है. कंपनी ने इसके लिए दो सहज प्लान भी जारी किए हैं. आईफोन-4 को भारत में लांच करने से पहले कंपनी ने कहा था कि उसकी तरफ से देश भर के 13 मोबाइल सर्किलों में 3-जी सेवा शुरू की जा चुकी है. ऐसे में इस बेहतरीन हैंडसेट के जरिए 3-जी सेवा का वास्तविक मजा लिया जा सकता है. आईफोन का यह भारतीय मॉडल अमेरिकी मॉडल से बेहतर है, क्योंकि इसका स्क्रीन बेहतर है और इसकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा है. इस स्मार्ट फोन में 5 मेगा पिक्सल का कैमरा है और इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील से भी मजबूत मेटल से बनी है.

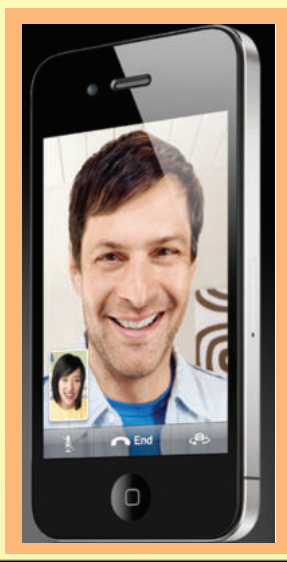

आईफोन-4 को भारत में लांच करने से पहले कंपनी ने कहा था कि उसकी तरफ से देश भर के 13 मोबाइल सर्किलों में 3-जी सेवा शुरू की जा चुकी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

डुअल बैंड वायरलेस

कंपनी का कहना है कि इस समय 2.5 गीगाहर्ट्ज में 450 सीरीज के जितने भी वायरलेस बाजार में उपलब्ध हैं, उनकी स्पीड केवल 300 एमबीपीएस है.

नेटगेर ने टीईडब्ल्यू-जीआर नामक डुअल बैंड वायरलेस लांच किया है. कंपनी का कहना है कि इस वायरलेस में 450 एमबीपीएस की स्पीड है. इसमें दो बैंड लगाए गए हैं, जिनमें से एक की फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी् -गीगाहर्ट्ज है. कंपनी का कहना है कि इस समय 2.5 गीगाहर्ट्ज में 450 सीरीज के जितने भी वायरलेस बाजार में उपलब्ध हैं, उनकी स्पीड केवल 300 एमबीपीएस है, लेकिन इस सीरीज में टीईडब्ल्यू-692 जीआर वायरलेस की स्पीड 450 एमबीपीएस है. इसे बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें वाईफाई प्रोटेक्टर भी लगाए गए हैं.

नोकिया का डुअल सिम फोन

दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी नोकिया ने दो शानदार फोन लांच करके बाज़ार में सनसनी फैला दी है. कंपनी इनके माध्यम से मिडिल क्लास ग्राहकों को अपनी ओर खींचना चाहती है और बाज़ार में अपनी घटती भागीदारी को संभालना भी चाहती है. नोकिया ने जो दो नए फोन लांच किए हैं, वे हैं, नोकिया सी 2-00 और म्यूजिक फोन एक्स 1-01. ये दोनों फोन ड्यूल सिम हैं और ऐसे फोनों की भारत में जबरदस्त मांग है. इस तरह के फोन माइक्रोमैक्स और स्पाइस ने बड़े पैमाने पर बाज़ार में उतार रखे हैं. नोकिया के सेल्स डायरेक्टर विपुल सब्बरवाल ने बताया कि कंपनी ग्राहकों के नजदीक आना चाहती है और इसलिए हमने ये उत्पाद पेश किए हैं. उन्होंने कहा कि ये दोनों मोबाइल बाज़ार में हंगामा कर देंगे. नोकिया का सी 2-00 एक ऐसा फोन है, जिसमें ग्राहक बिना किसी कठिनाई के सिम बदल सकता है. इसके लिए फोन ऑफ करने या बैट्री बदलने की जरूरत नहीं है. यह पांच सिम कार्ड की सेटिंग याद रख सकता है. इसकी कीमत महज 3,000 रुपये है. नोकिया के इन फोनों की खासियत है कि ये 36 घंटे तक बिना चार्ज हुए म्यूजिक सुना सकते हैं. नोकिया ने ये दोनों फोन राजधानी दिल्ली में पेश किए.

डोकोमो का 3 जी वाईफाई

docomo smartphone lounge

टाटा डोकोमो ने नया जी वाईफाई बाजार में उतारने की घोषणा की है. इसे लैपटॉप, टेबलेट्स एवं गेमिंग गैजेट्स के अलावा वाईफाई सुविधा वाले टीवी सेटों में भी लगाया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि यह टाटा डोकोमो के सभी नौ सर्किलों में काम करेगा. इसके साथ ही सर्किल से बाहर टाटा फोटोन पर सीडीएमए में इसका प्रयोग किया जा सकता है. जीएसएम पर इसकी स्पीड 7.2 एमबीपीएस और सीडीएमए पर 3.1 एमबीपीएस है. डोकोमो का यह वाईफाई पोस्टपेड प्लान में भी उपलब्ध होगा.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

आफ़रीदी की टीम में वापसी होती है या नहीं, यह तो बाद की बात रही, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए थे, जिससे लग रहा था कि आफ़रीदी को अपनी ग़लती का एहसास हो चुका है.

आफ़रीदी के इस्तीफ़े से उपजे सवाल

ए एन शिबली

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कब क्या हो सकता है, कहा नहीं जा सकता. कल तक टीम में जिस शाहिद आफ़रीदी की तूती बोलती थी, अचानक उस पर ऐसी आफ़त आ पड़ी कि उसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहना पड़ा. शाहिद आफ़रीदी, जिसे मैदान में गेंदबाज़ों की धुनाई के लिए जाना जाता था, की टीम में यह हैसियत हो गई कि उसे समय से पहले क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा. अगर इस मामले की गहराई में जाएं तो मालूम होता है कि आफ़रीदी ने यह क़दम इसलिए उठाया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें एक दिवसीय टीम की कप्तानी से हटा दिया, जिससे वह नाराज़ हुए और इसे अपना अपमान महसूस करने लगे. पाकिस्तानी क्रिकेट का इतिहास बताता है कि न तो यहां कभी खिलाड़ियों में आपसी मेलजोल हुआ और न ही कभी खिलाड़ी बोर्ड से ख़ुश रहे. इमरान ख़ान और जावेद मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास के दो बड़े स्टार रहे, लेकिन इनमें भी आपसी मतभेद रहे. जहां तक बोर्ड का सवाल है तो कोई खिलाड़ी अगर इससे ख़ुश रहा तो बोर्ड से नाराज़ खिलाड़ियों की कमी भी नहीं रही. कुछ खिलाड़ी तो ख़ुद को बोर्ड से ऊंचा भी मानते रहे. इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि शाहिद आफ़रीदी न केवल बोर्ड की हरकतों से नाराज़ हैं, बल्कि वह चाहते हैं कि बोर्ड अपने किए धरे पर शर्मिंदा हो और उनको मनाए. इसीलिए शाहिद आफ़रीदी ने इस्तीफ़े का ऐलान करते समय ज़ोर देकर कहा कि वह सिर्फ़ एक ही शर्त पर टीम में वापसी करेंगे, जब पीसीबी से घटिया क़िस्म के लोग हट जाएंगे.

आफ़रीदी की टीम में वापसी होती है या नहीं, यह तो बाद की बात रही, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए थे, जिससे लग रहा था कि आफ़रीदी को अपनी ग़लती का एहसास हो चुका है. दरअसल, शुरू में आफ़रीदी ने यह सोचा कि जब वह बोर्ड और अध्यक्ष एजाज़ बट्ट के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो उन्हें भारी समर्थन मिलेगा और लोग बोर्ड की हरकतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन बोर्ड ने आफ़रीदी की ऐसी हालत बना दी कि उनकी कमाई के सारे रास्ते बंद हो गए. जो आफ़रीदी संन्यास लेते समय बौखलाए नज़र आ रहे थे, वह नरम पड़ गए और बोर्ड से यह अपील करने को मजबूर हो गए कि कम से कम उन्हें काउंटी खेलने की इजाज़त दे दी जाए. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी और काउंटी में खेलने की उनकी अपील ठुकरा दी. आफ़रीदी इस बात से नाराज़ थे कि उनको बिना किसी विशेष कारण के कप्तानी से हटा दिया गया. बक़ौल आफ़रीदी, मेरी बोर्ड में कोई क़दर नहीं है. उसने मुझे कप्तानी से हटाने की न तो कोई वजह बताई और न मेरी बात सुनने की कोशिश की. मुझे नहीं मालूम कि किस बुनियाद पर और किस कारण मुझे हटाया गया. मैंने बिखरी हुई टीम को संवारने में मेहनत की और विश्वकप सेमी फाइनल में खेला और इसके बावजूद उन्होंने मेरी बात सुने बिना मुझे कप्तानी से हटा दिया. मालूम हो कि बोर्ड ने वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान की 2-3 से जीत के बावजूद आफ़रीदी को टीम की कप्तानी से हटा दिया. बोर्ड ने उन्हें हटाने का कोई कारण नहीं बताया, बल्कि कहा जा रहा है कि यह सब आफ़रीदी के कोच वक़ार यूनुस के साथ बढ़ते मतभेदों का नतीजा था. ख़ुद आफ़रीदी ने कहा कि लाहौर के पंजाब राज्य का एक ग्रुप है, जो हमेशा उनके ख़िलाफ़ रहता है. उन्होंने कहा कि यह ग्रुप हमेशा मेरे ख़िलाफ़ काम करता है. यह मेरे ख़िलाफ़ पीसीबी अध्यक्ष एजाज़ बट्ट के कान भरता रहता है, क्योंकि यह नहीं चाहता कि मैं खेलूं, क्योंकि मैं उसकी योजनाओं में बाधा बनता हूं. इस तरह के धमाके का अंदाज़ा आम क्रिकेट प्रेमियों को उसी वक़्त हो गया था, जब आफ़रीदी को आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच के लिए कप्तानी से हटा दिया गया था. कप्तानी से हटाए जाने के बाद उन्होंने बोर्ड से कहा कि वह अपने बीमार पिता के साथ समय बिताना चाहते हैं, जो अमेरिका में इलाज करा रहे हैं, लेकिन वह अमेरिका से इंग्लैंड पहुंच गए और वहीं लंदन से अपने संन्यास की घोषणा कर दी. आफ़रीदी कुछ भी कहें, लेकिन क्रिकेट के विशेषज्ञ आफ़रीदी की इस हरकत को उचित नहीं समझते. उनके अनुसार, बोर्ड को यह अधिकार है कि वह किसे कप्तान बनाए और किसे नहीं, आपका काम सिर्फ़ खेलना है और आपको हर हाल में देश के लिए खेलने को तैयार रहना चाहिए.

इस संबंध में पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ज़हीर अब्बास ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी. आज वह बोर्ड को दोषी ठहरा रहा है, लेकिन शायद वह भूल गया कि आस्ट्रेलिया में गेंद से छेड़छाड़ के विवाद के समय उसी बोर्ड ने उसका साथ दिया था, जबकि वह फॉर्म में भी नहीं था. पूर्व टेस्ट लीग स्पिनर एवं पूर्व मुख्य चयनकर्ता अब्दुल क़ादिर ने भी शाहिद आफ़रीदी के फ़ैसले को ग़लत ठहराते हुए कहा कि आजकल संन्यास की घोषणा करना मज़ाक सा बन गया है. हमारे खिलाड़ी नियमित रूप से ऐसा कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट को नुक़सान हो रहा है. पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट स्पिनर इक़बाल क़ासिम ने कहा कि आफ़रीदी के फ़ैसले से पाकिस्तानी क्रिकेट को नुक़सान ही होगा. वैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जो आफ़रीदी के फ़ैसले को उचित ठहरा रहे हैं. ऐसे लोगों का कहना है कि जिस कप्तान ने टीम को विश्वकप के सेमी फाइनल में पहुंचाया, उसके साथ बोर्ड को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए.

आफ़रीदी का फ़ैसला उचित है या नहीं, इस पर बहस आगे भी चलती रहेगी, लेकिन इतना तो तय है कि आफ़रीदी की गिनती पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में होती है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आफ़रीदी ने तेज़ बल्लेबाज़ी का एक शानदार नमूना पेश किया. अपने दूसरे ही मैच में उन्होंने सिर्फ़ 37 गेंदों पर शतक जड़ दिया. यह वन डे क्रिकेट की गेंदों की दृष्टि से आज भी सबसे तेज़ शतक है. शुरू से ही अपनी विस्फ़ोटक बल्लेबाज़ी के लिए मशहूर शाहिद आफ़रीदी बाद में बेहतरीन गेंदबाज़ी भी करने लगे. वह अब तक 325 एक दिवसीय मैचों में खेले हैं, जिनमें उन्होंने 6695 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 113.82 रहा. एक गेंदबाज़ के रूप में उन्होंने 34.22 के औसत से 315 विकेट भी लिए. शाहिद आफ़रीदी ने 43 टी-20 मैच भी खेले, जिनमें उन्होंने 683 रन बनाने के अलावा 53 विकेट भी लिए. आफ़रीदी को 27 टेस्ट मैचों में भी खेलने का मौक़ा मिला, जिनमें उन्होंने 1716 रन बनाए और गेंदबाज़ के तौर पर 48 विकेट लिए. आफ़रीदी की वापसी होगी या नहीं, इसका पता तो जल्द ही चल जाएगा. अगर उनकी वापसी नहीं होती है तो उनके तेज़ खेलने और किसी को आउट कर देने के बाद उनके ख़ुश होने का अंदाज़ हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा.

feedback@chauthiduniya.com

भारत की उम्मीदें फिर टूटीं

भारतीय मुक्केबाज़ों का क्यूबा के हवाना में चल रही गिराल्डो कोर्दोवा कार्डिन मेमोरियल मुक्केबाज़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका और उन्हें केवल एक रजत और पांच कांस्य पदकों के साथ संतोष करना पड़ा. भारत के छह मुक्केबाज़ सेमीफाइनल में पहुंचे थे लेकिन इनमें से कोई भी स्वर्ण पदक जीतने में सफल नहीं हो सका. पांच मुक्केबाज़ों की चुनौती तो सेमीफाइनल में ही दम तोड़ गई जबकि मनप्रीत सिंह 91 किग्रा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा. ग्वांगझू एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता मनप्रीत हमवतन और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता परमजीत समोटा को हराकर फाइनल में पहुंचे लेकिन चिकित्सा कारणों से वह फाइनल में नहीं खेल पाएंगे. इस तरह उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा. ननाओ सिंह (49 किग्रा) सुरंजय सिंह (52 किग्रा) संतोष हरिजन (52 किग्रा) कुलदीप सिंह (75 किग्रा) और परमजीत समोटा (91 किग्रा) को सेमीफाइनल में हार के कारण कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा. सुपर हैवीवेट वर्ग से हैवीवेट वर्ग में उतरे समोटा मनप्रीत की गति और सटीकता का सामना नहीं कर पाए. पहले राउंड के बाद समोटा एक अंक से पिछड़े हुए थे लेकिन मनप्रीत ने दूसरे राउंड की समाप्ति तक पांच अंकों की बढ़त बना ली. तीसरे राउंड में दोनों के बीच कड़ा मुक़ाबला हुआ लेकिन मनप्रीत 20-18 के क़रीबी अंतर से जीत दर्ज करने में सफल रहे. लाइट हैवीवेट वर्ग में एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता ननाओ सिंह को कजाकिस्तान के मूजापारोव के ख़िलाफ़ 22-57 से हार का सामना करना पड़ा. फलाई वेट वर्ग में संतोष हरिजन को क़रीबी मुक़ाबले में मेजबान क्यूबा के रामिरेज के हाथों 4-7 से हार का सामना करना पड़ा. फलाई वेट वर्ग के एक सेमीफाइनल में छोटा टायसन के नाम से मशहूर सुरंजय सिंह को ब्राजील के जे नेटो के हाथों 7-18 से शिकस्त का सामना करना पड़ा. एशियाई खेलों के बाद पहली बार किसी मुक़ाबले में खेल रहे सुरंजय ने हालांकि बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन किया, लेकिन वह ब्राजीली मुक्केबाज़ से पार नहीं पा सके. मिडल वेट वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन कुलदीप सिंह को डोमिनिका के कास्टिलो जूनियर ने 10-18 से हरा दिया. कुलदीप प्रतिद्वंद्वी मुक्केबाज़ के मज़बूत डिफेंस में सेंध लगाने में नाकाम रहे और उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 20 जून-26 जून 2011

विद्या उनके सामने अजब-ग़ज़ब हरकतें करने लगीं. यह देख सुजॉय ने घोषणा कर दी कि वह आज शूटिंग नहीं करेंगे.

नर्मदा के कोच सल्लू

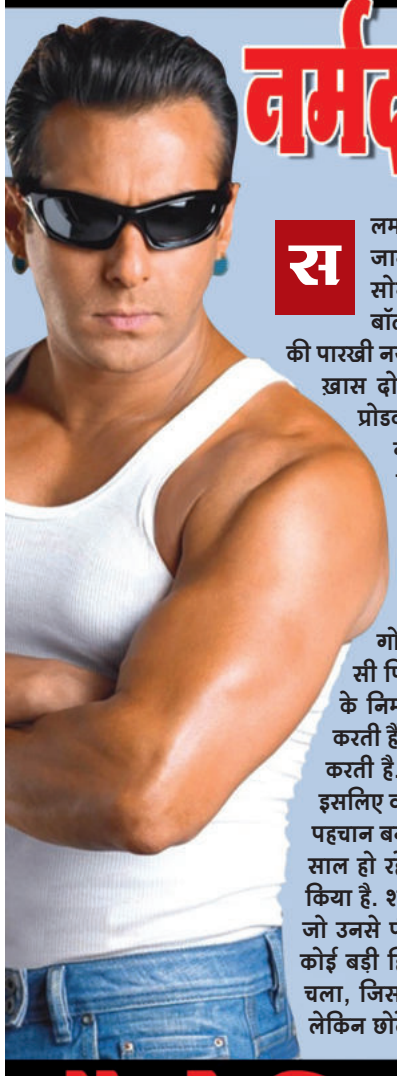

सलमान ख़ान बॉलीवुड में कई नए कलाकारों को लांच करने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने ही ज़रीन ख़ान, कैटरीना कैफ और हाल में सोनाक्षी सिन्हा को लांच किया. उनकी लगभग हर पसंद बॉलीवुड की पसंद बन जाती है. यही वजह है कि सलमान ख़ान की पारखी नज़र पर सबको भरोसा है. अब ख़बर आ रही है कि वह अपने ख़ास दोस्त गोविंदा की बेटी नर्मदा को जल्द ही अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म के माध्यम से लांच करेंगे. सलमान ख़ान और गोविंदा की दोस्ती के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन पिछले दिनों दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर ग़लतफ़हमी हो गई थी, लेकिन अब फिर से दोनों दोस्त बन गए हैं. सलमान ने अपना हाथ नर्मदा के सिर पर रख दिया है. वह उसका पूरा ध्यान रखते हुए हर तरह से गाइड कर रहे हैं और फिटनेस पर भी ध्यान देते हैं. सलमान ने गोविंदा से बहुत पहले वादा किया था कि वह नर्मदा को अच्छी सी फिल्म के साथ लांच करेंगे, लेकिन बीच में वह फिल्म दबंग के निर्माण में जुट गए थे. नर्मदा भी सलमान की बहुत इज़्ज़त करती हैं. उनके सारे टिप्स वह ध्यान से सुनती है और उन पर अमल करती है. सलमान कहते हैं कि नर्मदा एक बेहतरीन कलाकार है और इसलिए वह उसे सहयोग कर रहे हैं. उन्हें पूरा विश्वास है कि नर्मदा अपनी पहचान बना पाने में कामयाब होगी. गोविंदा को बॉलीवुड से जुड़े 25-30 साल हो रहे हैं, उनकी एक अलग पहचान है, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा किया है. शायद इसके पीछे कारण यह है कि उनके सामांतर जो नायक थे या जो उनसे पीछे थे, आज उनसे आगे निकल चुके हैं. गोविंदा ने लंबे समय से कोई बड़ी हिट नहीं दी है. राजनीति और टीवी दोनों जगह उनका सिक्का नहीं चला, जिससे परेशान होकर गोविंदा ने वह काम शुरू कर दिया, जो नवोदित, लेकिन छोटे कलाकार करते हैं.

विद्या हुई पियक्कड़

कभी-कभी कुछ गंभीर और डेडिकेटेड कलाकारों को भी न जाने क्या हो जाता है कि वे सेट पर बचकाना या मज़ाकिया व्यवहार करने लगते हैं. बेहतरीन एवं संजीदा किरदार निभाने वाली और रीयल लाइफ में भी समझदार विद्या बालन ने तो हद ही कर दी. सुजॉय घोष की फिल्म कहानी के सेट पर वह कुछ ऐसा कर गुजरीं कि सभी हैरान रह गए और सोच में पड़ गए कि आख़िर विद्या को हुआ क्या है. दरअसल, एक दिन जब सुजॉय फिल्म कहानी की शूटिंग के लिए आए तो उन्हें विद्या कुछ बदली- बदली नज़र आईं. यह बदलाव कोई छोटा बदलाव नहीं था, उस दिन विद्या ऐसे झूम रही थीं, जैसे शराब पीकर आई हों. यह देखकर सुजॉय तनाव में आ गए. वह जाकर एक कोने में बैठ गए. विद्या उनके सामने अजब-ग़ज़ब हरकतें करने लगीं. यह देख सुजॉय ने घोषणा कर दी कि वह आज शूटिंग नहीं करेंगे. थोड़ी देर बाद जब विद्या ने देखा कि मामला गंभीर होता जा रहा है तो उन्होंने बताया कि वह तो सिर्फ़ नशे में होने का नाटक कर रही थीं. विद्या ने सुजॉय को सॉरी कहा और फिर काम शुरू हुआ. सुजॉय ने नाराज़ होने के बजाय कहा कि विद्या आप शराबी लड़की का किरदार बहुत अच्छे ढंग से निभा सकती हैं. विद्या यह सुनकर ख़ुश हो गईं कि उन्हें इस किरदार में भी लोगों ने पसंद किया. प्रशंसकों, आप अपना दिल छोटा न करें, आपकी गुड्गर्ल विद्या ने कोई तमाशा नहीं किया. यह सिर्फ़ उनका एक मज़ाक था. विद्या सुजॉय की फिल्म में एक गर्भवती स्त्री की भूमिका निभा रही हैं.

क्या करें यूविका

सोशल नेटवर्किंग साइट कभी भलाई कर देती है तो कई बार बुरी भी साबित होती है, सिर्फ़ आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि सेलिब्रिटीज और फिल्मी सितारों के लिए भी. वर्ष 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम से अपना करियर शुरू करने वाली अभिनेत्री यूविका चौधरी को भी ख़ासी परेशानी झेलनी पड़ी. वजह है, देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाला जॉन नामक ब्रोकर. दरअसल, इस ब्रोकर ने उनकी जानकारी के बिना सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके नाम का अकाउंट खोलकर एक अश्लील पोस्ट कर दिया था. इस पोस्ट में लिखा गया था कि अगर कोई शख़्स यूविका को पांच लाख रुपये देगा तो वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगी. बस फिर क्या था, इस पोस्ट के बाद यूविका के पास फोन की झड़ियां लग गईं और ख़ुद यूविका बेहद हैरान-परेशान हो गईं. वह तो जॉन का पता लगाने में जुट गईं, क्योंकि लोग उन्हें फोन करके अश्लील बातें करने लगे थे. यूविका ने तो पुलिस की मदद लेने का भी विचार कर लिया. हालांकि यूविका को जितनी परेशानी होनी थी, उतनी हो गई. वैसे सितारों को सोशल नेटवर्किंग साइट से हुई परेशानी से ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वर्चुअल वर्ल्ड की ओपन स्ट्रीट है, जहां सितारे मौजूद रहते हैं अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, पर सभी चीजों के अपने साइड इफेक्ट भी होते हैं. ग़ौरतलब है कि यूविका चौधरी ने ओम शांति ओम, बात हमारी पक्की और नॉटी एट 40 में काम किया है. पहली दो फिल्मों में यूविका का किरदार बेहद सादगीपूर्ण था, वहीं नॉटी एट 40 एक सेक्स कॉमेडी आधारित फिल्म थी, जिसमें यूविका को काफी हॉट दिखाया गया था.

कैसे मिलेगी कामयाबी

जिया ने फिल्मों में भले ही ख़ास कमाल न दिखाया हो, लेकिन लगातार नाम बदलने में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बॉलीवुड में क़दम रखने से पहले अभिनेत्री जिया ख़ान को लोग नफीसा के नाम से जानते थे, मगर बॉलीवुड में क़दम रखते ही उन्होंने असल नाम नफीसा को बदल कर जिया ख़ान कर लिया. अब बताया जा रहा है कि जिया फिर अपना नाम बदलने के मूड में हैं. ख़ुद जिया ने पिछले दिनों ट्वीट किया है कि वह अपने मूल नाम का दोबारा इस्तेमाल करने जा रही हैं. जब जिया ने बॉलीवुड में क़दम रखा था, तब उनकी काफी चर्चा हुई थी, मगर उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी. इसलिए यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद जिया नाम बदल कर बॉलीवुड में अपनी क़िस्मत दोबारा आजमाना चाहती हैं. फ़िलहाल वह अपने परिवार के साथ लंदन में हैं. कुछ समय पहले वह फिल्म हाउसफुल में नज़र आई थीं. वहीं उनकी फिल्म निशब्द को भला कौन भुला सकता है. हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर ज़्यादा धमाल नहीं मचाया, लेकिन अपने हॉट सब्जेक्ट के लिए यह काफी चर्चा में रही. इसमें दिखाया गया कि एक 16 वर्षीय लड़की अपनी सहेली के पिता पर मर मिटती है और उससे शादी करना चाहती है. इस किरदार को पर्दे पर निभाया था अभिनेत्री जिया ख़ान ने, लेकिन उन्होंने रीयल लाइफ में भी ऐसा ही धमाका कर दिया है. ख़बर है कि जिया ने ख़ुद से लगभग 15 साल बड़े आदमी से शादी कर ली है, लेकिन उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है. वह कहती हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने कुछ न कुछ किया ज़रूर है. फ़िलहाल जिया के कथित पति का नाम उजागर नहीं हो पाया है. शादी की वजह से करियर में कोई बाधा न पहुंचे, इसलिए जिया इसे सीक्रेट ही रखना चाहती हैं.

कहां हैं डायना

बिग बॉस के बाद कहीं भी नज़र नहीं आईं डायना. दरअसल, बॉलीवुड में उनकी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है. वह बहुत सिंपल और डायरेक्ट पर्सन हैं, जो अपनी पसंद का काम करके ही ख़ुश होती हैं. उन्हें लेखन का काफी शौक है और इन दिनों वह यही काम कर रही हैं. उन्हें ख़ुशी है कि वह जो कर रही हैं, ठीक कर रही हैं. लेखन के अलावा वह चैरिटी और राइटिंग में बिज़ी हैं. पिछले दो सालों से वह महिलाओं की ग्रूमिंग पर एक किताब लिख रही हैं. उनकी इस किताब में मॉडल्स से लेकर आम महिलाओं तक के लिए मेकअप और अच्छी बॉडी से जुड़ी हर तरह की जानकारी होगी. अ ब्यूटीफुल ट्रुथ नामक उनकी यह किताब सितंबर में रिलीज होगी. इसके अलावा वह बॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं. वह टीवी कलाकार करण सिंह के साथ एक फिल्म में भी काम कर रही हैं, जिसका नाम लॉरी है. यह फिल्म भी सितंबर में ही रिलीज होने वाली है. यह एक रीयल स्टोरी पर आधारित है. डायना की इच्छा अमिताभ बच्चन के साथ काम करने की है. हालांकि उन्हें अजय देवगन, स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी, प्रीति जिंटा और जॉर्ज क्लूनी भी बेहद पसंद हैं. डायना कहती हैं कि वह स्टार कास्ट देखकर कोई फिल्म साइन नहीं करतीं. अगर स्क्रिप्ट दमदार है और उसमें उनके करने के लिए कुछ है तो वह उसे तुरंत साइन कर लेती हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

डबल धमाल

फिल्म डबल धमाल की झलक देखकर आपको आमिर की याद आएगी और शाहरुख की भी. शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग याद आएगा और बारबरा मोरी को भी आप नहीं भूल पाएंगे. फिल्म डबल धमाल इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित है. यह 2007 में आई फिल्म धमाल का सिक्वल है. फिल्म के कई पात्र पिछली फिल्म के ही हैं, हालांकि पिछली फिल्म में कोई भी अभिनेत्री नहीं थी, लेकिन इस बार डबल धमाल के लिए मल्लिका शेरावत और कंगना रानावत को लिया गया है. फिल्म आगामी 24 जून को रिलीज़ होगी. फिल्म की शूटिंग महबूब स्टूडियो, हांगकांग और मॉरीशस में हुई है. फिल्म में अरशद वारसी सिख घंटा सिंह की भूमिका में नज़र आएंगे और जावेद जाफरी फिर से उनके छोटे भाई की भूमिका निभाएंगे. वहीं रितेश देशमुख फिल्म में तीन रोल निभाएंगे. अनिल कपूर और आमिर ख़ान अतिथि भूमिका में नज़र आएंगे. फिल्म के मुख्य कलाकार संजय दत्त, मल्लिका शेरावत, कंगना रानावत, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी, रितेश देशमुख एवं सतीश कौशिक हैं.

अभिनेता जावेद जाफरी डबल धमाल के एक दृश्य की शूटिंग के दौरान घायल हो गए. उनके पैर में चोट आई है. जावेद के घायल होने के बाद निर्देशक इंद्र कुमार ने इस दृश्य में बदलाव कर दिया. जावेद ने धमाल में भी अभिनय किया था. वह महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, उसी दौरान उनका पैर जख्मी हो गया और उन्हें अस्पताल में दाख़िल होना पड़ा. निर्माता अशोक ठाकेरिया ने कहा कि फिल्म अपने अंतिम चरण में थी. जावेद बिस्तर पर कूदे और उनके घुटने में बुरी तरह चोट लग गई. उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया. कोई बड़ी चोट नहीं थी, लेकिन उन्हें काफी दर्द हो रहा था. जावेद ने दर्द के बावजूद शूटिंग पूरी करने की जिद की और दृश्य परिवर्तन के बाद उसे पूरा किया गया. टोरंटो में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईआईएफए) में इसका प्रीमियर भी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 20 जून–26 जून 2011

www.chauthiduniya.com

शराबियत ख़तरनाक बीमारी

सीमाएं टूट रही हैं

शराबियत तो ऐसी गंभीर बीमारी है कि इसमें किसी की सहानुभूति भी नहीं मिलती. यह रोग तेज़ी से फैल रहा है. इस रोग ने रोगी के साथ ही कई घर तबाह कर दिए हैं. शराबियत के असंख्य मरीज़ों के परिवार के लोग मानसिक रोग की चपेट में हैं. इस मामले में जागरूकता की कमी है

अंजीव पांडेय

शराब के सेवन के मामले में महाराष्ट्र अब सारी सीमाएं तोड़ रहा है. यहां ड्रग्स के भी मामले हैं, लेकिन उसे क़ानूनी व सामाजिक वैधता न होने के कारण वह छुपा हुआ है. एक सर्वे के मुताबिक़ राज्य में कुल नशेड़ियों में से 70 फ़ीसदी अल्कोहल (शराब) का सेवन करते हैं. इनमें से 14 फ़ीसदी लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं. भले ही वे बींज पैटर्न (एक अंतराल के बाद पीने वाले) या क्रोनिक (रोज़ पीने वाले) के अंतर्गत आने वाले शराबी हों. अनुमान के मुताबिक़ महाराष्ट्र में इस समय लगभग 50 लाख से अधिक शराबी मौजूद हैं. इनमें से वे सभी मौत के क़रीब हैं, जो 15 साल से अधिक समय से शराब का सेवन कर रहे हैं. अब जबकि यह तथ्य चिकित्सकीय स्तर पर पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि शराब की लत लगना अपराधी व्यक्तित्व का सूचक नहीं, बल्कि यह एक गंभीर रोग है, जो शराबी को मौत की नींद तो सुलाता है ही है, साथ ही उसके पूरे परिवार को जीते जी मार डालता है, सरकार का इस ओर ध्यान न देना ग़लत है. वैसे भी यही एक मात्र ऐसी बीमारी है, जिसमें मरीज़ को समाज की सहानुभूति भी नहीं मिलती है. एक और ख़तरनाक तथ्य यह है कि अब 15 वर्ष की आयु से ही किशोर शराब का सेवन करने लगते हैं. अगली पीढ़ी के लिए यह क़तई अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता.

मदिरालय जाने को घर से चलता है पीनेवाला,
किस पथ से जाऊं? असमंजस में है वह भोलाभाला,
अलग-अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं-
राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला।

हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ शराब, शराबी और शराबख़ाने की अलंकारिक व्याख्या करती है. वैसे भी शराब को आम तौर पर शौक़ और मस्ती का शग़ल माना जाता है. मौज-मस्ती के लिए पी गई शराब कब शरीर और दिमाग़ की सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाती है, किसी को पता नहीं चलता. सदियों से शराब को लेकर कुछ इसी प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं. फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन ने शराब पीकर शराब पीने से लीवर ख़राब होता है, डायलाग क्या कहा, यह तथ्य समाज में स्थापित हो गया कि शराब पीने से लीवर ख़राब हो जाता है. शराबी, कबाबी, व्यसनी व्यक्ति को आम तौर पर असामाजिक तत्व के रूप में पेश कर समाज अपना पल्ला झाड़ लेता है. वैसे ही जिस प्रकार एड्स या एचआईवी को सीधे-सीधे चरित्र से जोड़ दिया गया. इससे एक बात तो साफ़ है कि समाज में व्यसन के प्रति जागरूकता का अभाव है. अब जबकि यह तथ्य चिकित्सकीय स्तर पर पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि शराब की लत लगना अपराधी व्यक्तित्व का सूचक नहीं, बल्कि यह एक गंभीर रोग है. यह न सिर्फ़ शराबी को मौत की नींद सुलाता है, बल्कि उसके पूरे परिवार को जीते जी मार डालता है. यह बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि सामान्य चिकित्सकों में भी भ्रम की स्थिति रहती है और अनाप शनाप दवाएं मरीज़ को देते हैं. इसके लिए विशेषज्ञ मनोचिकित्सक की ज़रूरत होती है. सरकार केंद्र की हो या राज्य की, दोनों ही शराब के मामले में ख़ामोश हैं. कारण साफ़ है. पहले शराब बनाने वाली कंपनियों और फिर शराब की बिक्री से मिलने वाले राजस्व के कारण सरकारें शराब की रोकथाम तो दूर इस ओर व्यापक जनजागरण भी नहीं कर रही है. अब यह बात तो हर प्रबुद्ध नागरिक की समझ में आती है कि यदि शराब की लत भी एड्स जैसी आयातित बीमारी होती और इसके उपचार की दवाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास होतीं तो शायद अब तक सरकार इसकी रोकथाम के लिए कई क़दम उठा चुकी होती. शराबियत तो ऐसी गंभीर बीमारी है कि इसमें किसी की सहानुभूति भी नहीं मिलती. यह रोग तेज़ी से फैल रहा है. इस रोग ने रोगी के साथ ही कई घर तबाह कर दिए हैं. शराबियत के असंख्य मरीज़ों के परिवार के लोग मानसिक रोग की चपेट में हैं. शराबियत की बीमारी और इसके उपचार के संबंध में जनजागरूकता नहीं के बराबर है. सड़क दुर्घटनाओं के माध्यम से ही बड़ी संख्या में शराबियों के साथ ही बेगुनाहों की मौत हो जाती है. इन सभी तथ्यों के बावजूद इस दिशा में पहल न करना सरकार के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है. महाराष्ट्र में अभी हाल ही में शराब (बियर छोड़कर) पीने की न्यूनतम आयु 21 से बढ़ा कर 25 वर्ष कर दी गई है. सरकार का दावा है कि शराब की बिक्री को कम करने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन यहां हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग नज़र आते हैं. अगर सरकार शराब के इस्तेमाल के प्रति इतनी ही गंभीर है तो पहले इस बात का ख़ुलासा होना चाहिए कि पिछले सालों में 21 वर्ष के कम आयु के युवाओं को शराबख़ाने में जाने से रोकने के लिए सरकार ने क्या एहतियाती क़दम उठाए या फिर इस नियम को लागू करने के लिए सरकार ने क्या क़दम उठाए. बियरबारों में ज़रूर एक तख्ती लगी होती है, जिस पर यह चेतावनी लिखी होती है कि 21 वर्ष (अब 25 वर्ष) से कम आयु के लोगों का प्रवेश वर्जित है. यह तख्ती भी इस क़द्र लगाई जाती है कि किसी को दिखाई नहीं देती.

आदत नहीं व्यसन – कई बार व्यसन को आदत मान लिया जाता है, जबकि यह ग़लत है. दरअसल, व्यसन का सीधा संबंध मानसिक और शारीरिक बंधन से है. जब व्यक्ति शराब के व्यसन के अधीन हो जाता है तो उसमें कंपकपी, चिड़चिड़ापन, भूख नहीं लगना, अनिद्रा, निर्णय क्षमता का अभाव, मानसिक अस्वस्थता जैसे शारीरिक लक्षण प्रगट होने लगते हैं. इसलिए यह शारीरिक एडिक्शन की श्रेणी में आता है. मानसिक लत का उदाहरण यह है शराब पीने के बाद शराबी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है. यही कारण है कि शराबी व्यक्ति कई बार शराब पीने के बाद कई ऐसे बड़े काम कर डालता है जो आम तौर पर वह बिना शराब पिए नहीं कर सकता. कई बार शराबी शराब पीने के बाद कुछ समय के लिए ही सही मगर दुख भुलाने की चेष्टा करता है. जब मानसिक और शारीरिक लत मिल जाते हैं तब व्यक्ति शराबी हो जाता है.

यह रोग अनुवांशिक और जन्मजात है – ज़रूरी नहीं है कि शराब की लत लगने के पीछे सिर्फ़ संगत ही कारणीभूत हो. इसके कई ऐसे भी कारण होते हैं जो आम लोगों को मालूम नहीं हैं. कुछ लोगों के दिमाग़ की संरचना ही वायर्ड होती है. उनके न्यूरो सिस्टम में कुछ पेशियां ही ऐसी होती हैं जिन्हें अगर एक बार किसी नशे का स्वाद मिल गया तो वे उसकी बार-बार मांग करने लगते हैं. यहां बैठे रिसेप्टर्स यह मांग लगातार करते हैं. वैसे ही नींद की गोली का रिसेप्टर हमारे दिमाग़ में मौजूद रहता है. शेर के मुंह में मनुष्य का ख़ून लगने के समान इसका भी हाल होता है. यह कई लोगों में अनुवांशिक होता है. इनमें यह ख़ानदानी बीमारी होती है. वैसे अनुवांशिक संक्रमण का मतलब यह नहीं होता है कि कोई शराबी बन जाए. इसके बाद महत्वपूर्ण रोल मरीज़ की संगत, वातावरण, संस्कारों, समझबूझ का होता है. जिनमें इस बीमारी का जीन नहीं है, उन्हें ग़लत संगत मिलने पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर उक्त तीनों ही कारक एक साथ एकत्र हो गए तो फिर शराब की लत लगने से बचाना मुश्किल है. जिनमें यह कारक पाए जाते हैं, वे बचपन से ही ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति के होते हैं. इनमें सीखने की क्षमता कम होती है. इनमें उत्तेजनात्मक व्यवहार भी पाया जाता है. ऐसे लोग थोड़े लहरी प्रकृति के होते हैं.

लीवर से पहले ही दिमाग़ ख़राब हो जाता है – मनोचिकित्सक माधवराव राजे बताते हैं कि शराब पीने से सबसे पहले दिमाग़ पर असर पड़ता है. शराबी में जीने की तमन्ना ख़त्म हो जाती है. उसे हर समय शराब पीने की ही लालसा रहती है. उसके लिए स्वास्थ्य, धन, पत्नी, परिवार, समाज सब दूसरे दर्जे के हो जाते हैं. उसमें अवसाद, मायूसी, निराशा के भाव घर करने लगते हैं. इनसे बचने के लिए वह बार-बार शराब की ओर दौड़ता है, क्योंकि इसके सेवन के बाद वह जागृत नहीं रहता है. दरअसल, दिमाग़ में ग्लूटामाइट होता है जिसके कारण हम जागृत रहते हैं. इसमें जब ज़ोर पड़ता है तो जागृत होने के लिए शराब का सेवन शुरू हो जाता है. इसी कारण कई शराबी शराब पीने के बाद शेर बन जाते हैं. जब यह ग्लूटामाइट बदल जाता है तो शराबी के स्वास्थ्य में गिरावट शुरू हो जाती है. उसका रक्त चाप बढ़ जाता है. आंतें ख़राब होने लगती हैं. लीवर पर असर पड़ता है. उसमें संभोग की शक्ति धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है. कई कुंवारों में भी यह लक्षण पाया जाता है.

सामाजिक उपेक्षा – सलाहकार तुषार नातु इस बीमारी के संबंध में कहते हैं कि यह बीमारी धूर्त होती है. इसलिए शराबी में झूठ बोलना, मक्कारी जैसे लक्षण होते हैं.

शेष पृष्ठ 18 पर

आदमी नहीं, शराब ही पीती है शराब

यह आम धारणा भी ग़लत है कि आदमी शराब पीता है. दरअसल मस्तिष्क के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं. मनोचिकित्सकों का कहना है कि रक्त प्रवाह के साथ अल्कोहल दिमाग़ में मौजूद जितने रिसेप्टर्स तक पहुंचता है, उन्हें अपने अधीन कर लेता है. शराबी हो चुके ये रिसेप्टर्स पहले एक समूह बना लेते हैं. बाद में अपने समूह के साथ ये अन्य स्वस्थ रिसेप्टर्स से संपर्क करते हैं और उन्हें अपने समूह में शामिल करते हैं. इनकी सक्रियता इतनी अधिक होती है कि अपनी संख्या के जितने ही स्वस्थ रिसेप्टर्स को अपने समूह में शामिल करते हैं. जब ये मज़बूत हो जाते हैं तो किसी कारख़ाने की कर्मचारी यूनियन की तरह ही, हमारी मांगें पूरी करो की तर्ज़ पर शराब की मांग करते हैं. यदि उन्हें उस समय अल्कोहल नहीं दिया गया तो ये काम बंद हड़ताल कर देते हैं. ऐसे समय में शराबी के सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह ख़त्म हो जाती है. इसे ही क्रेविंग की स्थिति कहते हैं यानी उस समय शराब की मांग उच्चतम सीमा पर होती है. और एक बार अगर शराब को मुंह से लगा लिया तो कम से कम-किक-आने तक शराबी शराब पीता ही जाता है. यही क्रेविंग अगर नियंत्रण में आ जाए तो शराब से दूर होने की संभावना तेज़ हो जाती है. पहले मज़े के लिए शराबी शराब पीता है और बाद में दिमाग़ के अंदर की शराब ही शराब पीना शुरू कर देती है.

उपचार संभव है

मनोचिकित्सक माधवराव राजे कहते हैं कि शराबियत का उपचार संभव है. अब तो क्रेविंग ख़त्म करने के लिए भी दवाएं आ गई हैं. वैसे जिन लोगों को ऑब्सेसिव कम्पल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी है, वे क्रेविंग की स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीजोफ्रेनिया के मरीज़ इसे कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं. क्रेविंग को क़ाबू में करने का एक मात्र उपाय सत्संग है. क्रेविंग के बारे में परिवार को बताना चाहिए. चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए. फल का आहार, कोल्ड ड्रिंक्स से राहत मिलती है. लगभग 2 साल इसके उपचार में लग जाते हैं. एक बार मरीज़ शराब से 3 साल दूर रह गया, तब कुछ सकारात्मक परिणाम की कल्पना की जा सकती है. मैत्री व्यसन मुक्ति केंद्र, नागपुर के संस्थापक रवि पाध्ये का मानना है कि शराब छोड़ना जैसे शब्द ही ग़लत हैं. दरअसल शराबी को शराब से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए. व्यसनाधीनता मनो-शारीरिक बीमारी है. 30

परिवार का साथ ज़रूरी है

डॉ. राजे कहते हैं कि इलाज के दौरान शराबी के परिवारवालों का उसके साथ डटकर खड़ा रहना ज़रूरी है. परिवार के लोगों को उसे बिना किसी शर्त या अपेक्षा के प्यार देना होगा. कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार में उपचार के बाद शराब छोड़ देते हैं, ज़्यादातर लोग बार-बार शराब की ओर खिंच जाते हैं. इसलिए अपने सलाहकार और चिकित्सक को बदलना नहीं चाहिए. शराबी में आत्म स्वीकृति होनी चाहिए कि वह शराबी है और शराब से उसे काफ़ी हानि हो चुकी है.

सरकार को जागना होगा

जब शराब से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है तो शराबियत की बीमारी के नियंत्रण के लिए भी सरकार को जागना होगा. एड्स नियंत्रण की तर्ज़ पर ही शराबियत की बीमारी से मुक्ति के लिए भी इस क्षेत्र में काम कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ मिल कर काम करने की आवश्यकता है. साथ ही मेडिकल कालेजों और ज़िला चिकित्सालयों में इसके लिए विशेष कक्ष बनाए जाने चाहिए. उपचार पद्धति के ख़र्च को कम करने के लिए इसमें व्यापक सब्सिडी भी दी जानी चाहिए

मराठा–मराठी–महाराष्ट्र की अस्मिता का झंडा अब तक किसने बुलंद किया है भाई? यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए.

प्रत्येक विद्यार्थी को पास बुक दी गई है, जिसमें उसके द्वारा जमा राशि और बैंक से निकाली गई रक़म को विधिवत दर्ज किया जाता है.

महाराष्ट्र में सीमाएं टूट रही हैं

पृष्ठ 18 का शेष

यह मतिभ्रम करने वाला है. यह क्रमशः बढ़ने वाली, ताक़तवर और स्थाई बीमारी है. इस कारण कई बार शराबी को ग़ैर क़ानूनी काम करने के लिए जेल तक जाना पड़ता है. शराबियों की हरकतों के कारण समाज में ऐसे लोगों को तिरस्कार की नज़रों से देखा जाता है. जब तक शराब मौज–मस्ती तक सीमित रहती है, तब तक तो चल जाता है, लेकिन व्यसनाधीनता के बाद समाज से पूरी तरह बहिष्कार कर दिया जाता है. घरेलू झगड़े, पड़ोसियों से मनमुटाव, गाली–गलौज जैसी हरकतों को समाज में पसंद नहीं किया जाता है.

पूरा परिवार मानसिक रोगी हो जाता है – सबसे अफ़सोसनाक पहलू यह है कि शराबी व्यक्ति का परिवार भी मानसिक बीमारी की गिरफ्त में आ जाता है. कई मामलों में तो शराबी की पत्नी को भी समाज अकेली औरत की तरह ग़लत नज़रों से देखने लगता है. पति–पत्नी के संबंध विच्छेद होने के ज़्यादातर मामले शराब के कारण ही हैं. सबसे बुरा असर छोटे बच्चों पर पड़ता है और वे समय के पहले ही वयस्क हो जाते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

अपना ख़ून तो अपना ही होता है

ये क्या हो रहा है...

आदरणीय बालासाहब ठाकरे जी, ये क्या हो रहा है.. आपके घनिष्ठ मित्र शरद पवार के भतीजे आपके राजनीतिक करियर पर ही प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर एक आपके भतीजे हैं जिन्हें आपने दुश्मन घोषित कर दिया है, आपके बचाव में आ खड़े हुए हैं. सच अपना ख़ून तो अपना ही होता है. आपने सच ही कहा था कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, लेकिन जब भी ऐसी घटना–दुर्घटना होती है तो किंतु... परंतु.... पर.... के आधार पर कई सवाल उठ खड़े होते हैं. इसकी वजह है दोस्त से दुश्मन या दुश्मन से दोस्त बनने के पीछे छुपा स्वार्थ, मतलब सबका अपना–अपना स्वार्थ होता है इसलिए किंतु, परंतु बहुत लगते हैं. अब देखिये शरद पवार आपके परम मित्रों में हैं और अपने दल के मुखिया भी हैं, ऐसे में यदि उनका भतीजा ही आपकी राजनीतिक उपलब्धियों पर सवाल उठाता है तो आम आदमी या आम कार्यकर्ता आश्चर्य में पड़ जाता है. उसके ज़ेहन में कई और किंतु, परंतु उमड़ने–घुमड़ने लगते हैं. ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप मुंबई में कोई क्रिकेट मैच न होने देने की घोषणा करते हैं तो उपमुख्यमंत्री के काका आपको मनाने के लिए आपके दरबार में तुरंत हाज़िर हो जाते हैं और आप बड़ा दिल रखते हुए नरम भी हो जाते हैं. इसके बावजूद आपके ख़िलाफ़ बोलने की जुर्रत उनके पुतने ने की. यह सरासर अहसान–फ़रामोशी है. उम्र का लिहाज़ भी नहीं किया. मगर मानना पड़ेगा आपको भी– उसे ख़ूब खरी–खोटी सुनाई. वह अपने को अकेला महाराष्ट्र की राजनीति का दबंग समझते हैं फिर भी उद्धव भैया के न रहने पर आप पर हमला किया. उन्हें शायद इसका गुमान भी नहीं होगा कि राज आख़िर आपका ख़ून है, लेकिन राज भी आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके और ताक़ीद दी कि आपके विषय में बोलने से पहले दादा अपनी और आपकी उम्र का लिहाज़ करें. जब दादा ने राजनीति की ए.बी.सी.डी. भी नहीं सीखी थी तब से आपकी दबंगई पूरे महाराष्ट्र में एकछत्र चलती रही है. इस बात का ख्याल दिलाना ज़रूरी था. महाराष्ट्र की राजनीति आपके बिना अधूरी है. मातोश्री के नाम पर तो अच्छे–अच्छे कांपते हैं ऐसे में कोई यह सवाल कैसे उठा सकता है कि बालासाहब का राजनीतिक–सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान है? मराठा–मराठी–महाराष्ट्र की अस्मिता का झंडा अब तक किसने बुलंद किया है भाई? यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए. वह यह भूल गए कि एक दौर ऐसा भी था जब बालासाहब की गर्जना पर राज्य सरकार सहम जाती थी. राज्य की धड़कन रुक जाती थी. आज वृद्धावस्था आ गई तो कोई भी, कुछ भी कहेगा क्या? दादा को यह याद रखना चाहिए की बाघ तो बाघ ही होता है जिसके आगे कोई दादा ठहर नहीं सकता है. इसलिए जय शिवाजी, जय भवानी का मर्म समझें. यह नारा पूरे देश की आन–बान से जुड़ा है और बालासाहब की पहचान तो इसके बिना अधूरी लगती है, क्योंकि इस नारे के साथ ही उनकी सेना जोश से भर उठती है. उनकी सेना जब जोश से भर उठती है तो कुछ सोचे–समझे बिना, कुछ भी कर सकती है, जैसा कि कुछ दादा की पार्टी के कार्यालयों में किया गया. यदि दादा अब भी नहीं समझे तो राज या उद्धव उनको समझा देंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

स्पैन्को के विरोध में सियासी रंग

नागपुर में बिजली वितरण का काम संभाल रही कंपनी स्पैन्को लिमिटेड को काम हाथ में लेते ही जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा. फ्रेंचाइजी हाथ में आते ही स्पैन्को पर परेशानियों का अंबार टूट पड़ा. वर्षों से बीपीओ के रूप में काम कर रही स्पैन्को ने तो लोगों से माफ़ी मांग ली है, इसलिए इसके ठेका देने वाले राज्य के ऊर्जा मंत्री अजीत पवार और विपक्षियों को दबाव बनाने का एक और मौक़ा मिल गया है. अब इस स्पैन्को के मुद्दे पर विपक्षी दल माहौल गर्माने की कोशिश में लग गए हैं.

स्पैन्को के ख़िलाफ़ माहौल बनते ही विपक्षियों ने मौक़े को लपक लिया. भाजपा के महासचिव और विधायक देवेंद्र फडणवीस ने उपराजधानी के अन्य विधायकों के साथ मिलकर स्पैन्को को जमकर कोसा. साथ ही बिजली कटौती के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (एमएसडीसीएल) और महाराष्ट्र सरकार को भी दोषी ठहराया. उन्होंने यह तक कह डाला कि स्पैन्को को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य के ऊर्जा मंत्री अजीत पवार ने भ्रष्टाचार किया है. फडणवीस ने कहा कि बिजली वितरण में महावितरण ही अपनी जगह पर्याप्त था. स्पैन्को को बिजली वितरण का कोई अनुभव नहीं है. वह लोगों की मुश्किलें सुलझाने में पूरी तरह नाकाम हो रही है, इसलिए इसका ठेका रद्द कर दिया जाना चाहिए. भाजपा की यह चाल संभवतः राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्रालय तक पहुंच गई, तभी तो मंत्रालय ने भी अपनी ओर से ख़ानापूर्ति शुरू कर दी है.

दरअसल स्पैन्को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो दुनिया भर के विभिन्न देशों में बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) का कार्य कर रही है. यह दुनिया की अनेक कंपनियों और संस्थाओं के साथ टेलीकॉम, रेलवे, तकनीकी संरचना, परिवहन, ई–गवर्नेंस, रक्षा आदि क्षेत्रों में ऑउटसोर्सिंग पद्धति से कार्यरत है. कंपनी के अनेक कार्य भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ओमान–क़तर और नाइजीरिया में चल रहे हैं. उदाहरण के लिए यह अमेरिका में ऋण वसूली, खुदरा बाज़ार और खेल क्षेत्र में कार्यरत है. जानकारी के अनुसार स्पैन्को के लिए बिजली वितरण का क्षेत्र नया है. हालांकि स्पैन्को ने अपनी वेबसाइट में बिजली वितरण अनुभव को लेकर ख़ूब आत्मप्रशंसा की है, लेकिन उसके पास इस अनुभव के कोई प्रमाण नहीं हैं. सरकार ने महावितरण का निजीकरण बोली लगाकर किया है. इस बोली में स्पैन्को ने रिलायंस और टाटा जैसी कंपनियों को पीछे छोड़कर 5350 हज़ार करोड़ में ठेका हासिल किया. समझौते के तहत स्पैन्को नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत वर्धा रोड से पश्चिमी भाग, चिंचभवन और सीताबर्डी को छोड़कर अमरावती रोड के दक्षिणी भाग को बिजली प्रदान करेगी. यह समझौता आगामी 15 वर्षों के लिए हुआ है. स्पैन्को बिल वसूली, बिजली गड़बड़ियां सुधारने और नए कनेक्शन देने का काम करेगी. ये सभी काम अब तक महावितरण करती थी. फ्रेंचाइजी के क्षेत्र में महावितरण के 1,118 कर्मचारी कार्यरत थे. हस्तांतरण के बाद 60 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर स्पैन्को को सौंपा गया है, बाक़ी कर्मचारियों को महावितरण अन्यत्र नियुक्त कर रही है.

वैसे महावितरण के एक हज़ार से ज़्यादा कर्मचारी दो साल पहले से महावितरण के निजीकरण का विरोध कर रहे थे. आम जनता की सहानुभूति भी कर्मचारियों के साथ थी. इस दौरान बिजली कर्मियों का साथ देने के लिए प्रभावी रूप से कोई आगे नहीं आया. आख़िर ऊर्जा मंत्रालय ने भारी विरोध के बीच कंपनी को 1 मई से महावितरण का कामकाज स्पैन्को को सौंप दिया. संयोगवश मई के पहले ही सप्ताह में शहर में तेज़ आंधी से बिजली की लाइनें ध्वस्त हो गईं. फिर क्या था, पहले से गुस्साए बैठे लोगों ने स्पैन्को पर चढ़ाई कर दी. नागपुर के सिविल लाइंस, महल और गांधीबाग में अंधेरा छाते ही लोगों ने हल्ला बोल दिया. अगले दिन से स्पैन्को के कार्यालयों में तोड़फोड़ और मारपीट की ख़बरें आम हो गईं.

उधर, सत्तारूढ़ कांग्रेसी ख़ेमा स्पैन्को का भारी विरोध देखकर भी चुपचाप बैठा है. जिन्हें स्पैन्को पर व्यक्तिगत नाराज़ी है, वे भी पार्टी के डर से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं. हालांकि सरकार को स्पैन्को को काम देकर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है, फिर भी अजीत पवार ने सक्रियता दिखाकर महावितरण का निजीकरण कर ही डाला. नागपुर में भी भारी बिजली कटौती होने तक सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी. जब भाजपा ने इसे मुद्दा बना दिया तब ऊर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र मुलक ने बिजली संबंधी जांच शुरू करने की दिशा में क़दम बढ़ाया. लोग सवाल कर रहे हैं कि आख़िर बिजली वितरण का निजीकरण क्यों किया गया? कम अनुभवी स्पैन्को को बिजली वितरण का ठेका क्यों दिया गया? इतना होने पर भी सरकार की ओर से सिर्फ़ इस बात की जांच की जा रही है कि शहर की बिजली व्यवस्था क्यों लड़खड़ाई. सत्तारूढ़ कांग्रेस–राकांपा की विरोधी पार्टियों ने इस गुस्से को और बढ़ाने का काम किया. अब लोगों के आक्रोश को भुनाने का सियासी दौर शुरू हो गया है. नागपुर में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से स्पैन्को क़रार रद्द करने की मांग करने की तैयारी कर ली है. अब देखना यह कि भाजपा के स्पैन्को हटाओ अभियान में कितना दम है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कुछ तथ्य

गत 27 मई को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण नागपुर आए थे. इस तारीख़ तक नागपुर में स्पैन्को का हाहाकर चरम पर था. मुख्यमंत्री दिन भर कांग्रेसियों से घिरे रहे और उनसे स्पैन्को के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा. स्पैन्को के पास मोबाइल कंपनियों की तरह कस्टमर केयर एक्जिक्यूटिव हैं, लेकिन जब बिजली गुल होती है तो फील्ड पर लाइनमैन कम पड़ जाते हैं. राज्यमंत्री राजेंद्र मुलक ने बार–बार बिजली जाने पर बिजली सुधार कार्य के दौरान अपने कई फोटो खिंचवाए, पर मामला बिगड़ने पर जांच करने की बात कहकर सरकार ने मामले को रफ़ा–दफ़ा कर दिया. जब महावितरण के कर्मचारी निजीकरण का विरोध कर रहे थे, तब भाजपा जाने कहां थी? अब जब स्पैन्को के नाम से लोग चीख़ने–चिल्लाने लगे तो भाजपाइयों ने भी सुर से सुर मिला दिया. वर्ष 2010 में बिजली वितरण के लिए जब बोलियां लगाई गईं, स्पैन्को ने ऊंची क़ीमत पर ठेका हासिल किया. क्या कंपनी अपने ख़र्च, ठेके की रक़म निकालने के लिए ग्राहकों पर आर्थिक बोझ नहीं डालेगी?

आदिवासी गांव में स्कूल बैंक

प्रणय निर्बाण

क्या बैंक पूंजीपति या कोई कंपनी ही शुरू कर सकती है? इस सवाल का जवाब सामान्य व्यक्ति हां ही में देगा. मगर महाराष्ट्र के एक अतिदुर्गम क्षेत्र में स्थित आदिवासी गांव के विद्यार्थियों ने स्कूल बैंक शुरू कर सामान्य व्यक्ति को अपनी सोच बदलने को मजबूर कर दिया है. इन बच्चों ने यह साबित किया है कि जहां कुछ करने की चाह हो, वहां राह अपने आप बन जाती है.

राज्य के वाशिम ज़िले की तहसील मालेगांव के अतिदुर्गम क्षेत्र में बसे मुसलवाड़ी ग्राम में स्थित ज़िला परिषद केंद्रीय शाला में शुरू है स्कूल बैंक. इस बैंक को शुरू किया है स्कूल के विद्यार्थियों ने. बैंक के दैनिक कामकाज का संचालन भी छात्र ही मिलजुल कर करते हैं. बैंक के 110 विद्यार्थी सदस्य हैं. हर सदस्य का खाता है और विधिवत सभी को खाता क्रमांक के साथ पास बुक दिया गया है. बैंक में पैसा जमा करने और निकालने की अपनी पावती भी हर व्यवहार पर दी जाती है. बैंक का सारा कार्यभार विद्यार्थी दोपहर में होने वाली छुट्टी के समय संभालते हैं. इस स्कूल बैंक के जन्म की कहानी बड़ी ही विचित्र है. मुसलवाड़ी ग्राम के निकट स्थित अमानी में हर बुधवार को साप्ताहिक बाज़ार लगता है. मध्याह्न छुट्टी होते ही स्कूल के विद्यार्थी बाज़ार में जाते और खुले में बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ ख़रीद कर खाते थे. बाज़ार से स्कूल लौटने पर बच्चों को अक्सर देर भी हो जाती थी. इस बात की ओर शिक्षक एस.वी. सांगले का ध्यान गया और इस समस्या के विषय में सोचना शुरू किया. इस संबंध में सांगले अपने सहयोगी शिक्षकों से भी विचार–विमर्श किया. तत्पश्चात उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की. शिक्षकों और विद्यार्थियों ने आपसी विचार मंथन करने के बाद स्कूल बैंक स्थापित करने का दृढ़ निश्चय किया. इस कार्य में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का पूर्ण सहयोग किया. शिक्षकों ने अपनी ओर से स्कूल बैंक में लगने वाली पावती, पासबुक छपवा दी. बैंक व्यवस्थापक का कार्यभार सौंपा गया कक्षा सात के छात्र रामदास भुरकाडे को और सहायक व्यवस्थापक अतुल गाढवे को बनाया गया. अवर सेविंग, अवर प्रॉफिट (हमारी बचत, हमारा लाभ) यह स्कूल बैंक का घोष वाक्य है. स्कूल बैंक के सभी सदस्य विद्यार्थियों का नाम रजिस्टर में पंजीबद्ध कर खाता नंबर दिया गया है. प्रत्येक विद्यार्थी को पास बुक दी गई है, जिसमें उसके द्वारा जमा राशि और बैंक से निकाली गई रक़म को विधिवत दर्ज किया जाता है. जिस विद्यार्थी को पैसा जमा करना होता है वही बैंक की पावती में अपना नाम, खाता क्रमांक, जमा की जाने वाली रक़म का पूर्ण विवरण भर कर बैंक व्यवस्थापक के पास देता है. व्यवस्थापक खाता क्रमांक व रक़म की जांच कर बहीखाते व पासबुक में इंट्री कर पावती का एक भाग अपने पास रखता है और दूसरा भाग सभासद (पैसा जमा करने वाले सदस्य) को देता है यानी विद्यार्थियों के स्कूल बैंक का पूर्ण आर्थिक लेन–देन की पद्धति आज के आधुनिक बैंकों की प्रक्रिया पर आधारित है. इस तरह यहां के स्कूल के बच्चे अपने माता–पिता से मिलने वाले जेब ख़र्च की रक़म को बचा कर स्कूल बैंक में जमा करते हैं. बचत की गई इस रक़म से वे अपनी पढ़ाई में लगने वाली सामग्री ख़रीदते हैं और कभी–कभार घर में ज़रूरत पड़ने पर इस बचत का उपयोग करते हैं. ऐसे करने से विद्यार्थियों को अलग ही आनंद मिलता है तथा बचत से होने वाले लाभ व उससे मिले अनुभव से उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का अहसास स्कूल जीवन में ही मिल रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

अपारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा मिले

लाखों करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में जमा है. यदि इस असंख्य राशि को उजागर करने के गंभीरता से प्रयास किए गए तो देश में विकास के लिए आर्थिक संसाधन की कमी नहीं रह जाएगी. सरकार को सलाह दी जानी चाहिए कि जो व्यक्ति अपना कालाधन उजागर नहीं करता, उसे देशद्रोही क़रार दिया जाए

चाहे घरेलू क्षेत्र हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र, आज ऊर्जा जीवन की प्रमुख आवश्यकता बन गई है. देश की प्रगति और समृद्धि के लिए ऊर्जा आवश्यक तत्व है. जापान में आई सुनामी हमें ख़तरनाक नतीजों का सबक़ दे गई है. इसलिए आण्विक ऊर्जा परियोजना लगाने से पहले बहुत ज़्यादा जांच–पड़ताल ज़रूरी है. महाराष्ट्र में स्थापित की जा रही जैतापुर परियोजना के लिए भी यह लागू होता है. सरकार को जल्द इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह अत्यावश्यक है. साथ ही साथ भारत को ग़ैर परंपरागत ऊर्जा को नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा हमें सुलभता से सूर्य, पवन, बायोमास और समुद्री लहरों से प्राप्त हो जाती है. भारत में तो समुद्र तट सात हज़ार किलोमीटर लंबा है. बिजली आपूर्ति को एक ही स्थान पर केंद्रित करने के बजाय प्रत्येक गांव में या कुछ गांवों के समूहों के बीच ग़ैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन को तरजीह दी जानी चाहिए. इससे न केवल पारेषण हानि रुकेगी, बल्कि नए शोध और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. हर गांव में पर्याप्त बिजली उत्पादन हो पाएगा, जबकि बिजली के केंद्रीयकरण से ग्रिड फेल होते हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र बिजली की कमी से जूझता है. इस कारण बिजली उत्पादन का विकेंद्रीकरण ज़्यादा उचित है.

योजना आयोग सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन प्रणाली को नई दिशा देने और उसे ज़्यादा सुलभ बनाने के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध कराएगा. यह अनुमान लगाया जा चुका है कि भारत ग़ैर–परंपरागत तरीक़ों से आज की तुलना में दस गुना अधिक ऊर्जा पैदा कर सकता है. ग़ैर परंपरागत ऊर्जा साधनों के द्वारा वर्तमान की ज़रूरत लायक़ बिजली आसानी से प्राप्त की जा सकती है.

पर्यावरणविद् डॉ. मोहन धारिया द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केंद्र को दिए गए सुझावों की अंतिम कड़ी

विकास के लिए संसाधन – हमेशा कहा जाता है कि देश में आर्थिक संसाधन सीमित हैं. योजना आयोग को सरकार के ध्यान में लाना चाहिए कि देश में बीस लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा धन कालेधन के रूप में है. लाखों करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में जमा है. यदि इस असंख्य राशि को उजागर करने के गंभीरता से प्रयास किए गए तो देश में विकास के लिए आर्थिक संसाधन की कमी नहीं रह जाएगी. सरकार को सलाह दी जानी चाहिए कि जो व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर अपना कालाधन उजागर नहीं करता, उसे देशद्रोही क़रार दिया जाए. इस अपराध में शामिल लोगों की संपत्ति ज़ब्त करने के साथ ही पांच वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा दी जाए. देश के अंदर और बाहर छुपे कालेधन को वापस लाने के लिए ऐसे ही कड़े मापदंड अपनाने की ज़रूरत है. साहस और दृढ़ निश्चिय के बिना यह संभव नहीं हो सकता है. इसे ही स्वच्छ और दृढ़ नेतृत्व कहा जाता है. राजनीतिक इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता और साहस की कमी से भारत अपने स्वयं के संसाधनों की सुरक्षा करने में नाकाम है. भारत को अपने दम पर समृद्ध बनाना है तो राष्ट्रद्रोहियों और कालाबाज़ारियों को बचाने की वर्तमान नीतियों को छोड़ना होगा. हालांकि योजना आयोग कोई वैधानिक संस्था नहीं है फिर भी वह सरकार को वास्तविकताओं से अवगत कराकर भारत के समृद्ध भविष्य के लिए उसे सही दिशा दे सकती है.

डॉ. मोहन धारिया
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना के विस्थापित ग्रामवासी नागपुर विभागीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए.

सेवानिवृत्ति से पूर्व नागपुर आगमन पर एयर चीफ मार्शल नाईक का हवाई अड्डे पर स्वागत करते हुए एयर फोर्स अधिकारी.

ऐ भाई, जरा संभल केचलना ! बारिश आ गई. न जाने मनपा को कब सुध आएगी इन गड्ढों की

विदर्भ के पहले इंडोर स्टेडियम का विहंगम दृश्य, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री ने लोकार्पित किया.

नागपुर सुधार प्रन्यास के नवनियुक्त सभापति प्रवीण दराडे, पदमुक्त सभापति संजय मुखर्जी से पदभार ग्रहण करते हुए.

पदमुक्त जिलाधिकारी प्रवीण दराडे नवनियुक्त जिलाधिकारी सौरभ राव को पदभार सौंपते हुए.

चौथी दुनिया महाराष्ट्र
आवश्यकता

विज्ञापन व्यवस्थापक (पांच साल का अनुभव)
विज्ञापन प्रतिनिधि (कम से कम तीन साल का अनुभव)
प्रसार व्यवस्थापक (कम से कम तीन साल का अनुभव)
जिला प्रतिनिधि (महाराष्ट्र के हर जिले में- मानधन + कमीशन बेस पर)
वितरण एजेंट (महाराष्ट्र के हर ज़िले में)
संपर्क
आशिर्वाद पब्लिकेशन प्रा.लि.
२७, पिसे कॉम्प्लेक्स, धंतोली रेलवे पुल के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर- ४४०००३
फोन नं. - ०७१२- २७०७४१४/१५

चौथी दुनिया
हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार
महाराष्ट्र
आशिर्वाद पब्लिकेशन प्रा.लि.
२७, पिसे कॉम्प्लेक्स धंतोली रेलवे पुल के पास,
ग्रेट नाग रोड नागपुर- ४४०००३
फोन नं. - ०७१२- २७०७४१४/१५
Email:- chauthiduniya@gmail.com
राष्ट्रीय साप्ताहिक १६ पृष्ठों के साथ महाराष्ट्र के रंगीन ४ पृष्ठ
आज ही अपना अंक सुरक्षित करवाएं
हॉकर और बुक स्टॉल धारकों के लिए उपलब्ध

मुंबई	: दातार एंड सन्स, मुंबई	– 022–2203427
नागपुर	: पाठक ब्रदर्स, नागपुर	– 0712 2420293
नागपुर	: दांगट न्यूज पेपर, रामदासपेठ, नागपुर	
जलगांव	: पाठक ब्रदर्स, जलगांव	– 0257–2225806
नासिक	: पाठक ब्रदर्स, नासिक	– 0253–2506898
पुणे	: दांगट न्यूज पेपर, पुणे	– 9922419042
औरंगाबाद	: संदीप सुखधान	– 9762478014
अकोला	: कृष्णा मार्केटिंग, अकोला	– 9011325700
चंद्रपूर–गडचिरोली	: रतन न्यूज पेपर एजन्सी	– 07172–258554

धन्यवाद

श्री अनिस अहमद
सेक्रेटरी, अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटी(ए.आय.सी.सी.)
संत्रा नगरी को आप पर गर्व है।
आपके कॅबिनेट खेल मंत्री के कार्यकाल में आपने
मानकापुर डिव्हीजनल स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स
हेतु रु. 5 करोड के अनुदान का धनादेश सौपा तथा
अधुरे निर्माण कार्यो को पुरा करने के लिये
रु. 8 करोड की अतिरिक्त राशी का प्रावधान किया।
आपकी खेल के प्रति रुची एवं प्यार ही था
जो आपने स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बजेट राशी को
रु. 16 करोड से बढाकर रु. 24 करोड
का प्रावधान करने हेतु दि.18 फरवरी, 2009 को
मंत्रीमंडल के कॅबीनेट मिटींग में पारित करवाने में प्रमुख भुमिका
अदा की तथा शासकिय मंजुरी प्रदान करवाने में सफलता हासिल की।
(शासन निर्णय क्रः राक्रीयो–2009/(प्र.क्र.25/09)/ क्रीयुसे–1, दि.21 मार्च, 2009)
इसी के फलस्वरुप आज यह स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स
खेल प्रेमियो के लिए उपलब्ध है

Mugdha Creations
हार्दिक शुभकामनाये

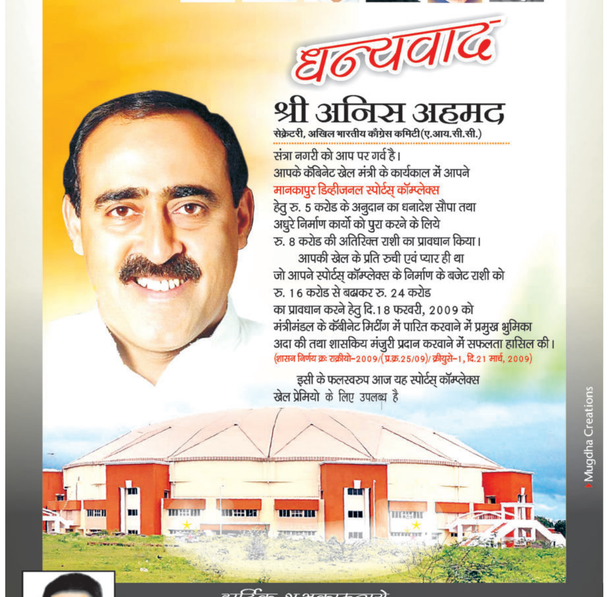

अतुल कोटेचा

...श्रीकांत ढोलके, देवेन्द्र सिंह रोटेले, आशिष पांडे, रींकु जैन, डॉ. मेहुल अडवानी, विक्रम सिंह परीहार, ...मनीष छल्लानी, लोकेश बरडीया, सारंग दाबडे, मुस्तफा टोपीवाला, अरशद सेठ, अनुराग रोटकर, ...अॅड. राकेश मोहोड, शंकर सुगंध, अश्वीन झवेरी, आशिष दिक्षीत, राहुल सरोदे, प्रमोद शुक्ला, सलमान अहमद, ...मनीष धाडीवाल, सुशील श्रीवास्तव, रीतेश सोनी, शारीक अहमद, राजु गायकवाड, योगेश तीरपुडे, ...विधान शर्मा, नवकार जैन, शेख अलिम, बंटी अब्बुमीया, श्रीकांत कैकाडे, कुमार डगा, अनिल ढोबळे, ...विलास लारोकर, अतिक कुरेशी, शिवकुमार गुप्ता, सुरज शर्मा, किशोर चव्हाण, जमीर शेख, आकाश चौरीया ...आशीष वारजुरकर, राजु वैरागडे, मीलींद शिवरकर, गुणवंत रंभाड, राहुल प्रधान, फैजर तव्वकल, विपुल कश्यप

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

गांधीसागर तालाब का सौन्दर्यीकरण किए जाने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना होगा.

तालाब मांगे ख़ून

नागपुर का शुक्रवारी तालाब उर्फ़ गांधी सागर तालाब बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं के कारण चर्चा में है. लोग कहने लगे हैं कि शुक्रवारी तालाब ख़ून मांगता है. इसलिए यहां आए दिन आत्महत्याएं होती रहती हैं. लोग यहां खिंचे चले आते हैं और आत्महत्या करते हैं. गांधी सागर तालाब में 2010 में 45 लोगों और 2011 में पिछले माह तक 15 लोगों ने कूद कर आत्महत्या की है यानी औसतन हर माह तीन व्यक्ति इस तालाब में आकर अपनी जान दे देते हैं.

राजेश नामदेव

जो तालाब कभी उपराजधानी की शान कहलता था, जिस तालाब के कारण नागपुर के कुओं का जलस्तर हमेशा सामान्य से ऊपर बना रहता था, जो तालाब नागपुर के इतिहास का सदियों से साक्षी था और है, वह आज ख़ूनी तालाब के नाम से कुख्यात है. वह अपनी इस हालत पर सिसक रहा है. अब तो नागपुरवासी यह भी कहने लगे हैं कि शुक्रवारी तालाब उर्फ़ गांधी सागर तालाब ख़ून मांगता है. इसलिए यहां आए दिन आत्महत्याएं होती रहती हैं. लोग यहां खिंचे चले आते हैं और आत्महत्या करते हैं.

दरअसल हक़ीक़त यह नहीं है. वास्तविकता इसके उलट है. यह उपराजधानी वासियों की कृतघ्नता, क्रूरता है, जो एक जीवंत तालाब घुट-घुट कर सिकुड़ता गया और वर्तमान में जो कुछ बचा है वह भी हमारी असंवेदशीलता के कारण उपेक्षित है. अपनी उपेक्षा व कुख्यात होने के कारण उदास है, निराश है. ऐसा भी नहीं की इस तालाब की ओर किसी का ध्यान गया और इसके उद्धार का प्रयास नहीं किया गया. कुछ नेताओं को इस तालाब पर तरस आया और इसके उद्धार के प्रति उनमें करुणा भी जागी, पर जो भी प्रयास किए गए आधे-अधूरे मन से किए गए. इसका नतीजा यह है कि इस तालाब का पानी इतना ज़हरीला और गंदा हो गया है कि इसके पास जाते ही दुर्गंध आने लगती है. इंसान तो इसका पानी पीने की सोच भी नहीं सकता है. अब एक बार पुनः महानगर पालिका प्रशासन को इसकी सुध आई है और इसका सौंदर्यीकरण किए जाने की चर्चा हो रही है. वहीं सामाजिक कार्यकर्ता उमेश चौबे ने गांधी सागर तालाब को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग शासन-प्रशासन से की है.

अब सवाल यह है कि मनपा प्रशासन का सौंदर्यीकरण से तात्पर्य क्या है? क्या जैसा देवेंद्र फडणवीस के महापौर के कार्यकाल में किया गया था वैसा. यदि वैसा सौंदर्यीकरण करना है तो जनता का पैसा बख्श दो. सौंदर्यीकरण का अर्थ यह नहीं है कि जनता के करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा कर पेड़-पौधे लगाएं, चारों तरफ़ लाइट लगाई, रंग-रोग़न कराया और हो गया सौंदर्यीकरण. फिर उसकी कोई सुध लेना वाला नहीं, छोड़ दिया लापरवाह जनता-जनार्दन के पीछे. लोग यहां आते हैं, मरते हैं, मरने दो. कचरा फेंकते हैं तो फेंकने दो. सब चलता है, चलने दो. यह रवैया नहीं चलेगा. मनपा प्रशासन और नागपुर की जनता को इस ऐतिहासिक तालाब के दर्द के मर्म को समझना होगा. तभी इसका वास्तविक सौंदर्यीकरण होगा. वरना हालत नागनदी जैसी होगी. नागनदी की साफ़-सफ़ाई कर उसे पुनर्जीवित करने की बातें बहुत हुईं, पर सिर्फ़ बातें हुईं. तन-मन-धन से उसके अस्तित्व को बचाने का प्रयास नहीं किया गया. इसीलिए गांधी सागर तालाब को तालाब बनाए रखने के लिए पूरे तन-मन-धन से प्रयास करने होंगे.

ग़ौरतलब है कि वर्तमान विधायक व भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के महापौर रहने के दौरान करोड़ों रुपए ख़र्च कर बड़े जोशो-ख़रोश के साथ शुक्रवारी तालाब की साफ़-सफ़ाई की गई थी. चारों तरफ़ लाइट लगाई गई थी. पश्चिमी छोर पर सीढ़ियां बैठने के लिए बनाई गईं. बोटिंग भी चालू की गई थी. यह व्यवस्था कुछ दिनों तक ठीक चली. एक दिन बोटिंग करने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई. इसके बाद बोटिंग बंद हो गई. मानो मनपा प्रशासन ने शुक्रवारी तालाब को अपशकुनी मान लिया हो, उसे फिर से उपेक्षित छोड़ दिया गया. वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता उमेश चौबे बताते हैं कि उस समय सिर्फ़ तालाब की गाद (कीचड़) निकालने में एक करोड़ रुपए ख़र्च किए गए थे, उसके बाद भी पूरी मिट्टी नहीं निकाली जा सकी थी. उसके बाद से यह तालाब आत्महत्याओं के लिए कुख्यात होता गया. इस संबंध में गणेशपेठ थाने के वरिष्ठ निरीक्षक डी.जी. जगदाले ने बताया कि गांधी सागर तालाब में साल 2010 में 45 लोगों और 2011 में पिछले माह तक 15 लोगों ने कूद कर आत्महत्या की है यानी औसतन हर माह तीन व्यक्ति इस तालाब में आकर अपनी जान दे देते हैं. आत्महत्या करने वालों में युवक-युवतियों के साथ ही बुज़ुर्ग भी शामिल हैं. सभी के आत्महत्या के कारण अलग-अलग होते हैं. इस तालाब में आत्महत्याओं की घटनाओं को रोकने के उपाय के संबंध में जगदाले का कहना है कि थाने में उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए नियमित बंदोबस्त कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है. इसके लिए मनपा प्रशासन को उपाय योजना बनानी चाहिए.

नागपुर की महापौर अर्चना डेहनकरने के अनुसार मनपा ने गांधी सागर के पानी की साफ़-सफ़ाई और सौंदर्यीकरण के लिए क़रीब ढाई करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. विशेष ध्यान पानी के शुद्धिकरण पर है. वॉटर प्यूरीफिकेशन के लिए प्लांट लगाया जाएगा. सौंदर्यीकरण व लाइटिंग जो अव्यवस्थित है उसे दुरुस्त किया जाएगा. शुक्रवारी तालाब में आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय है. पिछले दिनों ही एक इंजीनियरिंग के छात्र ने तालाब में कूद कर आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या की इन घटनाओं को रोकने के लिए तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ ही उपाय योजना भी बनाई है, जिसके तहत गांधीसागर तालाब की चारों दिशाओं में चार गार्ड तैनात किए जाएंगे. इसके लिए मनपा आयुक्त के पास प्रपोजल दिया है. साथ ही हमने गणेशपेठ थाने के निरीक्षक को गांधी सागर तालाब के पास पुलिस चौकी स्थापित करने का प्रस्ताव भी भेजा है. चौकी के लिए जगह की व्यवस्था मनपा प्रशासन करेगा. इससे तालाब के आसपास गार्डों के साथ ही पुलिस भी चौबीस घंटे निगरानी करेगी. इसके अलावा हम फिर से गांधी सागर में बोटिंग चालू कराने का प्रयास कर रहे हैं और मनपा आयुक्त के पास इससे संबंधित प्रस्ताव मंज़ूरी के लिए दिया गया है, लेकिन सबसे पहले गांधी सागर तालाब के पानी को स्वच्छ करने का सवाल है, इसे ही दृष्टि में रखते हुए उसके ओवरफ्लो होने पर पानी निकासी के लिए बनाए गए आउटलेट एक साल पहले ही बंद कर दिए गए है.

इस तालाब के सौंदर्यीकरण किए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता चौबे का कहना है कि केवल गांधीसागर तालाब का सौंदर्यीकरण किए जाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना होगा. इसके पानी को साफ़ करके इस पर दिन में बोटिंग और रात में रंगीन, म्यूजिकल फव्वारा, लाइट शो शुरू किया जा सकता है जैसा कि हैदराबाद के विख्यात उस्मान तालाब में किया गया है. लाइट शो में नागपुर के इतिहास की झलकियां दिखाई जा सकती हैं जिस पर अभी तक किसी ने ग़ौर नहीं किया है. शुक्रवारी तालाब को किसने बनवाया, कब बनवाया यह नागपुर के लोगों को ही पता नहीं है. कोई शिलालेख उपलब्ध नहीं है. यदि मनपा प्रशासन शुक्रवारी तालाब को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करती है तो जो लोग यहां आएंगे, उन्हें उपराजधानी के इतिहास की जानकारी भी मिलेगी और मनपा को आय भी होगी, यानी दोहरा लाभ होगा. बड़े अफ़सोस की बात यह है कि जिस चांद सुलतान ने नागपुर को बसाया, राजधानी बनाई, उसका कहीं ज़िक्र नहीं किया जाता है. पुरातत्व विभाग की सूची में नागपुर का एक भी स्थल शामिल नहीं है जबकि खुद शुक्रवारी तालाब एक ऐतिहासिक स्थल है. सबसे पुराना तालाब है बाकी के तालाब उसके बाद के हैं. नागपुर में ही बख्त बुलंद शाह सहित अनेक राजा-रानियों की समाधियों सहित कई ऐतिहासिक स्थल हैं, पर उपेक्षित हैं. जहां तक तालाब के पानी को स्वच्छ करने की बात है तो अंबाझरी तालाब से 13 इंच की पाइप लाइन कॉटन मार्केट के सुभाष रोड तक पड़ी है, जो बंद है. उसे गांधी सागर तालाब तक लाया जा सकता है, जिससे पानी को साफ़ रखा जा सकता है. अब यह मनपा प्रशासन पर निर्भर करता है कि उसे गांधी सागर तालाब को मात्र सौंदर्यीकरण करना या उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है. इतना अवश्य है कि यहां पर ऐसी व्यवस्था मनपा प्रशासन व पुलिस विभाग को मिलकर करनी होगी कि आत्महत्याएं न हों. भविष्य में यह आत्महत्याओं के लिए कुख्यात नहीं, बल्कि अपनी ख़ूबसूरती व अन्य विशेषताओं के लिए सुविख्यात हो.

नागपुर का इतिहास शुक्रवारी तालाब के बिना अधूरा ही रह जाता है. राजा बख्तबुलंद शाह के पुत्र चांद सुलतान ने बारह गांवों को मिलाकर नागपुर शहर बसाया था और इसे अपनी रियासत की राजधानी बनाया था. इस संबंध में उमेश चौबे बताते हैं कि चांद सुलतान ने 1702 में नागपुर को जब राजधानी बनाया तभी उसने इस शहर का ढांचा भी बनाया. सड़कों के साथ ही एक बांध बनाया. यह एक तरह से गणेश टेकड़ी की तराई थी. बांध सुभाष रोड के पास था और आज का शुक्रवारी तालाब मेडिकल के आगे तिलक पुतला तक फैला था. भोसले जब यहां के शासक बने तो वे नाव में बैठ कर गणेश टेकड़ी अपनी संगीत मंडली के साथ दर्शन के लिए जाया करते थे. उस समय इस तालाब के कारण पूरे नागपुर के कुओं का पानी सामान्य स्तर से ऊपर रहता था.

feedback@chauthiduniya.com

शुक्रवारी नाम कैसे पड़ा

भोसले राजाओं की सेना में बड़ी तादाद में मुस्लिम सैनिक थे. शुक्रवार के दिन सैनिक नमाज़ से पहले यहां वुज़ू करते थे, इसलिए इसका नाम जुम्मा तालाब पड़ गया. धीरे-धीरे लोग इसे शुक्रवारी तालाब कहने लगे.

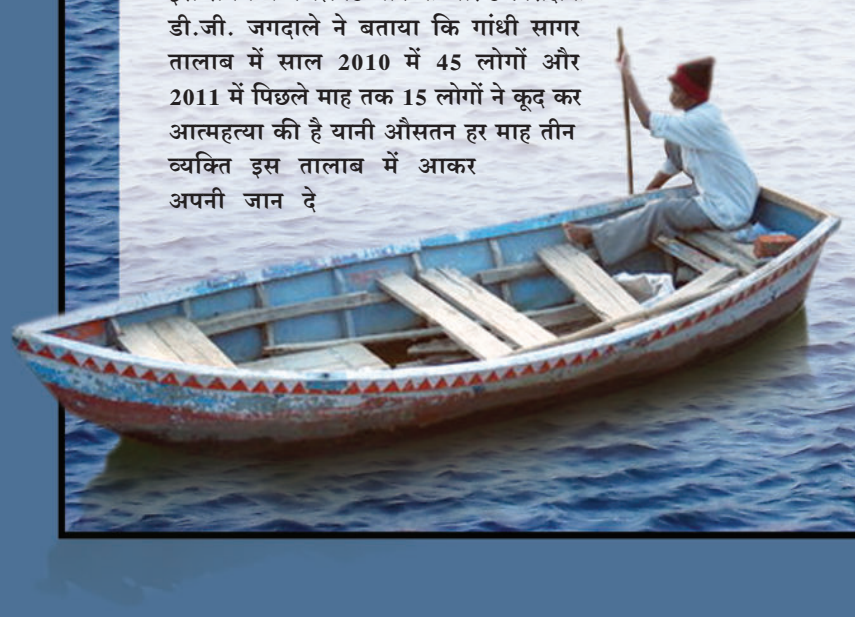

चौथी दुनिया
बिहार झारखंड

पूर्णिया उपचुनाव

दम और दिमाग़ की अग्निपरीक्षा

यह उपचुनाव नीतीश व मोदी की जोड़ी से कहीं ज़्यादा विपक्ष के भविष्य की लकीरें खींचेगा. हार -जीत, दोनों ही हालात में विपक्ष को एक ऐसा संदेश मिलेगा, जिसके बलबूते अगर वह चाहे तो आगे की रणनीति बना सकता है और नीतीश कुमार के सामने एक मज़बूत चुनौती रख सकता है. विधानसभा चुनाव के बाद छह माह शायद विपक्षी दलों ने महसूस किया कि उनके अलग-अलग रास्तों ने नीतीश कुमार व सुशील मोदी का रास्ता आसान कर दिया है.

सरोज सिंह

पच्चीस जून को पूर्णिया विधानसभा सीट के लिए होने वाला उपचुनाव बिहार की भावी राजनीति की दिशा तय कर देगी. राजकिशोर केसरी की हत्या के कारण हो रहा यह उपचुनाव एनडीए व यूपीए दोनों के लिए ही लिटमस टेस्ट की तरह है. यहां की जनता तय कर देगी कि नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ आगे विपक्ष की रणनीति क्या हो. उपचुनाव के नतीजों से यह भी तय होगा कि बिहार के लोग नीतीश कुमार के छह माह के कार्यकाल पर क्या राय रखते हैं. साफ़ कहें तो यह उपचुनाव नीतीश व मोदी की जोड़ी से कहीं ज्यादा विपक्ष के भविष्य की लकीरें खींचेगा. हार व जीत दोनों ही हालात में विपक्ष को एक ऐसा संदेश मिलेगा, जिसके बलबूते अगर वह चाहे तो आगे की रणनीति बना सकता है और नीतीश कुमार के सामने एक मज़बूत चुनौती रख सकता है. विधानसभा चुनाव के बाद छह माह के आत्ममंथन के दौर में शायद विपक्षी दलों ने महसूस किया कि उनके अलग-अलग रास्तों ने नीतीश कुमार व सुशील मोदी का रास्ता आसान कर दिया है. यही वजह है कि इस बार राजद व लोजपा ने तय किया है कि वह किसी भी हालत में पूर्णिया विधानसभा उपचुनाव में धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा नहीं होने देंगे. कई दौर की बातचीत के बाद दोनों दलों के नेताओं ने यहां अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करने का फैसला किया.

पूर्णिया में राजनीतिक सरगर्मी तेज़ है और चुनावी तपिश का पारा सातवें आसमान पर है. भाजपा ने अनंत भारती, तारा साह, विजय खेमका, कैलाश लाहौटी जैसे भाजपाई को दरकिनार करते हुए स्वर्गीय राजकिशोर केसरी की विधवा किरण केसरी को टिकट दिया है. कांग्रेस ने रामचरित्र यादव व सीपीएम ने अमित सरकार को मैदान में उतारा है. पूर्णिया विधान सभा में कुल मतादाताओं की संख्या लगभग 2 लाख 25 हज़ार के आस पास है, जिसमें बनियां 55 हजार, यादव 20 हजार, मुस्लिम 40 हजार, राजपूत 25 हजार, अतिपिछड़ा 45 हजार, बंगाली 17 हजार, दलित 40 हजार, आदिवासी 15 हजार, ब्राह्मण 18 हजार एवं अन्य जातियां शामिल हैं. अगर 2010 के चुनाव परिणाम का आकलन किया जाय तो भाजपा के विजय प्रत्याशी स्वर्गीय राजकिशोर केसरी को कुल 54605 वोट मिले थे, निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं पराजित कांग्रेस के रामचरित्र यादव को 39006, सीपीएम के अमित सरकार को 23061, रांकपा के सैयद गुलाम हुसैन को 3555 वोट मिले थे जबकि लोजपा प्रत्याशी समेत अन्य की जमानत जब्त हो गई थी. इस प्रकार से 15599 मतों से भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई थी.

भाजपा हर हाल में पूर्णिया में अपने जीत के सिलसिले को बनाए रखना चाहती है. यही वजह है कि उसने इस उपचुनाव को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए अपनी पूरी ताक़त झोंक दी है. उसे सहानुभूति वोटों की भी उम्मीद है. विपक्ष के साझा उम्मीदवार न होने से भी किरण केसरी की ताक़त बढ़ी है. बाबा रामदेव प्रकरण का भी फ़ायदा भाजपा उठाने में लगी है. पटना में बैठे एनडीए आकाओं का गणित यह है कि उपचुनाव में भारी जीत दर्ज कर विपक्ष के पस्त हौसले को और भी पस्त कर दिया जाए ताकि आगे आक्रामक राजनीति करने के लिए उसे कोई जगह न मिल सके. इस जीत से एनडीए अपने बागी नेताओं को भी यह संदेश देना चाहती है कि नीतीश व मोदी के साथ में ही भलाई है.

लेकिन राजद व लोजपा का पूरा प्रयास है कि उपचुनाव में विपक्ष के वोटों का बंटवारा न हो. भरोसेमंद सूत्रों पर भरोसा करें तो राजद व लोजपा ने अपने विकल्प खुले रखे हैं. मतदान के अंतिम तीन चार दिनों में हवा के रुख़ पर ही इनका फ़ैसला होगा. रामचरित्र यादव व अमित सरकार में जो भारी दिखेगा उनका फ़ैसला उसी के पक्ष में जाएगा. राजद व लोजपा अपने इसी मास्टर स्ट्रोक से भाजपा को यहां मात देना चाहते हैं. नगर निगम पंचायत प्रकरण पर पूर्णिया सांसद उदय सिंह उर्फ़ पप्पू सिंह उच्चतम न्यायालय से न्याय दिलाने की बात कहकर मतदाताओं को भाजपा की ओर लाने में लगे हैं. दूसरी तरफ पप्पू यादव व रंजीता रंजन के लिए भी यह चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है. पप्पू यादव यहां अपने पुराने जनाधार को साबित करने के लिए गोटी बैठा रहे हैं.

पूर्णिया विधानसभा के मतदाता राजेंद्र ऋषि, मानिक उरांव, प्रदीप महतो, नुनिया देवी, बागो देवी, फसिया देवी आदि का कहना है कि कांग्रेस बड़ा भ्रष्ट सरकार छैय, पेट्रोलों के दाम बढ़ले, डीजल, गैस सब के दाम बढ़ेले जाय छैय. खाय के सामान बहुत मंहगा भय गेले. रामदेव बाबा जेय काला धन के चर्चा करे छय अगर उ धन देश में वापस आ जयेते त हमरा सब के कल्याण होय जेते, हमे सब भुखे नय मरबै और हमरो मकान पक्का के बनी जयते और हमरो सभी के ग़रीबी भागी जयते. जबकि मो. ईसराइल व अरविन्द यादव ने कांग्रेस को बेहतर बताकर समर्थन करने की बात कही. इनका कहना था कि नीतीश सरकार में अफसरसाही व लूट खसोट चरम पर है. हाल ही में रामचरित्र यादव ने पांचों पंचायत को नगर निगम में शामिल करने के मुद्दे पर आवाज जोर-शोर से बुलन्द की थी. इसको लेकर पंचायत के मतदाताओं में उनके प्रति कुछ सहानभुति बन सकती है. रामचरित्र यादव के कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में आने से यहां का मुकाबला रोचक हो गया है क्योंकि पप्पू यादव का खासा प्रभाव इस क्षेत्र में रहा है और अल्पसंख्यकों में उनकी काफी पकड़ है. बंगाल व केरल में शिकस्त खाने के बाद वामदलों को भी लग रहा है कि अगर अमित सरकार के हाथ बाजी लग गई तो यह संजीवीनी का काम करेगी. इसलिए अमित सरकार के साथ साथ उनकी पार्टी भी हर दरवाजे पर जा रही है. लेकिन माले व झामुमो ने यहां अपना प्रत्याशी देकर अमित सरकार को परेशानी में डाल दिया. राजद व लोजपा का विकल्प खुला होने के कारण रामचिरत्र व अमित में आगे निकलने की होड़ मची है. देखना है पूर्णिया का यह उपचुनाव कौन सा इतिहास रचता है.

feedback@chauthiduniya.com

छोटे उस्ताद भी कम नहीं

नीरज सिंह

पूर्णिया उपचुनाव में बड़े महारथी तो गरज ही रहे हैं पर सभी दलों के दूसरी लाइन के नेताओं ने भी अपने दावों व जोड़तोड़ से इस चुनावी मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है.लोजपा के प्रधान महासचिव राघवेंद्र कुशवाहा अपने हाईटेक तीरों से भाजपा को घायल करने में लगे हैं. कुशवाहा कहते हैं कि मक़सद भाजपा को हराना है और हमलोग इसमें सफल हो रहे हैं. विपक्ष ने ऐसी घेरेबंदी कर दी है कि इससे भाजपा का निकलना असंभव है. युवा लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार का दावा है कि पूर्णिया उपचुनाव नीतीश सरकार के पतन की शुरुआत है और चुनावी नतीजे यह साबित कर देंगे कि सूबे की जनता इस सरकार को बदलना चाहती है. दूसरी तरफ युवा कांग्रेस अध्यक्ष ललन यादव कहते हैं कि उपचुनाव में यह बात साफ़ हो गई कि बिहार की जनता इस शासन से उकता चुकी है. इसका प्रमाण यह है कि हर जगह कांग्रेस प्रत्याशी को भारी समर्थन मिल रहा है. सोनिया गांधी व राहुल गांधी ने बिहार के लिए जो सपना देखा है, उसे हर कांग्रेसी यहां पूरा करने में जुट गया है. रामचरित्र यादव यहां भारी मतों से जीत रहे हैं. दूसरी तरफ भाजपा नेता वरुण सिंह कहते हैं कि किरण केसरी रिकॉर्ड मतों से यह चुनाव जीत रही हैं. उनका दावा है कि मुक़ाबले में खड़े प्रत्याशी अपनी जमानत ही बचा लें तो बड़ी बात होगी. इसी तरह भाजपा नेता अनंत भारती भी मानते हैं कि यहां किरण केसरी आसानी से जीत दर्ज कर रही है. पूर्णिया के लोग भाजपा के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे.

अनंत भारती

वरुण सिंह

ललन यादव

राघवेंद्र कुशवाहा

रोहित कुमार

feedback@chauthiduniya.com

ज़िला परिषद अध्यक्ष के अलावा प्रखंडों में भी प्रमुख पद के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज़ हो गई है. ज़िले के राजनीतिक दिग्गज, जो पंचायत चुनाव में स्वयं को या अपने परिजनों को जीत दिला पाने में असफल रहे हैं.

घटना की गंभीरता को लेकर एसपी विभिन्न थाना पुलिस के साथ पहुंची तो ग्रामीणों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें एसपी को भी चोटें आईं.

बोर्ड गठन पर राजनीतिक खिचड़ी पकने लगी

विकास कुमार

[illegible]

अनुपम कुमार

पुष्पलता देवी

राम किशोर राय

[illegible] हैं. चुनकर आए सभी नए सदस्य अपने-अपने हिसाब से समीकरण बनाने में जुटे हैं. शिवनाथ राम, रामप्रकाश महतो, बैजू राय समेत एक महिला का नाम प्रमुख पद के लिए सामने आया है. वारिसनगर प्रखंड में प्रमुख की कुर्सी अनुसूचित [illegible] सौंप दी है. ज़िले के बिथान प्रखंड के बेलसंडी पंचायत से हसनपुर के जदयू विधायक राजकुमार राय की पत्नी निवर्तमान मुखिया पुष्पलता देवी को मतदाताओं ने फिर से सर आंखों पर बिठाया है.

feedback@chauthiduniya.com

श्रद्धांजलि
दिग्विजय सिंह (1955-2010)

फोटो-प्रभात पाण्डेय

देश और अपने राज्य बिहार का दुनिया भर में सम्मान दर्ज कराने में दिग्विजय सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है. बिहार के जमुई ज़िले के गिद्धौर गांव में 14 नवंबर 1955 को दिग्विजय सिंह पैदा हुए थे. राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी उनकी ख़ास रुचि थी. वह 1999 से भारतीय शूटिंग संघ के अध्यक्ष थे और कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों को लेकर वे लंदन गए थे, जहां उनका निधन हो गया. दादा को उनकी पहली पुण्य तिथि पर चौथी दुनिया की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि.

लोकतंत्र के प्रहरी थे दादा

हमारे प्रिय नेता स्व. दिग्विजय सिंह, जिन्हें हमलोग प्यार से दादा कहा करते थे, उनकी पुण्य तिथि 24 जून को है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं, क्योंकि जिन विचारधाराओं, मूल्यों एवं आदर्शों को लेकर उन्होंने संघर्ष शुरू किया था वे आज भी सुरसा की तरह मुंह बाये खड़े हैं. दिग्विजय बाबू एक कर्मठ, सरल स्वभाव एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे. उन्होंने बिहार की राजनीति में एक नये अध्याय की शुरुआत के लिए संघर्ष किया. आज वह जीवित होते तो बिहार की दशा और दिशा अवश्य बदल गई होती, लेकिन अफ़सोस कि काल के क्रूर पंजों ने असमय ही उन्हें हमसे छीन लिया. दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि कल तक जो उनके साथ छाया की तरह लगे रहते थे और अपने को उनका सच्चा अनुयायी बताते थे, आज वही लोग उनकी विचारधारा के विपरीत काम करते नज़र आ रहे हैं. दूसरी तरफ़ आज भी ऐसे लोग हैं जो उनकी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं. ऐसे लोग रुकने वाले नहीं हैं, वह हर हाल में दादा के सपनों को पूरा करेंगे. **- आलोक हर्ष**

मैंने देर से मानी उनकी बात

[illegible] सौम्यता का एक उदाहरण हमसे छिन गया. उनकी कमी आज इसलिए भी सबसे ज़्यादा खलती है कि सही सोच रखने वालों की आज की राजनीति में भारी कमी हो गई है. मेरा उनके साथ प्रगाढ़ मानवीय संबंध था और मेरे दिल में उनके प्रति आज भी बेहद सम्मान है. बिहार व इस देश के लिए उनकी सोच काफ़ी व्यापक थी और वह समग्र विकास के हिमायती थे. समाज व इस देश के प्रति इनके विचार हमें शक्ति प्रदान करते हैं. उन्हें नमन, इन्हें प्रणाम. **- डॉ. अनिल सुलभ**

दलितों के लिए दिल में दर्द था

[illegible] इस काम में हमेशा वह मदद करने को तैयार हैं. आज वह हमलोगों के बीच नहीं हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. सभी लोगों को मिलकर यह सोचना पड़ेगा कि दिग्विजय बाबू ने जिस सोच को गढ़ा इसे मूर्तरूप कैसे दिया जा सकता है. कमज़ोर तबक़े के उत्थान के लिए हमारी पार्टी के विचारों से वह काफ़ी सहमत थे. उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो अधूरे काम वह छोड़ गए हैं इउसे हर हाल में पूरा किया जाए. **- रामचंद्र पासवान**

ग़रीबों के मसीहा थे दिग्विजय बाबू

देश के मौजूदा हालात में दिग्विजय बाबू की कमी मुझे और मेरे जैसी सोच रखने वाले लोगों को काफ़ी खलने लगी है. दादा बराबर कहा करते थे कि ग़रीबों के पेट जब तक भरे नहीं जाएंगे तब तक सही आज़ादी का दावा करना बेमानी होगा. वह कहा करते थे कि विकास व तकनीक का लाभ समाज के सबसे निचले तबक़े के लोगों को सबसे पहले मिलना चाहिए, पर अभी उलटी गंगा बह रही है. ग़रीब और ग़रीब होते जा रहे हैं और अमीर और अमीर होते जा रहे हैं. सड़कों पर ज़ुल्म व भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों की भारी कमी हो गई है. दादा ने हमलोगों को एक रास्ता दिखाया था. उनके रास्ते पर चलकर अगर हमलोग इस समाज का थोड़ा भी भला कर सकें तो यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. दादा हमलोगों के दिलों में बसे हैं और हमेशा बसे रहेंगे. **- रामबिहारी सिंह**

दादा ने जीने का मक़सद दिया

मुझे आज भी याद है 19 अप्रैल 2010 की सहरसा नगरपालिका मैदान में हज़ारों की भीड़ दिग्विजय सिंह के इंतज़ार में खड़ी थी. मुरलीगंज से सहरसा की लगभग 50 किमी. की दूरी तय करने में दादा को तक़रीबन ढाई घंटे लगे. मैं भी दादा के साथ था और उनकी लोकप्रियता से अभिभूत था. सड़क के किनारे पड़ने वाले हरेक चौक - चौराहों पर जनता दादा की एक झलक पाना चाहती थी, मिलना चाहती थी. सभा स्थल से मुझे बार-बार फोन आ रहा था जल्दी आइए, भीड़ बेक़ाबू हो रही है. जनता उनमें अपना भविष्य देख रही थी. सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के निकम्मेपन के कारण 2008 में कोसी बांध टूट गया. सरकार तबाह किसानों के नाम पर समाज को बांट रही है. उद्योग- धंधों के नाम पर बिहार सरकार की उपलब्धि शून्य है. स्थानीय परिसदन में 20 मई की सुबह चाय की चुस्कियों के साथ बिताए वे क्षण आज भी मेरी प्रेरणा हैं. चेहरे पर 19 मई की सभा की सफलता की मुस्कराहट के साथ आमजन की पीड़ा पर चर्चा में मशग़ूल रहते हुए वे तीन प्याली चाय पी गए. कोसी में कल-कारख़ानाओं की संभावनाएं और स्थानीय किसानों की समस्याओं पर गहन चर्चा हुई. दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने छात्र जीवन के दौरान वर्ष 1994 में संपर्क में आने के बाद की दर्जनों मुलाक़ातों में हमेशा बिहार और देश की समस्याओं पर चर्चा करते थे. ऐसा प्रतीत होता है कि वे सिर्फ़ जनसरोकार के लिए बने थे.

जाते-जाते वो मुझे इतनी सज़ाएं दे गया,
उम्र भर दोहराऊंगा इतनी कहानियां दे गया

- अजय कुमार

हर क़दम पर दादा की नज़र

पिछले साल भर से दादा को देख रहा हूं, सुन रहा हूं. साल भर पहले तो हमारी ग़लतियों को हंसकर टाल देते थे, पर अब ऐसा नहीं है. दादा की नज़र हमारे हर एक क़दम पर है. अब वह हमारी ग़लतियों को हंसकर टालने की बजाय उसे न करने की हिदायत देते हैं. दादा अहसास दिलाते हैं कि मेरे चले जाने के बाद तुम लोगों पर काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी है. इसलिए अब ग़लतियों की गुंजाइश न छोड़ो. शायद दादा की यही ख़ासियत उन्हें अन्य नेताओं से अलग करती है. दादा अपने चाहने वालों के लिए अपना सबकुछ देने को हमेशा तैयार रहते थे. बिहार व इस देश के लिए दादा के मन में कई सपने थे. दादा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्हें चाहने वाले सभी लोग मिलजुल कर उनके सपनों को साकार करें. दादा को शत्-शत् नमन. **-किशोर कुमार, मुन्ना**

दादा के सपनों को पूरा करेंगे

श्री अन्ना हज़ारे एवं स्वामी रामदेव के आह्वान पर देश में भ्रष्टाचार के विराध में तथा लोकतंत्र के समर्थन में चलाए जा रहे अभियान को जिस तरह पूरे देश में आम जनता का समर्थन मिल रहा है, उनसे दो बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो गई हैं. पहला यह कि पूरा देश सार्वजनिक जीवन एवं शासनतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से त्रस्त एवं तबाह होकर आक्रोशित है. दूसरा यह कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रमुख राजनीतिक दल सिर्फ़ इसलिए अप्रासंगिक हो गए हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में उनकी कथनी एवं करनी में प्रत्यक्षत: अंतर है. उपर्युक्त संदर्भ में आज लोकतंत्र के प्रहरी प्रखर राजनेता स्व. दिग्विजय सिंह की याद आती है. उन्होंने देश में स्वच्छ राजनीति एवं ईमानदार सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अगस्त 2009 में मुंबई में राष्ट्रीय सम्मेलन किया. विचारोपरांत लोकमोर्चा का गठन करके भ्रष्टाचार एवं लोकतंत्र के मुद्दों पर पूरे देश में जनजागरण अभियन चलाने का संकल्प लिया गया था. दुर्भाग्यवश जून 2010 में दिग्विजय सिंह का आकस्मिक निधन हो गया. फलस्वरूप आज इन मुद्दों से जुड़ा अभियान ग़ैर राजनीतिक संगठनों के हाथों में चला गया. आज लोकतंत्र के प्रहरी प्रखर राजनेता स्व. दिग्विजय सिंह की पुण्य तिथि के अवसर पर हमलोग पुन: संकल्प लेते हैं कि उनके द्वारा अगस्त 2009 के मुंबई सम्मेलन में घोषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेंगे. यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. **-पी के सिन्हा**

मिथिला

रेल परियोजनाओं पर ग्रहण

मनोज ठाकुर

रेलवे परियोजना का हश्र प्रमंडल में बहुत बुरा है. प्रमंडल के ज़िले सहरसा, मधेपुरा, सुपौल के दुरूह ग्रामीण इलाक़े तक लोगों को आने-जाने में होने वाली कठिनाई इस इलाक़े को दुरूह बनाती है. आते-जाते रेल यात्री परेशान ही नहीं हो रहे, बल्कि ख़ुद को प्रताड़ित भी महसूस करते हैं.

प्रमंडल का सड़क संपर्क राजधानी व अन्य महानगरों से डुमरी पुल के टूटने के कारण कई माह से बाधित है. हवाई मार्ग की न तो यहां सुविधा है और न ही यहां के लोग इसे लेने में सक्षम. जल मार्ग भी उपलब्ध नहीं है. अब बचता है रेल मार्ग. रेलमार्ग भी मात्र सहरसा-मानसी से होकर आता-जाता है अर्थात वन वे. और रेल परियोजनाओं की स्थिति को देख ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले कुछ वर्षों तक यहां के लोग ऐसे ही दुरूह रास्ते से गुज़रने को मजबूर रहेंगे. अब बताते हैं कि विभिन्न रेल परियोजनाओं का हाल. पिछले 15 वर्षों से आजतक स्वीकृत हुईं रेल योजनाएं रेलमंत्री के बदलने से कैसे प्रभावित होती रहीं और इन योजनाओं में से तो कुछ कभी बंद तो कभी खुली स्थिति में रही. वर्ष 1996 में तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान द्वारा रेल-बजट में शामिल सहरसा-मधेपुरा-पूर्णियां रेलखंड की स्थिति. कुल 85 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का आमान-परिवर्तन कार्य संपन्न होने की तय समय-सीमा थी वर्ष 2005, लेकिन आज तक यह 18 किलोमीटर की दूरी तय कर मधेपुरा तक ही पहुंच पाया है. शेष 67 किलोमीटर की दूरी कब ख़त्म होगी, यह प्रश्न यहां के लोगों को सालता रहता है. बता दें कि तय समय-सीमा को गुज़रे 6 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मधेपुरा से पूर्णियां तक बड़ी रेल-लाइन आमान परिवर्तन होने के बजाए इसके एक हिस्से मधेपुरा-मुरलीगंज आमान परिवर्तन कार्य ही शुरू हो पाया है, वह भी तब जब समस्तीपुर मंडल के डीआरएम सत्य प्रकाश त्रिवेदी द्वारा डिवीजनों को दी जाने वाली राशि से इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए. यह योजना भी वर्ष 2010 में शुरू हुई थी जो आज भी निर्माणाधीन है. रेल निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अरुण कुमार कहते हैं कि मार्च 2012 को मधेपुरा से बनमनखी के बीच आमान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया है, जो समय पर पूरा कर लिया जाएगा. अब उनकी कथनी और करनी में कितनी समानता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

दूसरी योजना 1996 के ही रेल बजट में रेल मंत्री रामविलास पासवान ने स्वीकृति प्रदान की, जो 111 किलोमीटर दूरी की सहरसा-फारबिसगंज आमान परिवर्तन योजना है. यह योजना भी काफ़ी मंथर गति से पिछले वर्ष के शुरुआती महीने से चल रही है. इस योजना का लक्ष्य 2012 को रखा गया. मगर सहायक अभियंता श्री कुमार के अनुसार मार्च 2012 में मेगा ब्लॉक करने की ही संभावना है. और 2013 तक योजना को पूरा कर लिए जाने की संभावना है. मतलब इस योजना में भी लेट-लतीफ़ी. 355. 81 करोड़ की योजना की सुस्त रफ्तार से कतिपय यह नहीं लगता है कि श्री कुमार द्वारा बताए गए समय में भी यह पूरी हो पाएगी. तीसरी योजना कोसी नदी पर रेल महासेतु का निर्माण है जो निर्मली सरायगढ़ में बन रही है. 341.41 करोड़ की महत्वपूर्ण इस परियोजना का निर्माण कार्य गैमन इंडिया कंपनी व तांतिया कन्स्ट्रक्शन मिलकर कर रही है. यह योजना भी अपने निर्धारित समय में लगता नहीं है कि पूर्ण होगी. चौथी योजना वर्ष 2008 में तात्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा पारित 1960 करोड़ की लागत से मधेपुरा में बनने वाली विद्युत रेल इंजन कारख़ाना ममता बनर्जी के शासन काल में कभी बंद तो कभी चालू होने की विवादों से चल रही है. पांचवी योजना 15 वर्ष पूर्व सहरसा के बंगाली बाज़ार में प्रस्तावित ओभरब्रिज का निर्माण कार्य आजतक शुरू नहीं करवाया गया. छठी योजना है पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा पूर्णिया ज़िला अंतर्गत रूपौली में बिहारीगंज-कुरसैला भाया बनमनखी नई रेल-लाइन का शिलान्यास, परंतु यह योजना भी ममता के कार्यकाल में ठंडे-बस्ते में चली गई. इस रेलखंड में स्थापित स्टेशन अब हाल्ट बन कर रह गया है, जबकि ब्रिटिश काल में राजस्व प्राप्ति की असीम संभावनाओं को देखते हुए यह रेल मार्ग बनाया गया था. अब इस मीटर गेज रेलखंड पर ऊंट की सवारी जैसी यात्रा करने को रेल यात्री विवश हैं.

सातवीं परियोजना है 5 करोड़ की लागत से सहरसा रेलवे स्टेशन से सटे दक्षिण में बनने वाला वांशिग पीट, जो पिछले तीन वर्षों से निर्माणाधीन है. इसके लिए निर्माण नहीं होने के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का सहरसा से परिचालन शुरू नहीं हो पाया है. सबसे ज़्यादा परेशानी यहां के यात्रियों को वाशिंग पीट के निर्माणाधीन रहने के कारण ट्रेनों की सफ़ाई-धुलाई को लेकर होता है. लंबी दूरी की पूरबिया एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन वाशिंग पीट नहीं रहने के कारण बरौनी सफ़ाई व धुलाई को जाकर सहरसा वापस लौटने में घंटो लेट हो जाती है जिसका ख़ामियाज़ा यात्री भुगतते हैं. ऐसे में यात्रियों की फ़ज़ीहत होकर रह जाती है. बता दें कि इसके निर्माण का लक्ष्य पहले मार्च, 2009 था जो बढ़कर दिसंबर 2009 और मार्च, 2010 पर पहुंची. हालांकि अब शीघ्र पूरा कर लेने का लक्ष्य मंडल अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं. रेलवे परियोजना की सुस्ती को देख आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब परियोजनाओं के प्रति रेल मंत्री व उनके अधिकारी इतने असहज हैं तो रेलवे स्टेशनों की स्थिति कैसी होगी? स्टेशनों में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा को बताना शायद अब ज़रूरी नहीं रह जाता. अब अगर बनने वाले नए रेल मंत्री द्वारा अधर और मंथर गति से जारी रेल परियोजनाओं को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया गया तो कोशी क्षेत्र में विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और पड़ोसी देश नेपाल से सीधे व्यापारिक संपर्क की उम्मीदें सपने बनकर रह जाएंगी और आमलोग रेलवे के चक्के के नीचे ऐसे ही पिसते रहेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

वैशाली ज़िला परिषद

चुनावी खेल मुन्ना व सतीश तय करेंगे

आरती देवी | नजिया नाज़ | पूनम | संतोष कुमार निराला
उपेंद्र कुमार राय | शत्रुघ्न गुप्ता | जय प्रकाश चौधरी | धीरेंद्र कुमार

इकतालीस सदस्यीय वैशाली ज़िला परिषद में अब ज़िला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव की गहमागहमी है. स्थानीय बड़े नेता नवनिर्वाचित ज़िला पार्षदों पर अपने प्रभाव दिखाने में व्यस्त हैं. पार्टी के समारोहों से लेकर पंचायत स्तर तक के कार्यक्रमों में जिनकी भूमिका रही, उन्हीं के सिर जिपा का सेहरा बंधा. वैशाली जिप अध्यक्ष का पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए आरक्षित है, जबकि पिछली बार की तरह जिप उपाध्यक्ष का पद सामान्य महिला के लिए है. पिछली बार ज़िला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर रहीं क्रमश: कलबा देवी और नीलम देवी इस बार मैदान ही में नहीं थी. कलबा देवी के पुत्र जयप्रकाश चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, जबकि नीलम देवी के पति एवं पूर्व जिप अध्यक्ष उमेश राय स्वाधीनता सेनानी अक्षयवट राय की पौत्रवधू अनीता देवी के पक्ष में मैदान से अलग थी.

अनीता देवी हार गयीं, तो एक कांग्रेस परिवार के मिटते हुए राजनीतिक अस्तित्व को और भी आघात लगा. इस बार जयप्रकाश चौधरी स्वयं जिप अध्यक्ष की कुर्सी के दावेदार हैं. पिछले सत्र में भले ही उनकी मां जिप अध्यक्ष थीं, पर जयप्रकाश अपनी मां की ख़ाली पड़ी कुर्सी के बग़ल में एक सामान्य कुर्सी पर तौलिया बिछाकर पूरे पांच साल क़ाबिज़ रहे. जयप्रकाश स्वयं लालगंज नगरपालिका के अध्यक्ष रहे, परंतु अपनी मिल्कियत के साथ माता के राजनीतिक ओहदे से जुड़े निर्णय भी वही करते रहे. जयप्रकाश लालगंज की राजनीति में ख़ास रहे जगन्नाथ चौधरी के पुत्र हैं. जगन्नाथ की हत्या कोई डेढ़ दशक पहले गोली मारकर कर दी गई थी.

आरंभ में जयप्रकाश के विरुद्ध अध्यक्ष पद की दावेदारी में अनीता चौधरी का नाम आ रहा था, पर समीकरण ऐसा उलटा कि अब जयप्रकाश का पलड़ा भारी दिखता है. पिछली बार उनकी मां के विरुद्ध अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोंकने वाले अनिल कुमार और कुमारी बबिता में से किसी की सीट न बच सकी, पर अनिल की सीट से जीते संजय भगत और बबिता की सीट से जीतीं अनीता चौधरी के नाम उछले थे. संजय विधायक नित्यानंद राय के निकटस्थ रहे हैं और शुरू में संजय ने उन्हें ही अपने राजनीतिक भविष्य का तारणहार बनाया था, परंतु इधर के दिनों में नित्यानंद राय को भी जयप्रकाश के पक्ष में हवा बनाते हुए देखा जा रहा है.

ज़िले की राजनीति में ख़ास कहे जानेवाले राजद के विधान पार्षद उदयनारायण राय उर्फ़ भोला राय के गृह प्रखंड राघोपुर से जीतकर आईं आरती देवी, पूर्णिमा कुमारी और चांदनी देवी का झुकाव भी जयप्रकाश की ओर ही दिख रहा है. आरती देवी 2001 में चांदपुरा की मुखिया बनी थी और 2006 में जिपा चुनी गई थी. उनके पति इंद्रदेव राय राजद के राघोपुर प्रखंड अध्यक्ष हैं और लालू प्रसाद से उनकी निकटता रही है. अर्जुन राय की पुत्रवधु पूर्णिमा को अपने समर्थन से भोला राय ने खड़ा करवाया. पिछली दोनों ज़िला परिषदों में भोला राय के पुत्र और पुत्रवधु को ही जिपा बनने का मौक़ा मिला था, इस बार उन्होंने अपने परिवार से किसी को उम्मीदवार नहीं बनवाया था. वीरपुर के पूर्व मुखिया और रामविलास पासवान के ख़ास रहे जनक राय की पुत्रवधु चांदना के सिर दूसरी बार जिपा का ताज बंधा है. पूर्व मंत्री मुंशीलाल राय की पुत्रवधु एकता पिछली बार महनार से जिपा थीं. इस बार एकता के बदले पूर्व प्रखंड प्रमुख रूपा देवी को मुंशीलाल ने जिपा उम्मीदवार बनाया था. रूपा न जीत सकीं, पिछली बार दूसरे क्रम पर रहीं पूनम देवी जीतीं. वह ठेकेदार विनोद कुमार सिंह की पत्नी हैं. यदि जिप अध्यक्ष जयप्रकाश बनते हैं, तो जिप उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए पूनम देवी और विद्या कुमारी राय के बीच भिड़ंत होगी. विद्या 2001 में जिपा बनी थीं. तत्कालीन जिप अध्यक्ष और विधान पाषर्द जगन्नाथ राय के पुत्र उमेश राय के साथ इनकी बहुचर्चित अदावत यहां तक पहुंच गई थी कि डीएम के साथ एक सभा में उन्होंने उमेश राय पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया था. बाद में विद्या के पति देवेंद्र राय के साथ हुई दुर्घटना के बारे में भी कहा गया था कि उमेश ने ही इन पर जानलेवा हमला करवाया.

पूर्व विधायक बसावन भगत की पत्नी और पूर्व जिप अध्यक्ष ललिता देवी के चुनाव में उतरने की पुन: चर्चा थी, पर बसावन ने अपने ख़ास कहे जाने वाले धनराज पंडित की पत्नी महेश्वरी देवी को जिपा बनवा दिया. अब महेश्वरी के समर्थन की दिशा बसावन ही तय करेंगे. जंदाहा में महनार के विधायक अच्युतानंद का प्रभाव है, तो उपेंद्र सिंह कुशवाहा का भी असर चलेगा, वहां तीन महिला जिपा हैं. सहदेई और महनार मे क्रमश: उपेंद्र राय और प्रदीप राय पर मुंशीलाल राय का असर है, दूसरी ओर सर्वाधिक रिकॉर्ड मतों से जीतीं नजिया नाज़ किसे समर्थन देंगी, यह पूर्व विधायक रामा सिंह तय करेंगे. पटेढ़ी बेलसर और गोरौला में वृष्णि पटेल का चलेगा. विदुपुर में शत्रुघ्न गुप्ता, गायत्री देवी और संतोष निराला जदयू के जिलाध्यक्ष देव कुमार चौरसिया एवं किसान प्रकोष्ठ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार सिंह के कारिंदे हैं. राघोपुर के विधायक सतीश कुमार यद्यपि अन्य ज़िला पार्षदों को जयप्रकाश की ओर आकर्षित करने में भिड़े हैं, पर शत्रुघ्न गुप्ता, संतोष निराला और गायत्री देवी इनकी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इन तीनों ने सतीश के आदेश को शिरोधार्य मान लिया है. लालगंज में मुन्ना शुक्ला का अपना प्रभाव है, तो राजापाकर में जिपा बनी आरती राय पप्पू यादव के ख़ास रहे पूर्व जिपा मंजयलाल की पत्नी हैं, वहीं दूसरी बार लगातार चुनी गई हैं. महुआ में पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष एवं अभी लोजपा के कारिंदे बालेंद्र दास की पत्नी जिपा हुई तो सांसद रामसुंदर दास के खास अखिलेश सिंह की पत्नी भी जिपा हुईं. इस बार की ज़िला परिषद में अति पिछड़े वर्ग की बाहुलता है, तो अधिकांश को जदयू मानसिकता का माना जा रहा है.

पिंकी आलोक
feedback@chauthiduniya.com

बिहार पुलिस का तालिबानी चेहरा

बिहार पुलिस का एक ख़ौफ़नाक चेहरा भी है, जिसका ख़ुलासा फारबिसगंज के भजनपुरा में हुआ. पुलिसिया तांडव में एक अबोध, एक महिला व दो युवक की जान गई. बात यहीं ख़त्म हो जाती तो भी हद थी, पर जब एक निहत्थे घायल युवक के चेहरे पर पुलिस का एक जवान कूदने लगा तो तालिबानों की करतूत याद आने लगी. इन लोगों का क़ुसूर बस इतना था कि वे फारबिसगंज के बियाडा औद्योगिक परिक्षेत्र अवस्थित 110 करोड़ की लागत से ग्लूकोज व स्टार्च उत्पादन के लिए औरो सुंदरम इंटरनेशनल प्रा. लि. के द्वारा निर्माणाधीन कारख़ाने के लिए बन रही चाहरदीवारी का विरोध कर रहे थे. कारख़ाने की चाहरदीवारी से गांव जाने वाली सड़क बंद हो रही है. गांववाले बस रास्ते की मांग कर रहे थे, पर उन्हें बार-बार झूठे आश्वासन दिए गए. जब गांववालों का सब्र का बांध टूटा तो पुलिस ने ऐसा तांडव मचाया कि तालिबान विद्रोहियों के घिनौने चेहरे की याद ताज़ा हो गई. महिला व बच्चों तक को नहीं छोड़ा. औरो कंपनी व भजनपुर के ग्रामीणों के बीच रास्ता विवाद पिछले छह माह से चल रहा था.

विवाद यह है कि बियाडा परिक्षेत्र होकर ही भजनपुर गांव जाने का सुगम मार्ग है. आगे फोर लेन की सड़क है. कंपनी के चाहरदीवारी निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद भजनपुर वासियों का वर्षों पुराना रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा. इस विवाद को विराम लगाने के लिए पहली जून से पहले जब चाहरदीवारी का ग्रामीणों ने विरोध किया था तो कंपनी के मालिक सह विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, निदेशक अशोक कुमार चौधरी के अलावा फारबिसगंज के एसडीओ जीडी सिंह, थाना अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता आदि ने पहुंचकर रास्ता विवाद सुलझा लिउए जाने का दावा भी किया और कहा कि ग्रामीणों को बगल से रास्ता दे दिया गया है और इसका निर्माण भी किया जा रहा है. इस समझौते में भी ग्रामीणों के साथ राजनीति हुई. पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अलावा किसी अन्य पराजित व गांव के पसंदीदा सर्व मान्य लोगों को समझौते के बीच नहीं लाया गया. इस वजह से भी ग्रामीणों के स्वाभिमान पर ठेस पहुंची. कंपनी कुछ लोगों से सांठ-गांठ कर ग्रामीणों के मन के विपरीत समझौता कर लिया. धीरे-धीरे रास्ते का विवाद इतना बढ़ गया कि कंपनी के इस विवादित स्थल पर टेंट व सामियाना लगाकर दंडाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस जवानों का कैंप लगा दिया गया. जब पुन: कंपनी के द्वारा चाहरदीवारी का काम शुरू किया गया तो 3 जून की दोपहर आक्रोशित ग्रामीण लाठी-डंडों के साथ कंपनी में घुसे और ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन में आग लगा दी. जब कंपनी के अंदर तैनात दंडाधिकारी व पुलिस बलों से घटना बेक़ाबू हो गई तो एसपी अररिया गरिमा मल्लिक को भी सूचना गई. घटना की गंभीरता को लेकर एसपी विभिन्न थाना पुलिस के साथ पहुंची तो ग्रामीणों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें एसपी को भी चोटें आईं इसके बाद पुलिस ने अपना तालिबानी चेहरा दिखाया. कहा गया कि पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई पर एक घायल के चेहरे पर कूदने व नाचने को आत्मरक्षार्थ की कार्रवाई कहा जाता है क्या? उधर, पुलिस की गोली से घायल ग्रामीण युवक के सीने पर चढ़कर अमानवीय हरकत करने वाले होमगार्ड के जवान सुनील कुमार यादव के विरुद्ध प्रशिक्षु अवर निरीक्षक प्रशांत कुमार ने फारबिसगंज थाना में भादवि की धारा 302 के तहत कांड सं. 273/11 दिनांक 5 जून को दर्ज करवाया है. इस युवक की भी मौत हो गई, जबकि कंपनी परिसर में तैनात दंडाधिकारी सुनील गुप्ता ने एक हज़ार अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ जबरन औद्योगिक परिसर में घुसकर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने, राइफल व गोली लूटने का प्रयास करने व पथराव करने पर घायल होने संबंधी कांड सं. भादवि की धारा 147, 148, 341, 342, 323, 324, 325, 307, 332, 333, 337, 353, 379, 427, 436, 504, 120 बी व 27 आर्म्स एक्ट के तहत कांड सं. 269/11 दर्ज कराया गया है. फैक्टरी के निदेशक अशोक चौधरी ने कांड सं. 268 दर्ज कराया है और कहा है कि करोड़ों की संपत्ति का नुक़सान हुआ है, जिसका आकलन कर रिपोर्ट दूंगा. बहरहाल घटना के बाद यहां राजनीति भी शुरू हो गई है. नेता आने लगे हैं आंदोलन की बात हो रही है, पर जब तक भजनपुर के लोगों को रास्ता नहीं मिल जाता तब तक विकास का रास्ता निकलना मुश्किल लगता है. इस घटना के विरोध में राजद व लोजपा ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है कि न्यायिक जांच के दायरे मे सुशील मोदी को भी लाया जाए.

नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीक़ी ने आरोप लगाया कि श्री मोदी जब अररिया गए थे तो उन्होंने प्रशासन को जल्द से जल्द ज़मीन पर क़ब्ज़ा दिलाने का निर्देश दिया था.

एस सोनी
feedback@chauthiduniya.com

बिहार पुलिस की हैवानियत

एक घायल युवक के चेहरे पर कूदता बिहार पुलिस का जवान

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
Estd. 2000
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, which is Govt. of India registered, Regd. No. 03-09284 of 2000-2001.
- ISO 9001:2000 certified, Regd. No. CCPL/QMS/C1487
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where Practicals are conducted.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where one full paper of 100 marks on petroleum is taught.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where students of Industrial Safety Management Course of
- Patna University & Magadh University get Practical Training.
FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday
Excellent Placement with Handsome Salary
Website : www.psfsm.com
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph : 0612-6455019, Mob. : 9334107607, 9835042835, 9234729075

Enjoy with Nature MOULDED FURNITURE
1 YEAR WARRANTY शर्तें लागू
आइये आनन्द उठाएँ प्राकृति के संग प्रकृति की गोद में और करें बातें अपनी, अपनों से.....
मजबूती और खूबसूरती का शानदार नमूना बस 'नेचर' की ही हो सकती है जो रखती है आपके लिए खास ख्याल।
NATURE MOULDED FURNITURE
Mfd. By : CENTURY POLYPLAST INDUSTRIES
For trade enquirey Contact 9386595926, 9334115955 or e-mail:centurypolyplast@gmail.com

BALMUKUND SUPER
TMT ही नहीं SUPER TMT
मेरा मकान... सुरक्षित और सॉलिड निर्माण !!
TMT ही नहीं SUPER TMT
EXTRA STRONG-ECONOMICAL-CORROSION RESISTANT-FIRE RESISTANT